20 जुलाई, 2023 * वर्ष 32, पृष्ठ संख्या 60, अंक-7

राजस्थान सुजस

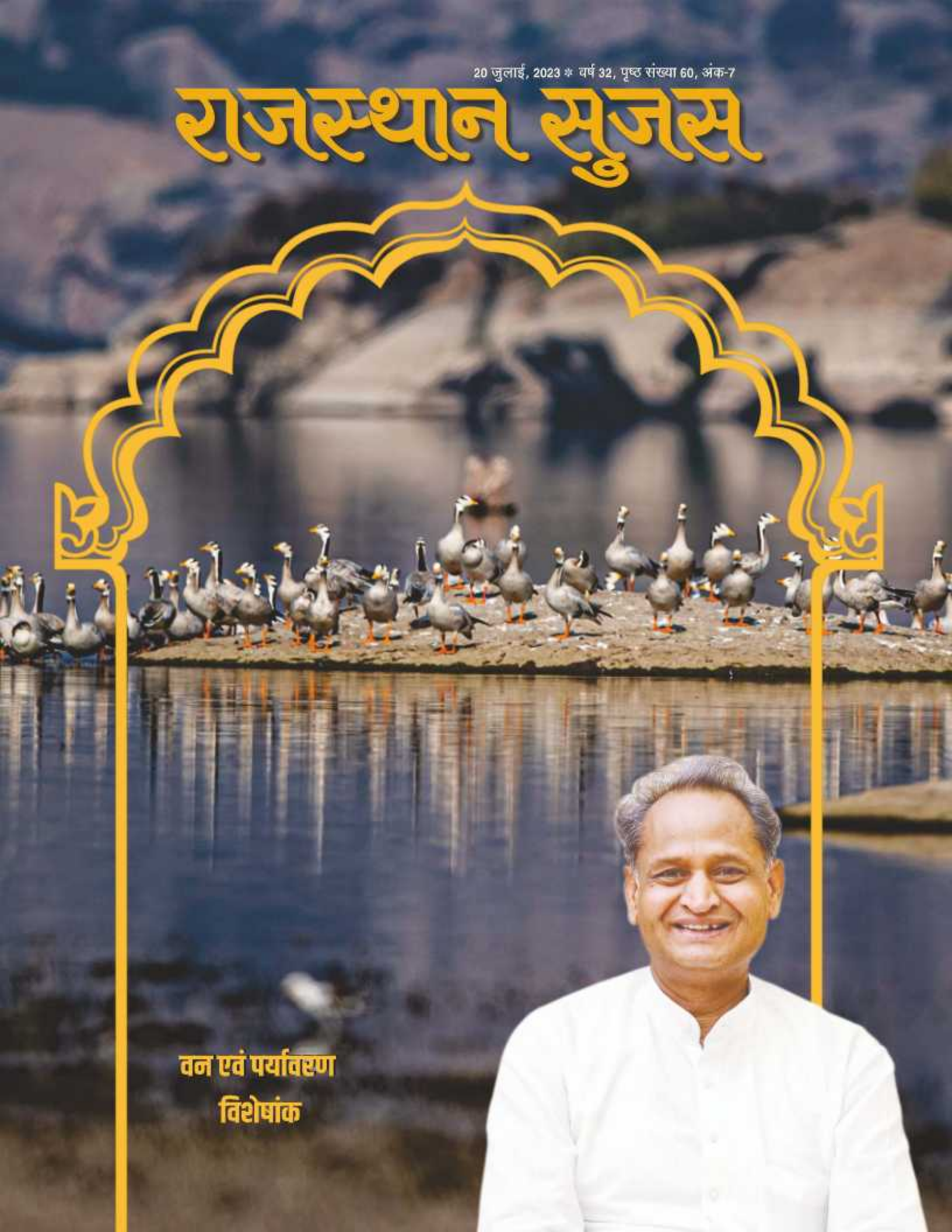

वन एवं पर्यावरण विशेषांक

पर्यावरण के लिए समर्पित

सुदूर ढाणी, खेतों में रहने और प्रकृति से जुड़ाव वाले व्यवहार से बिश्नोई समाज की जीवन शैली ऋषि परंपरा के अनुकूल रही है। समाज में पर्यावरण जागरूकता का विशेष स्थान है। "सिर सांटे रूंख रहे, तो भी सस्तो जाण" समाज का उद्देश्य रहा है। समाज के लोगों ने अनेक बार वृक्षों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है।

आलेख : विनोद जांभदास बिश्नोई
छाया : पीराराम बिश्नोई

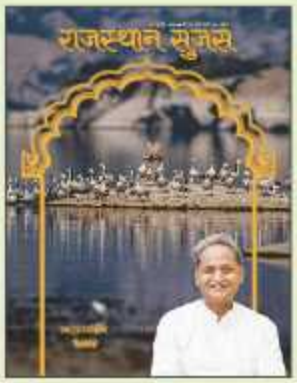

प्रधान संपादक
पुरुषोत्तम शर्मा

संपादक
अलका सक्सेना

सह-संपादक
डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा

उप-संपादक
सम्पत राम चान्दोलिया
आशाराम खटीक

सहायक संपादक
महेश पारीक

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
कृष्णा प्रिंटर्स

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. नं. 98292-71189
94136-24352
e-mail :
editorsujas@gmail.com
publication.dipr@rajasthan.gov.in
Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान का मासिक
वर्ष : 32 अंक 07 | जुलाई 2023

इस अंक में

लोक जीवन	02
संपादकीय	04
उदयपुर के नैसर्गिक सौंदर्य...	14
सरिस्का अभयारण्य	19
रणथंभौर टाइगर रिजर्व	22
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	24
सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य	26
ईको टूरिज्म	28
कुरजां प्रवास	32
Wetlands	35
पर्यटन मानचित्र पर उभर रहा चूरू	36
लव-कुश वाटिका	38
अमृता देवी स्मृति पुरस्कार	42
गौरवमयी गाथा	44
सामयिकी	46
बया	50
सूचना प्रौद्योगिकी	51
पर्यावरण संरक्षण	52
पालनहार योजना	54
लक्ष्मण मंदिर	56
ग्रामीण पर्यटन	58
धरोहर	59
तब और अब	60

राजस्थान में वन के बाहर वृक्ष योजना

05

राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण

07

साक्षात्कार

10

बातचीत

12

फोटो फीचर

30–31

राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें। कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

चंबल रिवर फ्रंट

16

झालाना लेपर्ड सफारी

40

हमारे अनुकूल बना रहे पर्यावरण

अनुकूल वायु, जल और भोजन सामग्री पर्यावरण द्वारा हमें दिए गए सबसे मूल्यवान उपहार हैं। हम सब हमेशा से पर्यावरण के इन संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसके विपरीत इंसानों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं भी पर्यावरण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं और इन क्रियाओं की वजह से पर्यावरण में आने वाले बदलाव हमारे शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं को प्रभावित करते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार हमेशा ऐसे प्रयास करती है जिससे पर्यावरण हमारे अनुकूल बना रहे। राजस्थान देश का रेगिस्तानी और अर्धशुष्क क्षेत्रों का प्रदेश है। हाल में शुरू की गई "राजस्थान में वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष" (TOFR) मुहिम के तहत जनसहयोग से पांच करोड़ पौधे रोपित किए जाएंगे। इससे वृक्षों का आवरण बढ़ेगा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी।

राज्य सरकार बेहतर मानवीय जीवन के साथ बेहतर वन्य जीवन के प्रबंधन के लिए संकल्पित है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पृथ्वी की किडनी के रूप में पहचाने जाने वाले वेटलैंड के संरक्षण और एकीकृत प्रबंधन के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने 19 जिलों में 44 अधिसूचित वेटलैंड की सूची जारी की है। जैसलमेर में गोडावण के कृत्रिम प्रजनन की शुरुआत, खरमोर पक्षी का संरक्षण व उदयपुर पक्षी उद्यान में हरित मुनिया का संरक्षण और प्रजनन दुर्लभ पक्षियों को संरक्षण देने की कड़ी में महत्वपूर्ण कदम हैं।

रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, आमागढ़, माउंट आबू, खेतड़ी, बांसियाल, बीड़ झुंझुनूं, मनसा माता, जयसमंद, कुंभलगढ़ और रावली टाडगढ़ में शुरू की गई जंगल सफारी से देश के कोने-कोने से आने वाले पर्यटक आनंदित होंगे और क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। नई राजस्थान वन नीति, ई-वेस्ट प्रबंधन नीति और ईको टूरिज्म पॉलिसी भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण नीतिगत पहल हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार विभिन्न स्तर पर प्रयास कर रही है। हम सब भी इस दिशा में छोटे-छोटे कदम उठाकर आसान तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं।

आशा करता हूं कि राजस्थान सुजस का जुलाई, 2023 का वन एवं पर्यावरण विशेषांक हम सबको पर्यावरण संरक्षण के प्रति और संवेदनशील बनाने में उपयोगी साबित होगा।

अभिवादन और शुभकामनाओं सहित,

(पुरुषोत्तम शर्मा)
प्रधान संपादक

■ मुनीश कुमार गर्ग
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)

यह सर्वविदित है कि प्रकृति या पर्यावरण का संरक्षण हम सबका आवश्यक दायित्व है। वन क्षेत्र एवं वन क्षेत्र के अतिरिक्त भू-भाग पर पेड़-पौधे इस प्राकृतिक वातावरण का स्वाभाविक हिस्सा हैं। वन क्षेत्र के बाहर वृक्षों को पनपाना भी एक अत्यंत आवश्यक व महत्ती कार्य है। इस कार्य में सरकार के विभिन्न विभागों, कई संस्थाओं तथा नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है। सब के सहयोग से ही सभी के लिए यह कार्य किया जा सकता है।

9 सितंबर, 2022 को भारत में "वन के बाहर पेड़" (Trees Outside Forests - TOF) योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य भारत में वनाच्छादन को बढ़ाना है। इसी तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में राजस्थान में वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष (Trees Outside Forests in Rajasthan-TOFR) योजना की घोषणा की गई है, जिसमें वर्ष 2023-24 में विभिन्न विभागों, संस्थाओं तथा नागरिकों के सहयोग से प्रदेश में 5 करोड़ पौधे लगाया जाना तय किया गया है।

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य पारम्परिक वनों के बाहर वृक्षों के कवरेज को विस्तारित करना। राज्य में किसानों की आय में वृद्धि करते हुए कृषि प्रणालियों के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए कृषि वानिकी का उपयोग करना। रोजगार सृजन एवं आय में वृद्धि करना। वृक्ष आधारित उद्यमों में बढ़ोतरी एवं कार्बन क्रेडिट की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना एवं पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं का सृजन, वैश्विक जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए राजस्थान में वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण को बढ़ाना है।

क्रियान्वयन का तरीका व तैयारी

वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण (TOFR) को प्रोत्साहित किये जाने हेतु ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों एवं जन साधारण के सहयोग से राज्य के 33 जिलों में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाना तय किया गया है। योजना को वन विभाग के नेतृत्व में एवं जिला प्रशासन के माध्यम से एक जन अभियान के रूप में जनप्रतिनिधिगण, स्वायत्तशासी संस्थाओं, पंचायतीराज संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं व अन्य राजकीय विभागों एवं विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों इत्यादि का सहयोग लेकर क्रियान्वित किया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ पौधों के वितरण हेतु वर्ष 2022-23 में वन विभाग द्वारा 6 माह के 2 करोड़ और 12 माह के 3 करोड़ (3

फीट या इससे अधिक ऊंचाई के) कुल 5 करोड़ पौधे तैयार किए गए हैं।

वितरण एवं दर

5 करोड़ पौधों में से 1 करोड़ पौधे ग्राम पंचायतों को तथा 1 करोड़ पौधे शहरी निकायों यथा विकास प्राधिकरणों, नगर परिषदों, नगर विकास न्यासों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं आदि को उपलब्ध कराया जाना निर्धारित किया गया है। ग्राम पंचायतें ओरण, चरागाह (गोचर) में तथा शहरी निकाय शहरी क्षेत्रों में इन पौधों का रोपण करेंगे। इन में 6 माह के पौधे की दर 9 रुपये प्रति पौधा एवं 12 माह के पौधों की दर 15 रुपये प्रति पौधों निर्धारित की गई है। शेष 3 करोड़ पौधे व्यक्तिगत लाभार्थियों, जन साधारण को जन आधार कार्ड के आधार पर उपलब्ध करवाया जाना तय किया गया है। 6 माह एवं 12 माह दोनों ही आयु के पौधों के लिए 1 से 10 तक की संख्या में मांग पर 2 रुपये प्रति पौधा, 11 से 50 तक की संख्या में मांग पर 5 रुपए प्रति पौधा तथा 51 से 200 तक की संख्या में मांग पर 10 रुपये प्रति पौधा की दरें निर्धारित की गई हैं। व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 200 पौधे उपलब्ध हो सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा हाल में उन संस्थाओं और विभागों को वितरण दर में छूट दी है, जो 50,000 से अधिक पौधे क्रय करना चाहते है। इस हेतु 50,000 से अधिक व 2,00,000 पौधों तक क्रय करने पर 50 प्रतिशत की छूट एवं 2,00,000 से अधिक पौधे क्रय करने पर 75 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है।

ऑनलाइन पौधे क्रय करने की सुविधा

पहली बार नर्सरियों से पौधे ऑनलाइन क्रय करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए कोई भी नागरिक वन विभाग की वेबसाइट पर जाकर विभाग की किसी भी नर्सरी में पौधों की उपलब्धता देखकर, अपनी पसंद के पौधे, एसएसओ आईडी के माध्यम से भुगतान कर बुक करवा सकता है। उसकी बुकिंग 7 दिन तक वैध रहेगी।

मूल्यांकन व्यवस्था

योजना की सफलता के लिये योजना का प्रबोधन एवं मूल्यांकन समय-समय पर राज्य स्तर पर वन विभाग द्वारा तथा जिला स्तर पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा किया जाएगा। राज्य स्तर पर योजना की माहवार समीक्षा के लिये अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रबोधन एवं मूल्यांकन) राजस्थान प्रभारी होंगे तथा संभाग स्तर पर योजना की साप्ताहिक समीक्षा सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा की जायेगी। संभागीय मुख्य वन संरक्षक अपने स्तर पर सभी वनमंडलों का नियमित मूल्यांकन करेंगे तथा प्रगति में आ रही समस्याओं का यथासंभव निराकरण करेंगे। प्रजातिवार पौधों की उपलब्धता संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि जिलों को आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप पौधों की उपलब्धता बनी रहे तथा उप वन संरक्षक द्वारा एफएमडीएसएस पोर्टल पर दर्शाए गए प्रजातिवार पौधों की संख्या नर्सरी में उपलब्ध हों।

चालू वर्ष 2023-24 में इस योजना के तहत 17 जुलाई तक 50 लाख से भी अधिक पौधे वितरित किए जा चुके हैं। जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझनूं, अलवर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, राजसमंद सहित कुल 44 डिविजनों में इन पौधों का वितरण किया गया है। •

राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण

अरिंदम तोमर
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक

जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में वन्यजीवों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राजस्थान राज्य में अनेक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र होने के कारण जैव विविधता समृद्ध है तथा इसके संरक्षण हेतु वन्यजीवों व उनके पर्यावास की सुरक्षा अपरिहार्य है। राजस्थान में वनों, घास के मैदानों, झीलों और रेगिस्तानी क्षेत्रों जैसे विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिनका संरक्षण संरक्षित क्षेत्रों के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। साथ ही अनेक वन्य जीव प्रजातियां लुप्तप्राय अथवा संकटग्रस्त हैं जिनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत होती है। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

संरक्षित क्षेत्रों में वृद्धि

संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के प्रति अमूमन जनता में शंकाएं रहती हैं तथा कतिपय परिस्थितियों में इनकी स्थापना का पूर्व में विरोध भी हुआ है। राज्य सरकार के प्रयासों से न केवल संशयों का निराकरण हुआ है, अपितु अनेक प्रकरणों में जनता व की मांग पर संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं।

राजस्थान में 2019 में संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना को विशेष महत्व देते हुए राज्य सरकार द्वारा एक टाइगर रिजर्व (रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, 1496.49 वर्ग किमी), 16 कंजर्वेशन रिजर्व व एक अभयारण्य विस्तार की उद्घोषणाएं जारी की गई हैं। इसके साथ ही बंध बारेठा अभयारण्य का विस्तार 170 वर्ग किमी से बढ़ाकर 368 वर्ग किमी तक किए जाने की प्रारंभिक विज्ञप्ति जारी की गई है। मनसा माता, शाहबाद, शाहबाइ तलेटी, रणखार, फूलिया खुर्द, वाडाखेड़ा, बाघ दर्रा, रामगढ़, झालाना, आमागढ़, खरमोर, सोरसन—I, सोरसन—II, सोरसन—III, हमीरगढ़, कुरजां व

बांझ आमली कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए हैं।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व की स्थापना (1045.41 वर्ग किमी), रणथंभौर टाइगर रिजर्व के विस्तार (123.30 वर्ग किमी), सरिस्का टाइगर रिजर्व के विस्तार (607.66 वर्ग किमी) व मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के विस्तार (1191.56 वर्ग किमी) की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा अनेक कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जाने प्रस्तावित हैं। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व (2766.49 वर्ग किमी) के संबंध में भी एक रिपोर्ट राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को प्रेषित की गई है।

राजस्थान में 2019 से संरक्षित क्षेत्रों के क्षेत्रफल में 1,826.43 वर्ग किमी की कुल वृद्धि हुई है जिसमें अभयारण्यों से टाइगर रिजर्व में सम्मिलित किया गया क्षेत्रफल (481.91 वर्ग किमी) शामिल नहीं है।

ग्रामों का स्वैच्छिक विस्थापन

टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बसे ग्रामों के स्वैच्छिक विस्थापन की अवरुद्ध प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए गए। पूर्व में विस्थापित/आंशिक रूप से विस्थापित ग्रामीणों से किए गए वादों को पूर्ण कर व समझाइश कर उनका विश्वास दोबारा जीता गया।

वर्ष 2019 के बाद पानीढ़ाल, लॉज, गढ़ी, कालाखोहरा, डाबली, लक्ष्मीपुरा, खरली बावड़ी व घाटीगांव से सभी ग्रामीणों को सफलतापूर्वक विस्थापित किया गया। नाथूसर, मशालपुरा, गुलखेड़ी, मरमदा, चोड़क्या कलां व चोड़क्या खुर्द में विस्थापन प्रगतिरत है। 2019 से अब तक 790 परिवार विस्थापित किए जा चुके हैं तथा 183 परिवारों का विस्थापन प्रगतिरत है।

वन्यजीव संख्या में वृद्धि

जन साधारण के सहयोग व सुरक्षा में वृद्धि के कारण वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि हुई है। जब से बाघों की संख्या का आकलन आरंभ हुआ है, उस समय से आज तक बाघों की संख्या सर्वाधिक है तथा 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। चंबल नदी के सहारे धौलपुर से झालावाड़ तक बाघों का विचरण है। प्रोजेक्ट लेपर्ड के अधीन चयनित संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन करने से इनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है जिसका रचनात्मक उपयोग करते हुए पर्यटन के नए अवसर बने हैं। देश में

पहली बार राज्य में सियागोश की गणना की गई तथा इसके आधार पर केंद्र सरकार द्वारा सियागोश संरक्षण की योजना आरंभ की गई। विश्व में पहली बार गोडावण का कृत्रिम प्रजनन तथा खरमोर व हरित मुनिया का कृत्रिम प्रजनन सफलतापूर्वक किया गया। इन प्रजातियों के पर्यावास सुधार व विकास का कार्य भी निरंतर चल रहा है। अन्य प्रजातियों का भी कृत्रिम प्रजनन आरंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र के सतत अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि उसमें पाए जाने वाले सभी वन्यजीव पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों। इस कड़ी में सरिस्का में भालू का पुनर्स्थापन किया जा रहा है। बीड झुंझुनूं में काले हिरण पुनर्स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2000 के बाद पहली बार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में काले हिरण छोड़े गए हैं।

पुनर्स्थापन सुधार हेतु मुकंदरा, करौली, रामगढ़ विषधारी, जयसमंद, मोडिया, माचिया, नाहरगढ़, सरिस्का आदि में एनक्लोजर बनाकर चीतल, सांभर आदि वन्यजीव छोड़े गए हैं। 6 बाघों को सरिस्का, मुकंदरा हिल्स व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया है। पहली बार स्थान विशेष पर अस्थायी एनक्लोजर बनाकर बाघों को रिक्त टेरिटरी में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। कई वर्षों के बाद सरिस्का व भैंसरोडगढ़ में चौसिंगा की उपस्थिति दर्ज की गई है। कुंभलगढ़ में उदबिलाव की भी उपस्थिति दर्ज की गई है तथा कोटा में इनका प्रभावी संरक्षण किया जा रहा है।

पर्यावरण सुधार विकास

पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे रणखार, उम्मेदगंज, केवलादेव, चंबल आदि में संरक्षण को नए आयाम दिए गए हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अजान बांध से पाइपलाइन से जल उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। सभी आर्द्रभूमियों में डी सिल्टिंग बांध बनाना, रास्ता /मेड़ निर्माण आदि कार्य कराए गए हैं।

झालाना, आमागढ़, कुंभलगढ़, सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर आदि संरक्षित क्षेत्रों में जूलीफ्लोरा उन्मूलन कर ग्रासलैंड विकसित किए जा रहे हैं ताकि शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि हो। मानव वन्यजीव संघर्ष के अनेक प्रकरण निरंतर घटित होते रहते हैं। वन्यजीव रेस्क्यू कार्य प्रत्येक वन मंडल में निरंतर किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10,000 से अधिक मानव वन्यजीव संघर्ष प्रकरण घटित होते हैं। इनके लिये रेस्क्यू सेंटरों की स्थापना व उन्नयन का कार्य किया गया है। 25 जिलों में वन्यजीवों के रेस्क्यू व उपचार हेतु पशु चिकित्सक नियुक्त किये जा रहे हैं।

सुरक्षा

सभी टाइगर रिजर्व में विशेष बाघ संरक्षण बल का गठन कर पुलिस अथवा बॉर्डर होमगार्ड (उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में) लगाए गए हैं। सभी संरक्षित क्षेत्रों में रिक्त पदों के विरुद्ध भी होमगार्ड/बॉर्डर

होमगार्ड/नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी/सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी लगाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। स्थानीय निवासियों को वन्यजीव सुरक्षा में रोजगार दिए जाने हेतु केंद्र पोषित योजनाओं में अधिक प्रावधान किया गया है।

विकास में सहयोग

सामान्यतः वन विभाग व विशेषतः वन्यजीव प्रभाग को विकास का अवरोधक माना जाता रहा है। राज्य सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में 122 वन्यजीव स्वीकृति जारी की गई जिससे सड़क मरम्मत, ओ एफ सी केबल, जल पाइपलाइन, अंडरग्राउंड पावर केबल, पुल, नवीन सड़क आदि जन लाभकारी विकास कार्य कराए जा सकें। इन विकास कार्यों से वन्यजीव प्रबंधन पर विपरीत प्रभाव न पड़े इसके लिए मुकंदरा में 5 किमी सुरंग, रामगढ़ विषधारी में सुरंग व एलीवेटेड रोड, सिंगल स्पान ब्रिज, अंडरपास, दीवार आदि के अभिनव प्रावधान किए गए हैं जो पूरे देश में मिसाल कायम कर रहे हैं। सरिस्का में 23 किमी एलीवेटेड रोड की घोषणा हाल में की गई है जिससे न केवल अलवर, जयपुर की यात्रा सुगम होगी अपितु सरिस्का में व्यवधान भी समाप्त होगा। सरिस्का में पांडुपोल व रणथंभौर में गणेश मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों के व्यवधान को समाप्त करने के लिए कॉरिडोर बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

रोजगार सृजन

पालीघाट, जैतसागर व बस्सी में नौकायन की स्वीकृति दी गई है जिससे स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार सृजन हुआ है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, कुंभलगढ़ अभयारण्य एवं झालाना में वाहनों/रिक्शों के माध्यम से पूर्व में ही पर्यटन

आरंभ किया जा चुका था। इससे स्थानीय निवासियों को लाभ पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयसमंद में वन्यजीव सफारी, अभेड़ा बायलोजिकल पार्क (कोटा), उदयपुर पक्षी उद्यान (उदयपुर) व आमागढ़ (जयपुर) में लेपर्ड सफारी का लोकार्पण किया है। इसके अतिरिक्त अनेक स्थानों पर जनप्रतिनिधियों द्वारा सफारी इत्यादि का लोकार्पण किया गया। अब मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, कैलादेवी अभयारण्य, जयसमंद अभयारण्य, आबू पर्वत अभयारण्य, तालछापर अभयारण्य, आमागढ़, बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व व बीड़ झुंझुनूं कंजर्वेशन रिजर्व में भी सफारी की स्वीकृति जारी की गई है जिससे इन क्षेत्रों में भी पर्यटन व इस पर आधारित रोजगार का सृजन हो सके। इन सभी पर्यटन व्यवस्थाओं को ऑनलाइन भी किया गया है। लगभग 684 सफारी वाहनों को पर्यटन हेतु लगाए जाने की स्वीकृति जारी की गई है जिससे लगभग 2,000 लोगों को वाहन चालक, गाइड व वाहन मालिक के रूप में प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

योजनाबद्ध क्रियान्वयन

वन्य जीव संरक्षण से जुड़े सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से संपन्न किए गए हैं। बाघ संरक्षण हेतु बनाई गई 5 वर्षीय कार्य योजना के तहत लगभग सभी कार्य पूर्ण किए गए हैं। प्रे-बेस सुधार का कार्य एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो प्रगतिरत है।

राजस्थान में बाघ संरक्षण की एक दीर्घकालीन योजना भी तैयार की जाकर इसके तहत नवीन क्षेत्रों का चयन व विकास, कॉरिडोर चिन्हीकरण आदि की कार्यवाही प्रगतिरत है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा पुष्कर बायोलोजिकल पार्क व मरुधरा बायोलोजिकल पार्क की स्थापना, जयपुर व बीकानेर में पक्षी विहारों की स्थापना और गोड़वाड़ देसूरी-पाली में लेपर्ड कंजर्वेशन की स्थापना की घोषणा की गई है। साथ ही बाघों को बेहतर ईको सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए बाघ पर्यावास का बेहतर विकास की घोषणा की गई है।

इसी क्रम में पालीघाट सवाई माधोपुर में घड़ियाल, खींचन जोधपुर में कुरजां व राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोड ावण संरक्षण संबंधित कार्य करवाए जाएंगे।

साथ ही बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर को पक्षी संरक्षण के महत्व को देखते हुए वेटलैंड पक्षी संरक्षण केंद्र (Wetland Birds Conservation Centre) के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। आरएफबीसीपी, आरएफडीपी आदि सहायता प्राप्त परियोजनाओं में वन्यजीव संरक्षण को अधिक महत्व दिया जा रहा है।

दृष्टिकोण में बदलाव

व्यापक प्रचार व प्रसार से वन्यजीव संरक्षण के प्रति आम जनता में जागरूकता आई है। इस वर्ष वन्यजीव सप्ताह में 50,000 से अधिक विद्यार्थियों को वन्यजीव क्षेत्रों का भ्रमण कराया गया तथा उन्हें वन्यजीव संख्या के संबंध में जानकारी दी गई। •

राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में

राजस्थान ग्रीनिंग एंड रीवाइल्डिंग मिशन प्रारंभ

वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में सर्विलांस कैमरे स्थापित किये गये हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर में 12, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में 16, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में 16 , जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व पाली में 4, झालाना आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व जयपुर में 8 सर्विलांस कैमरे स्थापित किए गए हैं। कुल 56 कैमरों के द्वारा 24x7 वन्यजीवों की मॉनिटरिंग की जा रही है।

श्री हेमाराम चौधरी, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, राजस्थान से क्षिप्रा भटनागर, उपनिदेशक (जनसंपर्क) द्वारा लिए गए साक्षात्कार के प्रमुख अंश :

राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में राजस्थान सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा इसी वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइल्डिंग मिशन प्रारंभ किए जाने की बजट घोषणा की गई है, जिसके तहत कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं।

राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, राजस्थान सरकार द्वारा ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 में प्रत्येक जिले में एक-एक लव कुश वाटिका का निर्माण किया गया था। वर्ष 2023-24 में भी प्रत्येक जिले में 1-1 और लव कुश वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये तालछापर, जयसमंद, जवाहर सागर, कुंभलगढ़, रावली टाडगढ़, माउंट आबू, पालीघाट, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य तथा बांसियाल खेतड़ी, बीड झुंझुनूं, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व और मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा एवं रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी में पर्यटन सफारी प्रारंभ की गई है।

शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नगरों में ग्रीन लंग्स की आवश्यकता के क्रम में विभिन्न शहरों के आसपास के वनक्षेत्रों का विकास कर आम जनता के लिए खोला जाएगा। इस हेतु इस वित्तीय वर्ष में 28 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

राज्य सरकार द्वारा वनों के अतिरिक्त, वनों से बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए पहली बार विशेष ध्यान देकर राजस्थान में वन क्षेत्रों से बाहर वृक्ष (Trees Outside Forests in Rajasthan-TOFR) योजना शुरू की गई है जिसके तहत संपूर्ण राजस्थान में विभिन्न नर्सरियों में 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाकर जुलाई माह से वितरण शुरू कर दिया गया है।

वन क्षेत्रों के विकास हेतु आधुनिक तकनीक यथा ड्रोन, वायरलैस, कैमरा आदि का उपयोग किस तरह किया जा रहा है?

ड्रोन के माध्यम से बीजारोपण करवाकर वन के आवरण में वृद्धि की जाएगी। ऐसे स्थान जहां मानव द्वारा पौधारोपण का कार्य संभव नहीं है, उन स्थानों को चिन्हित कर ड्रोन के माध्यम से बीजारोपण किया जाएगा। पिछले वर्षों में इस तरह का कार्य करवाया गया है जिसके परिणाम सुखद रहे हैं। वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा के अनुरूप वन क्षेत्रों के विकास हेतु वन्यजीव निगरानी और अवैध शिकार विरोधी प्रणाली (Wildlife Surveillance and Anti-Poaching System) हेतु संरक्षित क्षेत्रों में 60 स्थानों पर टावर लगाए जाने प्रस्तावित हैं जिनकी संख्या रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी में 10, जमवारामगढ़ अभयारण्य जयपुर में 10, कुंभलगढ़ अभयारण्य में 10, टाडगढ़ रावली में 10, आमागढ़ नाहरगढ में 5, भैंसरोडगढ़ में 5 एवं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में 10 होगी।

खनन माफिया, लकड़ी तस्कर, वन अपराधियों, शिकारियों द्वारा विभाग के स्टाफ पर हमले की घटनाएं घटित हुई हैं। ऐसी घटनाएं न हों , इसके लिए राज्य सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु समय-समय पर परिपत्र, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। संबंधित उप वन संरक्षक को वन क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम हेतु अन्य विभागों यथा खान, राजस्व, परिवहन एवं पुलिस विभाग का सहयोग प्राप्त कर संयुक्त रूप से समय-समय पर गश्ती दलों का गठन कर वन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण करने,समुचित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित भी किया गया है।

फील्ड वनाधिकारियों को नियमित रूप से वन क्षेत्र में गश्त किये जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस संबंध में प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु प्रत्येक जिले में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की हुई है।

राजस्थान में वन अधिकार अधिनियम की प्रगति की क्या स्थिति है?

जनजाति क्षेत्रों में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अधिकार पत्र देने बाबत वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है एवं उसके अनुसार पात्र प्रार्थियों को अधिकार पत्र जारी किये गये हैं।

वर्तमान में वन अधिकार अधिनियम के तहत 48,489 व्यक्तिगत अधिकार पत्र (27,651 हेक्टेयर वन भूमि पर) तथा 591 सामुदायिक अधिकार पत्र (20,963 हेक्टेयर वन भूमि पर) जारी कर कुल 49,080 अधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निरस्त वनाधिकार दावों की केएमएल फाइल तैयार कर भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून को भिजवाई जानी थी। विभाग द्वारा 14,656 प्रकरणों की केएमएल फाइल तैयार कर भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून को भिजवाई जा चुकी है।

वनों के विकास के लिए वन विभाग की क्या प्राथमिकताएं हैं?

वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा पौधरोपण का कार्य करवाया जाता है। इस वर्ष विभिन्न योजनाओं के तहत 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा रहा है।

प्रदेश में वर्तमान में चार टाइगर रिजर्व हैं, क्या राजस्थान सरकार इनकी संख्या बढ़ाने का विचार रखती है?

धौलपुर-करौली को नया टाइगर रिजर्व बनाया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर दी गई है।

राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए क्या योजनाएं है ?

लुप्तप्राय (Critically Endangered) राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु भारत सरकार, भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राज्य सरकार के मध्य हुए त्रिपक्षीय करार के अनुसार सम क्षेत्र (जैसलमेर) में गोडावण का कृत्रिम प्रजनन केद्र प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में 25 चूजों का पालन पोषण किया जा रहा है। राष्ट्रीय मरू उद्यान में पर्यावास सुधार रिवाइल्डिंग एनक्लोजर (Rewilding enclosure) निर्माण के लिए तथा वन सुरक्षा से संबंधित कार्य किये जा रहे हैं।

वन विभाग में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों-अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया है?

अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों की विभाग में कमी के दृष्टिगत विभिन्न स्तरों पर भर्ती/नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वनरक्षक के 2,646, वनपाल के 148, क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के 115 एवं सहायक वन संरक्षक के 127 पदों पर भर्ती/नियुक्ति की कार्यवाही में प्रगति प्रक्रियाधीन है । इसी क्रम में सहायक वन संरक्षक के 122 तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी के 105 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाकर संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा अपनी उपस्थिति दी जा चुकी है। वनपाल के 148 पदों हेतु समस्त कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 148 पदों का अंतिम परिणाम जारी किया जाना शेष है। वनरक्षकों के 2,646 पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण की कार्यवाही पूर्ण कर बोर्ड को प्रेषित की जा चुकी है। इन अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही बोर्ड के स्तर पर प्रक्रियाधीन है ।

विभाग में पदोन्नति की क्या स्थिति है?

विगत वित्तीय वर्ष में राजपत्रित व अराजपत्रित कार्मिकों की 23 विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठक आयोजित कर कुल 509 कार्मिकों को पदोन्नत किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

राज्य में वनाग्नि की घटनाएं रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आपदा प्रबंधन सेल (फॉरेस्ट फायर) भारत सरकार के 3 मार्च, 2023 से प्राप्त निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय वन अग्नि की घटनाओं के रोकने हेतु फायर कंट्रोल रूम (24x7) स्थापित किए गए हैं। राज्य स्तर पर वन अग्नि कंट्रोल रूम की स्थापना हेतु नोडल अधिकारी को नामित किया गया है। साथ ही राज्य में समस्त वनमंडलों को भी वन अग्नि की घटनाओं को रोकने संबंधी फायर कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश प्रदान किए जा चुके हैं। •

राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण और संवर्धन के लिए हो रहे हैं सतत प्रयास

विषम जलवायु और सीमित वन क्षेत्र के बावजूद राजस्थान में जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए गए सतत प्रयासों की वजह से देश-विदेश से लाखों पर्यटक इन वन्य जीवों के स्वच्छंद विचरण के अवलोकन के लिए राजस्थान में स्थित अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों में आते हैं। वनों, वन्य जीवों और पक्षियों को संरक्षण देने में हाल में राज्य सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और नीतिगत पहल की हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत वन्य जीव क्षेत्रों में ढांचागत विकास, हैबिटेट सुधार, जल संसाधनों का विकास, अग्नि निरोधक कार्य एवं वन पथों को विकसित किया जा रहा है।

श्री शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से महेश पारीक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी से हुई बातचीत के प्रमुख अंश

वन और वन्यजीवों की सुरक्षा और पक्षियों का संरक्षण राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। हाल में इसके लिए कौन से प्रयास किए गए हैं?

राज्य सरकार वन और वन्यजीव की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है। दुर्लभ वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव अभयारण्य, 19 कंजर्वेशन रिजर्व और 4 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। इन सभी के संरक्षण और संवर्धन के लिए अधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य किए जा रहे हैं।

हाल में राज्य के चौथे टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में रामगढ़ विषधारी को विकसित किया गया है। कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट हेतु समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा धौलपुर टाइगर प्रोजेक्ट पर बातचीत चल रही है। बारां में शाहबाद, शाहबाद तलहटी, जालोर में रणखार, भीलवाड़ा में फुलियाखुर्द तथा उदयपुर में बाघदर्रा नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किये गए हैं।

विलुप्त हो रहे दुर्लभ वन्य जीवों व पक्षियों को संरक्षण देने में राज्य का वन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इसके अलावा धौलपुर में पांचवें टाइगर रिजर्व का कार्य प्रगति पर है।

राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए जैसलमेर के सम में गोडावण का कृत्रिम प्रजनन आरंभ कर दिया गया है। खरमोर पक्षी संरक्षण के प्रयास भी शुरू किए गए हैं। उदयपुर पक्षी उद्यान में हरित मुनिया का संरक्षण और प्रजनन शुरू किया गया है। साथ ही सरिस्का और मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बॉर्डर होमगार्ड लगाकर विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना की गई है। यह अनूठी पहल है।

राज्य में पैंथर की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है, जिसके कारण इनका प्रबंधन आवश्यक है। इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं?

पैंथर संरक्षण के लिये प्रोजेक्ट लेपर्ड के तहत सबसे पहले झालाना जयपुर को चयनित कर इसमें लेपर्ड सफारी शुरू की गई। वर्तमान में झालाना, आमागढ़, कुंभलगढ़, रावली टॉडगढ़, जयसमंद, शेरगढ़ (बारां), माउंट आबू, खेतड़ी बांसियाल, जवाई बांध एवं बस्सी व सीतामाता अभयारण्य क्षेत्रों को प्रोजेक्ट लेपर्ड में सम्मिलित किया जाकर विशेष प्रबंधन किया जा रहा है। आमागढ़, माउंट आबू, खेतड़ी, बांसियाल, बीड़ झुंझुनूं, मनसा माता, जयसमंद, कुंभलगढ़ एवं रावली टाडगढ़ क्षेत्रों में इस वर्ष पर्यटन प्रोत्साहन के लिये सफारी प्रारंभ की गई है।

संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने में पारिस्थितिकी पर्यटन की खास भूमिका है। इसे बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है?

राजस्थान अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। वन्य जीवों के

स्वच्छंद विचरण के दीदार के लिए देश—दुनिया के लाखों पर्यटक यहां के अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में आते हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। इन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए आमागढ़, कैला देवी, माउंट आबू, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, तालछापर, मनसा माता, बीड झुंझुनूं, बांसियाल खेतड़ी, झुंझुनूं, जयसमंद, कुंभलगढ़, टॉडगढ़ रावली क्षेत्रों में पर्यटन संचालन की अनुमति जारी की गई है। ईको -टूरिज्म के लिए प्रत्येक जिले में वन क्षेत्रों के निकट दो-दो ईको -टूरिज्म लव-कुश वाटिकाएं विकसित की जा रही हैं।

चंबल घड़ियाल अभयारण्य में पर्यटन की दृष्टि से बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। जयपुर के झालाना डूंगरी स्थित विश्व वानिकी उद्यान की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में भी वानिकी उद्यान विकसित किए जा रहे हैं।

पारंपरिक वनों के बाहर वनस्पति आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बजट 2023-24 में "राजस्थान में वन के बाहर पेड़" (TOFR) योजना की घोषणा की गई। इसके तहत किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं?

वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि में वनों के बाहर वृक्षों (Trees Outside Forests) की अहम भूमिका है। राज्य वन नीति, 2023 में निर्धारित वनस्पति आवरण को कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20 प्रतिशत तक बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण को विशेष प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इस योजना को एक अभियान के रूप लेते हुए ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों एवं जन साधारण के सहयोग से राज्य के सभी जिलों में एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत वर्ष 2023-24 में विभिन्न विभागों, संस्थाओं तथा नागरिकों के सहयोग से 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।

राज्य में ग्रासलैंड और वेटलैंड विकास के लिए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में घोषणा की थी। इस क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है?

हाल में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में ग्रासलैंड एवं वेटलैंड के विकास के विभिन्न कार्यों हेतु 50 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। इससे प्रदेश के 22 वन मंडलों में 7,800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण कार्यों के लिए 40 करोड़ रुपए, सांभर झील के विकास एवं प्रबंधन के लिए 9 करोड़ रुपए तथा कनवास रेंज (कोटा) के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के 19 जिलों में कुल 44 अधिसूचित वेटलैंड की सूची जारी की गई है। इससे राज्य में पारिस्थितिक तंत्र सुदृढ़ होगा और वन्यजीवों के लिए बेहतर खाद्य श्रृंखला उपलब्ध हो सकेगी।

कार्यों को सुचारू रूप से चलाने और रोजगार के लिहाज से वन विभाग में भर्तियों की क्या स्थिति है?

सहायक वन संरक्षक के 127 अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड-I के 106 अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं।

इसके अलावा वनपाल और वनरक्षक की भर्ती प्रक्रियाधीन है। अनुकंपात्मक नियुक्ति के तहत 118 कनिष्ठ सहायक के पदों पर मृतक आश्रितों को नियुक्ति दी जा चुकी है। सर्वेयर, वाहन चालक, कनिष्ठ अभियंता, प्रयोगशाला सहायक, गार्ड आदि की भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है।

वन विभाग की हाल में की गई नीतिगत पहले कौन सी हैं?

प्रदेश में वनों के संरक्षण को गति देने और बदलते समय की जरूरत के मुताबिक इस क्षेत्र के नवाचारों को शामिल करते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान वन नीति 2023 जारी की है जो राज्य वन नीति, 2010 को प्रतिस्थापित करेगी।

इसके अलावा राज्य में ई-वेस्ट को कम करने, उसके पुनः उपयोग तथा रि-साइकिल करने और ई-वेस्ट से पर्यावरण को पहुंच रही क्षति को कम करने के उद्देश्य से ई-वेस्ट प्रबंधन नीति तैयार की गई है।

इस नीति के लागू होने से राज्य में ई-वेस्ट को कम करने, वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने, रि-साइकिल एंड रि-यूज का क्रियान्वयन होगा, साथ ही वायु, जल एवं मृदा तथा अन्य पर्यावरणीय नुकसान को कम करने में सहायता मिलेगी।

राज्य सरकार ने पारिस्थितिकी संरक्षण एवं स्थानीय समुदाय के विकास को केंद्र में रखकर ईको टूरिज्म पॉलिसी 2021 लागू की है। इस नीति से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संपदाओं के संरक्षण में जनजागरुकता के साथ स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों का सृजन होगा। •

उदयपुर के नैसर्गिक सौंदर्य को मिला सम्मान

डॉ. कमलेश शर्मा
संयुक्त निदेशक, जनसंपर्क

सघन हरितिमा से आच्छादित विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसे मेवाड़ अंचल पर प्रकृति की असीम कृपा पहले से ही रही है, वहीं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी अपने कार्यकाल में इस अंचल के नैसर्गिक सौंदर्य को सम्मान देते हुए वन एवं वन्यजीव संस्कृति को संरक्षण और संवर्धन दिया है।

मौजूदा राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं-परियोजनाओं के माध्यम से इस अंचल में वनों के संरक्षण-संवर्धन के साथ-साथ यहां के पक्षियों, वन्यजीवों को अभयदान भी दिया है। गुलाब बाग में लोकार्पित हुए राजस्थान के पहले बर्ड पार्क में संचालित हो रहे ग्रीन मुनिया ब्रीडिंग सेंटर, गत दिनों शहर के माछला मगरा में बनाई गई लव-कुश वाटिका, जयसमंद अभयारण्य में प्रारंभ की गई लेपर्ड सफारी और मुख्यमंत्री द्वारा गत दिनों की गई पैंथर रेस्क्यू सेंटर और वन क्षेत्रों में लगने वाली आग से पेड़-पौधों व वन्यजीवों को बचाने के लिए अत्याधुनिक संसाधनों व प्रशिक्षण की घोषणा और इसको अमलीजामा पहनाने में किए जा रहे प्रयास इसके साक्षात उदाहरण हैं।

इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा उदयपुर जिला मुख्यालय से 12 किमी की दूरी पर उदयपुर-झामर कोटड़ा सड़क मार्ग पर स्थित बाघदड़ा वन खंड को विकसित करने की दृष्टि से नेचर पार्क की स्थापना की गई है, जहां पर वन एवं वन्यजीव तथा ईको-टूरिज्म के विकास हेतु प्राकृतिक आवास सुधार (Habitat Improvement), वनपथ संधारण, अग्नि सुरक्षा पट्टियों का संधारण, वाटर हॉल का निर्माण एवं संधारण के कार्य कराए गए। शहर में स्थित जैविक उद्यान सज्जनगढ़ और वन्यजीव अभयारण्य सज्जनगढ़ के माध्यम से भी पर्यटकों को वन्यजीव संस्कृति से रूबरू करवाया जा रहा है। शहर से सटे चिरवा क्षेत्र में फूलों की घाटी और समीप ही जैव विविधता पार्क व पुरोहितों का तालाब भी लेकसिटी में आने वाले पर्यटकों की पसंदीदा जगह हैं।

राजस्थान का पहला बर्ड पार्क

अपनी विमोहिनी झीलों के लिए विश्व प्रसिद्ध लेकसिटी में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 12 मई, 2022 को राजस्थान के पहले बर्ड पार्क का लोकार्पण किया। शहर के हृदय स्थल पर गुलाब बाग में करीब साढ़े ग्यारह करोड़ रुपये की लागत वाले इस आकर्षक बर्ड पार्क का निर्माण करवाया गया। करीब 5.11 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए गुलाब बाग के 3.85 हेक्टेयर में बर्ड पार्क का निर्माण किया गया है। इस पार्क के लिए पर्यटन विभाग ने 8 करोड़, नगर निगम ने 1.75 करोड़, यूआईटी ने 1.74 करोड़ रुपये दिए हैं।

बर्ड पार्क में पर्यटकों को एशियन, आस्ट्रेलियन, अफ्रीकन और अमेरिकन परिंदों के दीदार हो सकेंगे। इसमें कुल 28 प्रजातियों के पक्षियों को रखा गया है। इसमें मकाऊ, काकाटू, सन कोंनुअर, सेनेगल पैरेट, बैरा

बैंड पैराकीट, रोक पेब्लर, किम्सन बिग, पिंक कुर्क, सेनेगल फायर फिंच, रेड चिक्ड कार्डन ब्लू, ब्लैक रम्पड वैक्स बिल, कैलिफोर्निया क्वेल, नार्थन बॉब व्हाइट, चाइनीज क्वेल, ग्रीन मुनिया आदि की अठखेलियां पर्यटक करीब से देख सकेंगे। इसी प्रकार रोज रिंग पैराकीट, एलग्जैडिया पेरेट, प्लम हैडेड पैराकीट, मोर, बज्रीघर, लव बर्ड, कोकाटेल, रोजी पेलिकन, कॉम्ब डक, ग्रैलेग गूज, अमेरिकन पकिन, सिल्वर फिजेंट व ईमु शामिल हैं। बर्ड पार्क गुलाबबाग में 12 एक्जीबिट्स यानी पिंजरे बनाए गए हैं, जिनमें असोर्टेट पैराकीट, ईमु, ग्रीन मुनिया, लेसर पैसेराइन, ओस्टरीच, बार्न आउल, मका, ककाटू प्रजातियों के पक्षियों को रखा गया है।

पेंथर रेस्क्यू सेंटर

बर्ड पार्क के लोकार्पण उपरांत मुख्यमंत्री ने उदयपुर जिले में पैंथर की संख्या को देखते हुए पैंथर संरक्षण के लिए पैंथर रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने जिले के 31 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र और ग्रीष्म ऋतु में वन क्षेत्रों में आए दिन आग लगने की घटनाओं पर वनकर्मियों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाते हुए प्रशिक्षण दिलाने की भी घोषणा की।

राज्य में 50 पक्षीघरों का होगा निर्माण

सरकार द्वारा पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए किए गए निर्णय से पक्षी प्रेमियों में खुशी है। इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 43.50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। ये सभी पक्षीघर 33 लवकुश वाटिका और 17 अन्य जगहों पर बनाए जाएंगे।

प्रदेशभर मे बनने वाले इन 50 पक्षीघरों में प्रति पक्षीघर 87 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। उदयपुर के गुलाब बाग में बने पक्षीघर की तर्ज पर ये सभी पक्षीघर बनाए जाएंगे। पक्षीघरों के निर्माण, पक्षियों के लिए भोजन एवं विदेशी पक्षियों के क्रय के लिए प्रति पक्षीघर 87 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार कुल 43.50 करोड़ रुपये इस योजना पर खर्च होंगे। सरकार की ओर से मंजूर की गई 43.50 करोड़ रुपये में से एक-एक लाख रुपये से पक्षीघरों में कोकटियल (ऑस्ट्रेलियाई बर्ड), लव बर्ड तोता, बजरिगर (बुग्गी तोता), गिनी फाउल (चकोर मुर्गा) आदि पक्षी भी पेट शॉप्स से खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की इस मंजूरी से प्रदेश में पक्षियों को संरक्षण मिलने के साथ ही बीमार, असहाय एवं घायल पक्षियों का उपचार एवं संवर्द्धन किया जा सकेगा।

जयसमंद अभयारण्य में जंगल सफारी

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर पर्यटन सिटी उदयपुर में आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों को अनोखी सौगात प्रदान करते हुए जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया। जयसमंद अभयारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत से उदयपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही प्रदेश में एक प्रमुख ईकोटूरिज्म साइट का विकास होगा तथा क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। जयसमंद अभयारण्य में प्रोजेक्ट लेपर्ड के तहत किए गए प्रयासों से वर्तमान में लेपर्ड की संख्या बढ़कर 19 हो चुकी है।

जयसमंद अभयारण्य में विकास कार्य

राज्य सरकार द्वारा अभयारण्य में जंगल सफारी प्रारंभ करने के लिए वन विभाग के माध्यम से विविध विकास कार्य करवाए गए। इसके तहत अभयारण्य में 37 किलोमीटर प्रोटेक्शन ट्रैक का निर्माण, 4 वाटर प्वाइंट का निर्माण, 2 पुराने प्वाइंट का पुनरुद्धार, 3 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई वहीं गेट एवं बेरियर के साथ ही गार्ड चौकी रिनोवेशन व सुविधाओं का विकास किया गया। •

कोटा में दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट
देश-दुनिया की अद्भुत विशेषताएं एक ही स्थान पर

■ हरिओम सिंह गुर्जर
उप निदेशक, जनसंपर्क

रेतीले धोरों, मरुस्थल और किले-महलों के लिए विश्व विख्यात राजस्थान अब प्रदेश की एकमात्र सदानीरा चंबल नदी पर कोटा में बने हेरिटेज रिवर फ्रंट के लिए विश्व भर में जाना जाएगा। देश-दुनिया के पर्यटकों को लगभग 6 किमी के भ्रमण में अलग-अलग देशों की प्रसिद्ध इमारतों के दिग्दर्शन यहां होगें तो उनमें खान-पान भी उसी संस्कृति का मिलेगा। नदी किनारे बने 26 घाट अलग-अलग निर्माण शैली एवं उद्देश्यों को अपने में समाए हुए हैं।

कोटा बैराज के डाउन स्ट्रीम में चंबल नदी के दोनों किनारों को रिवरफ्रंट के लिए बेहद खूबसूरत बनाया जाकर अनेक विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। स्थापत्य शैली एवं आर्किटेक्ट की दृष्टि से इस स्थान को अद्भुत रूप से तराशा गया है। जहां हर इमारत, मूर्ति, किले का प्रतिरूप, नदी के विभिन्न घाट वास्तु की दृष्टि से भी अतुलनीय दिखाई देते हैं। रिवरफ्रंट को पूर्वी जोन एवं पश्चिमी जोन में बांटा गया है। यहां पर बच्चों, युवा, वरिष्ठ नागरिक हर वर्ग के आकर्षण को ध्यान में रखकर सुविधाओं को विकसित किया गया है। यहां पर्यटकों के लिए वोटिंग और क्रूज का संचालन भी होगा। चंबल नदी के दोनों किनारों पर भारत के पहले हेरिटेज रिवरफ्रंट का निर्माण 1,200 करोड़ की लागत से किया गया है। लगभग 6 किमी के रिवरफ्रंट पर देश की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति, वियतनाम के मार्बल से बनी विश्व की सबसे बड़ी चंबल माता की मूर्ति देखने को मिलेगी तो विष्णु के 10 अवतार के दर्शन भी यहीं होंगे।

स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल के मुताबिक चंबल नदी पर बना यह रिवरफ्रंट देश का पहला हेरिटेज रिवरफ्रंट है। इसे किसी एक विधा में सीमित नहीं किया जा सकता। इसमें संपूर्ण विश्व के पर्यटन महत्व के स्मारक हैं तो देश की प्रमुख विशेषताओं, राजस्थानी स्थापत्य एवं शौर्य गाथाओं का दिग्दर्शन एक स्थान पर देखा जा सकता है। सदानीरा चंबल के दोनों ओर घनी आबादी होने के कारण कभी इस क्षेत्र में आबादी के नालों का पानी सीधे नदी में मिलता था जिससे जलीय जीवों को नुकसान के साथ नदी में प्रदूषण बढ़ता जा रहा था। गंदगी एवं खरपतवार के कारण यहां आसपास नागरिक भी जाना पसंद नहीं करते थे। राज्य सरकार नालों के गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए लगातार प्रयासरत थी। रिवरफ्रंट बनने से नदी के प्रदूषण का खतरा समाप्त हो गया है। नदी में गिर रहे 14 गंदे नालों को ट्रेप कर पानी को एसटीपी से फिल्टर ट्रीटमेंट किया गया है। इससे चंबल के पानी का शुद्धीकरण भी होगा। वहीं जलीय जीव-जंतुओं की अठखेलियां अब निर्बाध रूप से देखी जा रही हैं।

रिवर फ्रंट बनने से पहले हर साल चंबल नदी में आने वाली बाढ़ के कारण आसपास के आबादी क्षेत्र में बाढ़ का पानी चला जाता था जिससे स्थानीय प्रशासन को प्रतिवर्ष आर्थिक नुकसान के साथ बरसात की ऋतु में अलर्ट रहना पड़ता था। नदी के दोनों किनारों पर बसी आबादी को अस्थायी शिविरों में जीवन गुजारना पड़ता था। कोटा बैराज से लेकर पुल तक नदी के

दोनों किनारें पर 6 किमी की दूरी तक अब बाढ़ के खतरे से स्थायी निजात मिल गई है।

नेहरू की आंखों से देख सकेंगे रिवर फ्रंट

रिवर फ्रंट के पश्चिमी जोन में 120 मीटर की लंबाई में जवाहर घाट का निर्माण किया गया है। इस घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का फेस मास्क बनाया गया है। यह फेस मास्क 12 मीटर ऊंचा और 3 मीटर चौड़ा है। गनमेटल से यह फेस मास्क बनाया गया है। इसके पीछे की तरफ से लोग इस मास्क के अंदर जा सकेंगे जो कि आंखों तक पहुंचेंगे और वहां से रिवरफ्रंट का नजारा देख सकेंगे। इसके बिल्कुल सामने चंबल माता की मूर्ति है जिसके भी दर्शन नेहरू की आंखों से किए जा सकेंगे।

विश्व की सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा

रिवर फ्रंट के पश्चिमी जोन में विश्व की सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा बनाई गई है। नंदी की प्रतिमा की ऊंचाई 6.5 मीटर, लंबाई 10.5 और चौड़ाई 4.5 मीटर है। नंदी की प्रतिमा जोधपुर स्टोन से बनाई गई है। इस प्रतिमा के सामने वैदिक मंदिर के स्ट्रक्चर भी तैयार किए गए हैं, जो पांच तत्वों को दर्शाते हैं।

विश्व की सबसे बड़ी घंटी

रिवर फ्रंट के पश्चिम जोन में विश्व की सबसे बड़ी घंटी भी स्थापित की जा रही है। यह घंटी सिंगल पीस कास्टिंग की होगी, यानी इसे टुकड़ों में नहीं लगाया जाएगा बल्कि सिंगल पीस ही बनाया जाएगा। यह 30 फीट ऊंची और 28 फीट चौड़ी होगी तथा इसका वजन 72 टन है। अष्ट धातु से इसका निर्माण किया जा रहा है। इसकी उम्र 5,000 साल होगी। इसकी एक और खास बात यह है कि इसमें जो पेंडुलम होगा वह भी बिना ज्वाइंट का होगा। दुनिया में चीन और रूस में ही ऐसी घंटियां हैं जिसमें से चीन की 6 गुणा 6 मीटर और रूस की 6 गुणा 6.5 मीटर की है। लेकिन रूस वाली घंटी को कभी लटकाया नहीं जा सका। वह सिंगल कास्टिंग की भी नहीं है।

सबसे बड़ी चंबल माता की मूर्ति

चंबल के पूर्वी किनारे पर रिवर फ्रंट पर सबसे बड़ी चंबल माता की मूर्ति स्थापित की जा रही है। यह प्रतिमा रिवर फ्रंट पर बैराज की तरफ बनाए गए बैराज गार्डन में बन रही है। वृंदावन गार्डन की तर्ज पर इस बैराज गार्डन को विकसित किया गया है। जहां 20 मीटर के पेडेस्टल पर 42 मीटर ऊंची चंबल माता की मूर्ति बनाई जा रही है। वियतनाम मार्बल से इसका निर्माण हो रहा है। यह भारत में संगमरमर की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। यहां 40 मीटर व्यास का बार्सिलोना फाउंटेन की तर्ज पर फाउंटेन भी बनाया गया है जहां लोग रंग बिरंगी रोशनी और म्यूजिक के साथ फाउंटेन शो देख सकेंगे। फव्वारे के सामने 42 मीटर ऊंची कैसल बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें संग्रहालय संचालित किया जा रहा है।

योग करता साधक गायब होकर चौंकाएगा

रिवरफ्रंट के पश्चिमी जोन में योग घाट बनाया गया है। भारतीय संस्कृति में योग की महत्ता को दिखाते हुए यहां 6 मीटर ऊंचा योग करते एक साधक को दिखाया गया हैं। यह इनविजिबल स्ट्रक्चर होगा। यानी कभी देखने पर ऐसा लगेगा कि यहां पर स्ट्रक्चर है तो कभी ऐसा लगेगा कि यहां कुछ नहीं है।

इसे स्टेनलैस स्टील से बनाया गया है। इसके निर्माण में स्टील की पत्तियों का उपयोग किया गया है। योग की महत्ता को साधक के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।

देश का पहला एलईडी गार्डन

चंबल रिवर फ्रंट पर देश का पहला एलईडी गार्डन भी बनाया गया है। इस घाट पर जो गार्डन विकसित किया है, उसमें एलईडी से अलग-अलग एलिमेंट बनाए गए हैं। एलईडी से पक्षी, पेड़-पौधों के एलिमेंट बनाएंगे। एक तरह से एलईडी शो की तरह ही यह काम करेगा। यहां आने वाले लोगों को

वास्तविक पेड़—पौधों और पक्षियों की जगह एलईडी एलिमेंट दिखाई देंगे।

ज्योतिष घाट

रिवर फ्रंट के पूर्वी जोन में ज्योतिष घाट बनाया गया है। जहां एक टावर पर अलग-अलग राशि के चक्र प्रदर्शित किए गए हैं। यहां भारतीय संस्कृति में ज्योतिष गणना के महत्व को प्रदर्शित किया जाकर व्यक्ति के जीवन में राशि चक्रों के प्रभाव को बताया गया है।

विश्व के प्रमुख भवन एक स्थान पर

वर्ल्ड हेरिटेज में अलग-अलग देशों के 9 प्रमुख भवनों को रिवर फ्रंट पर बनाया गया है। इनमें वेस्टमिंस्टर एबे इंग्लैंड, ईरान की अगाह बोजोर्ग मोस्क, दक्षिण भारतीय शैली में मंदिर प्रवेश का गोपुरम, इटली का ट्रेवी फाउंटेन, दिल्ली का लाल किला, चीन का पगोड़ा फोगोंग टेम्पल, फ्रांस का म्यूजियम, यूएस कैपिटल वॉशिंगटन और थाई टेम्पल की प्रतिकृतियां बनाई गई हैं। इन सभी भवनों की विशेषता यह है कि इनमें इन देशों की खानपान संस्कृति के अनुसार रेस्टोरेंट चलेंगे। मिसाल के तौर पर लाल किला भवन में मुगलई, गौपुरम भवन में साउथ, चाइनीस बिल्डिंग में चाइनीस फूड का लुत्फ यहां आने वाले पर्यटक उठा सकेंगे।

हाड़ौती घाट

रिवर फ्रंट पर हाड़ौती की लोक कला, स्थापत्य एवं सांस्कृतिक परंपराओं को भी प्रदर्शित किया गया है, जहां बूंदी शैली में 84 खंभों की छतरी और तारागढ़ फोर्ट का प्रवेश द्धार बनाया गया है। यहां पर 10- 10 फुट की पन्नाधाय और हाड़ी रानी की गनमेटल से बनी प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं।

राजस्थानी घाट

राजस्थानी घाट पर शौर्य एवं स्थापत्य कला का संगम किया गया है। यहां जयपुर का हवा महल, सरगासूली, घंटाघर, किले और महलों को प्रदर्शित किया गया है। यहां राजस्थानी योद्धाओं की प्रतिमा स्थापित की गई है। रिवरफ्रंट पर राजस्थानी पहचान के लिए गन मेटल के बने विशालकाय ऊंट की प्रतिमाएं स्थापित की गई है।

रामुपरा घाट

रामपुरा घाट पर बड़ी समाधि के पास विष्णु के 10 अवतारों की प्रतिमाएं एक ही स्थान पर भव्य रूप में देखने को मिलेंगी। यहां विष्णु के दसवें अवतार कल्कि के भी दर्शन किए जा सकेंगे।

किड्स जोन में वाटर पार्क, म्यूजिकल जोन

रिवर फ्रंट पर किड्स जोन बनाया गया है जिसे वाटर पार्क नाम दिया है। यहां तीन पुल होंगे जिनमें एक छोटा पुल बच्चों के लिए भी होगा जिसमें वाटर स्लाइडिंग रहेगी। पार्टी हॉल होगा, म्यूजिकल जोन में एम्फीथिएटर होगा जहां कलाकार अपनी प्रस्तुति दे सकेंगे और लोग बैठकर सुन सकेंगे। म्यूजिकल जोन के घाट को पियानो के आधार पर काले और सफेद पत्थर से बनाया है।

तरह-तरह के रिकॉर्ड

- चंबल रिवर फ्रंट देश का पहला हेरिटेज रिवरफ्रंट है, जहां इतनी शैलियां, अलग-अलग घाट अलग-अलग थीम पर बनाए गए हैं।
- भारत में संगमरमर की सबसे ऊंची मूर्ति चंबल माता की मूर्ति यही स्थापित की गई है।
- भारत का पहला एलईडी गार्डन चंबल रिवर फ्रंट पर बनाया गया है।
- सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा रिवर फ्रंट पर स्थापित हुई है।

साहित्य घाट में पुस्तकों का ज्ञान

रिवर फ्रंट पर साहित्य घाट भी बनाया बया है जिसे किताबों का आकार दिया गया है। इसे बांसवाड़ा के पत्थर से बनाया गया है। यहां 5 साहित्यकारों की प्रतिमाएं भी लगेंगी। लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी जा सकेंगी।

नदी को निहारते शेर

सिंह घाट में 9 शेरों की सफेद मार्बल से बनी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। 35-35 टन वजनी शेर बैठे हुए चंबल नदी को निहारते हुए दिखाई देते हैं। इस घाट के पास व्यावसायिक दुकानें बनाई गई हैं। इनमें पर्यटकों के लिए स्थानीय उत्पाद एवं खानपान की सामग्री मिलेगी।

गीता के उपदेश

रिवर फ्रंट के पश्चिमी किनारे पर गीता घाट बनाया गया है, जहां पर गनमेटल से लिखे गीता के श्लोक लगाए गए हैं। गीता के ये श्लोक यहां आने वाले लोगों को ज्ञान का संदेश देंगे।

मशाल घाट

मशाल को उत्साह एवं प्रगति का सूचक माना जाता है। रिवर फ्रंट पर मशाल घाट बनाया गया है जिसमें जलती हुई मसालें पर्यटकों को दिखाई देंगी। •

सरिस्का बना बाघों का घर

मनोज कुमार
जनसंपर्क अधिकारी

अरावली की सुरम्य पर्वत श्रेणी की तलहटी में बसे अलवर जिले को राजस्थान के सिंहद्वार के रूप में जाना जाता है क्योंकि अलवर शहर से करीब 40 कि.मी. की दूरी पर सरिस्का अभयारण्य स्थित है। यह मौजूदा समय में बाघों का घर बन गया है। सरिस्का अभयारण्य पहाड़ों की तलहटी में होने, सघन पौधों से चारों तरफ से घिरा होने एवं बाघों की शरणस्थली होने के कारण यहां दिन-प्रतिदिन पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यह देशी-विदेशी सभी तरह के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।

बाघों की संख्या में वृद्धि

सरिस्का अभयारण्य बाघों की पसंदीदा जगह होने के कारण बाघों की शरणस्थली बना हुआ है। सरिस्का में बाघों के पुनर्वास के उपरांत निरंतर उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। हाल में सरिस्का रेंज अलवर बफर के वन क्षेत्र में बाघिन एस.टी. 19 द्वारा दो शावकों को जन्म देने पर अब बाघों की संख्या 30 हो गई है। साथ-साथ सरिस्का जलीय प्रजातियों के लिए एक आदर्श आवास स्थान है क्योंकि इसमें साल भर पानी बरकरार रहता है। यहां करनावास तालाब में मगरमच्छ व कछुए बहुतायत में पाए जाते हैं। अत्यधिक समृद्ध जैव विविधता वाला बाघ अभयारण्य सरिस्का न केवल कई स्तनधारियों और पक्षियों का घर है बल्कि यह विभिन्न सरीसृप प्रजातियों का भी पसंदीदा निवास स्थान है। इसके साथ ही यहां विभिन्न प्रकार के पशु-पक्षी भी पाए जाते हैं जिनमें चीतल, सांभर, हिरण, नीलगाय, तेंदुआ, लकड़बग्घा, सियार, जंगली बिल्ली, भेड़िया, सांभर, चीतल, जंगली भालू सहित अन्य वन्यजीव स्वच्छंद विचरण करते देखे जा सकते हैं।

विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की शरणस्थली

सरिस्का अभयारण्य में विभिन्न प्रजातियों के देशी-विदेशी पक्षी निवास करते हैं, इसलिए इसे पक्षियों की शरणस्थली भी कहा जाता है। अभयारण्य में पक्षियों की कुल 345 से अधिक प्रजातियां निवास करती हैं जिनमें से भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, ग्रे पार्ट्रिज, पेंटेड स्परफॉवल, बुश बटेर,

सैंड ग्राउज, रूफस ट्रीपी, गोल्डन बैकेड, वुडपेकर, क्रेस्टेड सर्पेंटट ईगल, व्हाइट आइड बजर्ड, ओरिएंटल हनी बजर्ड, शिकरा, शॉर्ट टो स्नेक ईगल, इंडियन ईगल उल्लू, डस्की ईगल उल्लू, ब्राउन फिश उल्लू, पैराडाइज फ्लाईकैचर, गोल्डन ओरियल, भारतीय गिद्ध, मिस्र के गिद्ध (नियोफ्रॉन पर्कनोप्टेरस), लाल सिर वाले गिद्ध (सरकोजिप्स कैल्वेस), सिनेरियस गिद्ध (एजिपियस मोनैचस) प्रजाति के पक्षी निवास करते हैं।

पर्यटकों की सुख-सुविधाओं से समृद्ध क्षेत्र

देश की राजधानी नई दिल्ली व राज्य की राजधानी जयपुर से करीब 150 कि.मी की दूरी पर होने व एनसीआर क्षेत्र में स्थित होने के साथ रेल व सड़क मार्ग की बेहतर कनेक्टिविटी एवं पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र होने के कारण सरिस्का अभयारण्य में वर्ष भर यहां पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। देश-विदेश से पर्यटक यहां बाघों एवं अन्य पशु-पक्षियों की एक झलक पाने, प्रकृति की गोद में बसे इस शांत क्षेत्र में आनंद के क्षणों को महसूस करने के लिए भ्रमण पर आते हैं। पर्यटकों की संख्या में इजाफा कर पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पर्यटकों की सुख-सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए आरटीडीसी के होटल संचालित किए गए हैं। इनमें पर्यटकों के रहने, खाने, टूरिस्ट गाइड आदि सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

सरिस्का व इसके आसपास हैं दर्शनीय व ऐतिहासिक स्थल

अरावली पर्वत श्रृंखला को छूते हुए सरिस्का अभयारण्य के क्षेत्र में विभिन्न दर्शनीय व ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं जो बडी संख्या में देशी-विदेशी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।

सिलीसेढ़

सरिस्का अभयारण्य के पास सिलीसेढ़ बांध तीनों ओर से अरावली पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। तत्कालीन शासक विनय सिंह ने सन् 1844 ई. में 8 लाख रुपये की लागत से इस बांध का निर्माण करवाया था। 40 फीट ऊंचे व 100 फीट लंबे इस बांध के किनारे 4 मंजिला महल बना हुआ है। वर्तमान में यह आरटीडीसी का होटल है जिसमें ठहरने की व्यवस्था है। इसके अलावा यहां नौका विहार के लिए पैडल बोट्स भी उपलब्ध हैं। वर्षा ऋतु में यह स्थान और भी अधिक मनोहारी हो जाता है।

भर्तृहरि

सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में स्थित भर्तृहरि मंदिर जन आस्था का केंद्र है। उज्जैन के राजा और योगी भर्तृहरि ने अलवर के जिस स्थान को अपनी तपस्या स्थली चुना था, वही तपस्या स्थली भर्तृहरि के नाम से विख्यात है जो अलवर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां बनी भर्तृहरि की समाधि पर बड़ी संख्या में दर्शनार्थी अपने श्रद्धासुमन चढ़ाने पहुंचते हैं। हर वर्ष भाद्रपद और बैसाख माह में यहां भर्तृहरि का मेला लगता है। इस क्षेत्र के लोक देवता के रूप में विराजित भर्तृहरि बाबा की जयघोष के साथ नए कार्य का श्री गणेश करना शुभ माना जाता है। नाथ संप्रदाय के साधुओं का यहां वार्षिक सम्मेलन होता है।

पांडुपोल

सरिस्का अभयारण्य में पांडुपोल स्थित है। पांडुपोल में शयन मुद्रा में हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर से आगे पोल बनी हुई है जो कि प्राकृतिक रूप से पहाड़ काटकर बनी है। कहा जाता है कि भीम ने अपनी गदा से यह मार्ग बनाया था। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भाद्रपद के महीने में यहां विशाल मेला

लगता है जिसमें अलवर के अलावा अन्य जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जिले व आस-पास के क्षेत्रों के लोगों के लिए यह आस्था का विशिष्ट स्थान है।

भानगढ़

सरिस्का अभयारण्य के पास स्थित भानगढ़ के बारे में कहा जाता है कि यह नगरी अचानक अज्ञात कारण से उजड़ गई थी। यहां पर योजनाबद्ध तरीके से निर्मित आवास, बाजार एवं कलात्मक मंदिर के अवशेष देखने लायक हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसे पूर्व स्थिति में संयोजित किया जा रहा है।

नीलकंठ

सरिस्का अभयारण्य में स्थित दर्शनीय स्थलों में नीलकंठ भी एक सुरम्य दर्शनीय और धार्मिक स्थल है। यहां नीलकंठेश्वर का प्राचीन मंदिर है। अलवर शहर से दक्षिण-पश्चिम में 61 किलोमीटर दूर स्थित नीलकंठ का प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा अनुपम है।

तालवृक्ष

सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में ही स्थित तालवृक्ष जिले का एक सुरम्य स्थल है जो ऐतिहासिक व प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। अलवर-नारायणपुर मार्ग पर स्थित यह स्थल पहाड़ों की गोद में सघन वृक्षों से आच्छादित है। ऐसा माना जाता है कि महान ऋषि मांडव्य ने इस स्थल को अपनी तपोस्थली बनाया था। प्राकृतिक सौंदर्य और मनोहरी दृश्यों से भरपूर इस स्थल को देखने हजारों सैलानी आते हैं। गंगा माता का प्राचीन मंदिर और उसके नीचे बने गर्म व ठंडे पानी के कुंडों के कारण इस स्थल का महत्व एवं आकर्षण और भी बढ़ जाता है।

नलदेश्वर

सरिस्का अभयारण्य में जिले के प्राकृतिक सुरम्य स्थलों में नलदेश्वर का भी नाम आता है। यह अलवर और थानागाजी के मध्य पहाड़ियों में स्थित है। नलदेश्वर में महादेव जी का मंदिर है जो नैसर्गिक पहाड़ी चट्टानों से बना हुआ है। यहां तक पहुंचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर बनी मंदिरनुमा चट्टान से निरंतर पानी नीचे कुंड में गिरता रहता है। कुंड यहां की शोभा में और भी बढ़ोतरी करता है। यह क्षेत्र बांधों की नर्सरी के रूप में पहचाना जाता है।

मूसी महारानी की छतरी

अलवर शहर में स्थित 80 खंभों पर स्थित बाला दुर्ग की तलहटी में तरणताल सागर के दक्षिणी किनारे पर बनी यह अनूठी छतरी स्थापत्य कला की एक अनुपम धरोहर है।

संग्रहालय

अलवर संग्रहालय उत्तरी भारत के अच्छे संग्रहालयों में माना जाता है। यहां पर विशेष रूप से दुर्लभ ऐतिहासिक हथियारों, ऐतिहासिक मुगल

शासकों की तलवारें, पांडुलिपियां, कलात्मक वस्तुओं और प्राचीन मूर्तियों तथा शिलालेखों का संग्रह है। चित्रकला की दृष्टि से भी यह संग्रहालय बहुत समृद्ध है। यहां पर राग-रागनियां और बारहमास संबंधी चित्र भी बड़े सुंदर हैं। अलवर शैली के चित्र भी इस संग्रहालय में उपलब्ध हैं।

बाला दुर्ग

अलवर का बाला दुर्ग ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दुर्ग है। यह समुद्रतल से 1,960 फुट और समतल भूमि से एक हजार फुट ऊंचा है। किले में प्रवेश के लिए छह दरवाजे हैं, जिनमें पश्चिम में चांदपोल, पूर्व में सूरजपोल, दक्षिण में लक्ष्मणपोल और उत्तर में अंधेरी दरवाजा है। इनके अतिरिक्त पश्चिम में जयपोल और पूर्व में कृष्ण पोल भी है जो कृष्ण कुंड के पास स्थित है। दुर्ग से हाल में विकसित बायोडायवर्सिटी पार्क का विहंगम दृश्य नजर आता है। •

रणथंभौर टाइगर रिजर्व

प्रकृति के आनंद के बीच बाघ का दीदार

हेमंत सिंह

सहायक निदेशक, जनसंपर्क

एक ओर जहां रणथंभौर दुर्ग अपनी आन, बान, शान एवं शौर्य के कारण विश्व प्रसिद्ध है। वहीं दूसरी ओर रणथंभौर टाइगर रिजर्व अपनी जैव विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य एवं स्वच्छंद विचरण करते वन्य जीव-जंतुओं की वजह से एकाएक देशी-विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह टाइगर रिजर्व सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

अरावली और विंध्याचल पर्वत मालाओं के संगम स्थल पर स्थित इस टाइगर रिजर्व के उत्तर-पश्चिम में बनास व दक्षिण में चंबल नदी वर्ष पर्यंत बहती है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में औसतन 800 मिमी तक बरसात होती है। वन्य जीव की जलापूर्ति के लिए टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मलिक तालाब, पद्म तालाब, राजबाग तालाब के साथ कमलधार, नालघाटी में प्राकृतिक स्रोतों से लगातार जल प्रवाहित रहता है।

यह टाइगर रिजर्व 1,700.22 वर्ग किमी में फैला है जिसमें सवाई माधोपुर, करौली और टोंक जिलों के क्षेत्र शामिल हैं। प्रशासनिक एवं प्रबंधन की दृष्टि से रणथंभौर टाइगर रिजर्व को दो वन मंडलों उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक प्रथम रणथंभौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर, उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक द्वितीय रणथंभौर बाघ परियोजना करौली में विभाजित किया गया है। सवाई माधोपुर वन मंडल में 934.92 वर्ग किमी और करौली वन मंडल में 765.30 वर्ग किमी वन क्षेत्र स्थित है। 1,700.22 वर्ग किमी क्षेत्र में से 1,113.36 वर्ग किमी क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट घोषित किया गया है। वहीं 297.92 वर्ग किमी क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा बफर क्षेत्र घोषित किया गया है।

रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जैव विविधता

रणथंभौर टाइगर रिजर्व में विभिन्न प्रजातियों के वन्य जीव एवं वनस्पति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। रणथंभौर वन क्षेत्र की जैव विविधता के कारण यहां बाघों एवं अन्य वन्यजीवों को स्वच्छंद विचरण करते हुए देखा जा सकता है। यहां बिल्ली परिवार की 6 प्रजातियां बाघ, तेंदुआ, केराकल, जंगली बिल्ली, रेगिस्तानी बिल्ली और रस्टी स्पॉटेड बिल्लियाँ पाई जाती हैं। वहीं डॉग परिवार की तीन प्रजातियां लकडबग्गा, भेड़िया और सियार पाई जाती हैं।

नेवले परिवार की दो प्रजातियां इंडियन धूसर नेवला और रूड्डी नेवला हैं। इसमें स्तनधारियों की 38 प्रजातियां हैं जिनमें भालू, चीतल, सांभर, चिंकारा, नीलगाय, जंगली सूअर, सेही, खरगोश आदि प्रमुख हैं। पक्षियों की 315 प्रजातियां हैं जिनमें एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, इंडियन स्कीमर, पोचार्ड, आउल्स, डार्टर, स्ट्रोक आदि प्रमुखता से देखे जा सकते हैं। सरीसृपों की 35 प्रजातियां हैं जिनमें कछुआ, मगरमच्छ, कोबरा, क्रेट, वाइपर (रसेल, सॉ स्केल), रैट स्नेक, पाइथन, ट्रिंकेट, चेकर्ड कीलबैक, कैट स्नेक आदि शामिल हैं।

इसके अलावा पौधों की 402 प्रजातियां यहां मिलती हैं जिनमें धोंक, सालर, खैर, चिरोंज, तेंदू, कचनार, बेर, कदम, बांस, छीला, धामण घास, खस घास आदि महत्वपूर्ण हैं।

दुनिया के हर कोने से आते हैं पर्यटक

रणथंभौर टाइगर रिजर्व 1 अक्टूबर से 30 जून तक पर्यटकों के प्रवेश हेतु खुला रहता है। मानसून काल में जोन छह से 10 में सफारी चालू रहती है। यहां पूरी दुनिया के पर्यटक आते हैं और अप्रैल 2022 से मई 2023 तक 6 लाख 57 हजार 764 पर्यटकों ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व क्षेत्र का भ्रमण किया है। इनमें 1 लाख 196 विदेशी पर्यटक तथा 5 लाख 57 हजार 568 देशी पर्यटक शामिल हैं।

रणथंभौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर में सफारी के लिए कुल 10 जोन निर्धारित हैं। जोन एक से पांच तक कोर एरिया और छह से 10 तक बफर एरिया कहलाता है। जोन एक से पांच तक के लिए 138 नेचर गाइड जबकि जोन छह से 10 तक 48 ईडीसी गाइड उपलब्ध हैं। इन जोनों में सफारी के लिए 269 जिप्सी एवं 286 कैंटर पंजीकृत हैं।

सुरक्षा व्यवस्था

आरटीआर एक में टाइगर मॉनिटरिंग एवं वन व वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित कार्य दैनिक ट्रैकिंग रिपोर्ट, पीआईपी कार्य एक महीने में तीन बार किए जाते हैं। कैमरा ट्रैप कार्य के अंतर्गत सतत कैमरा ट्रैप लगाए जाते है जिसके आधार पर टाइगर का इलका तय होता है।

मॉनिटरिंग कार्य-प्रत्येक टाइगर रिजर्व में एनटीसीए (नेशनल टाइगर कंर्जवेशन अथॉरिटी) के प्रोटोकॉल के अनुसार एक वर्ष मे दो बार फेज - IV मॉनिटरिंग (विंटर एवं समर) करवाई जानी चाहिए। फेज- IV मॉनिटरिंग के अंतर्गत कैमरा ट्रैप मॉनिटरिंग कार्य कार्निवोरसाइन सर्वे एवं लाइन ट्रांसेक्ट सर्वे किया जाता है। मांसाहारी जानवरों की उपस्थिति के चिह्न दर्ज करने के लिए साइन सर्वे तथा शाकाहारी की अनुमानित संख्या का पता लगाने के लिए लाइन ट्रांजेक्ट सर्वे किया जाता है।

परियोजना क्षेत्र अंतर्गत आवश्यकतानुसार रात्रिकालीन गश्त की जाती है। परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत संवेदनशील क्षेत्र में विशेष टीमों के द्वारा रात्रिकालीन गश्त का कार्य किया जाता है। परियोजना क्षेत्र में निगरानी कैमरा लगवाए गए हैं जिनके द्वारा 24X7 निगरानी एवं सुरक्षा का कार्य किया जाता है। विभिन्न वन्य जीवों का रेस्क्यू कार्य, वन्य जीव अपराधों पर नियंत्रण, परियोजना क्षेत्र की परिधि पर बसे गांव के लोगों को जागरूक करने जैसे कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाते हैं। •

पर्यटकों को सम्मोहन पाश में बांधता

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान

प्रकाश चंद्र शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार

ऐसे तो भौगोलिक विविधताओं से अटी पड़ी धोरां री धरती राजस्थान में देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन स्थलों का टोटा नहीं है। एक ही प्रदेश में पहाड़ी, पठारी और मरुस्थलीय भूमि का समावेश, धरती की गोद से लेकर ऊंचे पहाड़ों पर बने ऐतिहासिक दुर्ग और विभिन्न अंचलों का पहनावा, बोली-भाषा व खानपान यहां आने वाले किसी भी पर्यटक के मस्तिष्क में स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए पर्याप्त हैं।

राज्य में चारों दिशाओं में स्थित पर्यटन स्थल अपना महत्व रखते हैं लेकिन पूर्वी राजस्थान में भरतपुर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं ऐतिहासिक दुर्ग विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करते हैं। इन्हें देखने के लिए आने वाले पर्यटक प्राकृतिक छटा को देख इस कदर सम्मोहित हो जाते हैं कि उनका बार-बार यहां आने का मन करता है। भरतपुर स्थित लोहागढ़ का किला भी अपने परकोटे से उस राष्ट्रीय केवलादेव पक्षी अभयारण्य को हर पल निहारता रहता है, जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है और जहां संसार के कोने-कोने से विभिन्न प्रजातियों के पक्षी बसेरा कर अपना कुनबा भी बढ़ाते हैं।

राजस्थान के पूर्वी सिंहद्वार और लोहागढ़ कहे जाने वाले भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 'घना' के नाम से भी जाना जाता है।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1956 में रक्षित वन घोषित किया गया एवं 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप घोषित किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर को वर्ष 1981 में 'रामसर साइट' घोषित किया गया था। वर्ष 1985 में इसे विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया। यह राजस्थान की एक मात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर है।

यह राष्ट्रीय उद्यान 28.73 वर्ग किमी. में फैला हुआ है। इसमें 375 प्रकार की प्रजाति के पक्षी देखे जा सकते हैं तथा 372 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं।

राष्ट्रीय उद्यान में प्रति वर्ष लगभग 1.25 लाख देशी एवं विदेशी पर्यटक भ्रमण हेतु आते हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हजारों स्थानीय लोगों का रोजगार के जरिये इस राष्ट्रीय पार्क से जीवनयापन होता है।

राष्ट्रीय उद्यान में वर्षा के आगमन से स्थानीय जलीय पक्षी प्रजनन हेतु एकत्र होना प्रारंभ कर देते हैं, जिनकी लगभग 15 प्रजातियां इस राष्ट्रीय

उद्यान में प्रजनन करती हैं। इसके बाद अक्टूबर के अंत में अथवा नवंबर माह में विदेशी जलीय पक्षियों का आगमन प्रारंभ होता है। इनमें प्रमुख प्रजातियां चाइनीज कूट, कॉमन टील, शॉवलर, बारहैडैड ग्रीज, गडवाल, पिनटेल, मैलार्ड, व्हाइट आईड पोचार्ड, रेड क्रेस्टैड पौचार्ड, वीजियॉन, अनेक तरह के बाज, गिद्ध, फाल्कन, तथा उल्लू प्रजाति के प्रवासी पक्षी यहां की छोटी-छोटी झीलों में पर्यटकों के लिये आकर्षण का केंद्र बनने के साथ-साथ वन्य प्राणी -फोटोग्राफर्स एवं अनुसंधान कर्ताओं के लिये विशिष्ट महत्व रखते हैं।

वर्ष 2009-10 में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देश से राष्ट्रीय उद्यान को पांचना बांध से गंभीर नदी के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया गया।

राष्ट्रीय उद्यान की सभी वन सुरक्षा चौकियों में सौर ऊर्जा से चलित लालटेन, पंखा, सर्च लाइट एवं वायरलैस चार्जिंग प्वाइंट की सुविधा प्रदान की गई है। गर्मी के मौसम में वन्यजीवों को पेयजल की सुविधा हेतु चार सौर ऊर्जा से चलित वाटर पम्पसैट लगाए गए हैं, जो पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त हैं।

हाल में केवलादेव नेशनल पार्क में मैन्युअल रिक्शा के स्थान पर ई-रिक्शा का संचालन शुरू किया गया है। इससे न सिर्फ पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा बल्कि रिक्शा राइडर्स की भी मेहनत बचेगी तथा ये लोग पर्यटकों को और भी बेहतर तरीके से पार्क के बारे में बता पाएंगे। पार्क में पहले मिलने वाली एवं वेटलैंड स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया जाना भी मैनेजमेंट प्लान में प्रस्तावित है। इससे पार्क में बेहतर इकोलॉजिकल बैलेंस बनेगा और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी।

रिसर्च को बढ़ावा देने की दृष्टि से कुछ डिग्गियों का भी निर्माण किया गया है ताकि पार्क में आ रहे भिन्न स्रोतों से पानी को एकत्रित करके भिन्न पादपों तथा उसमें पाए जाने वाले जलीय जंतुओं के बारे में डाटा एकत्रित

किया जा सके। इससे प्रबंधन में बेहतर दीर्घकालिक परिणाम मिलेंगे।

जूलीफ्लोरा हटाने का कार्य भी किया जा रहा है। इससे पार्क में मिलने वाली प्राकृतिक घास एवं वृक्षों को बढ़ने का मौका मिलेगा तथा पक्षियों को भी नया आशियाना बनाने में मदद मिलेगी। ग्रासलैंड डेवलपमेंट से पार्क में विचरण करने वाले शाकाहारी प्रजाति जैसे कि चीतल, सांभर आदि को भी एक बेहतर आवास मिलेगा। इससे यहां की जैव विविधता और समृद्ध होगी।

पार्क की अतुल्य धरोहर एवं पक्षियों की विभिन्नता को दर्शाने के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर का कार्य भी प्रगति पर है। इससे पर्यटकों को प्राकृतिक तकनीकी एवं मॉडल्स के माध्यम से इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में और अधिक जानकारी दी जा सकेगी। इससे न सिर्फ बेहतर तरह से चीज़ों को समझाया जा सकेगा बल्कि जन चेतना को अगले स्तर में पहुंचा कर लोगों को पार्क के बारे में और भी जागरूक किया जा सकेगा। •

सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य

जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम संगम

नवधा परदेशी
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

सागवान के वन, आर्द्र भूमि, बारहमासी जल धाराएं, सौम्य अविरल पहाड़, प्राकृतिक गहरी घाटियां और सागवान के मिश्रित वन, तेंदुआ और उड़न गिलहरी दक्षिणी राजस्थान में स्थित प्रतापगढ़ जिले को आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। प्रतापगढ़ जिले में लगभग 1 लाख 57 हजार हेक्टेयर पर प्रादेशिक वनमंडल वन क्षेत्र और सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य के तहत लगभग 42 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा, उसे सहेजती जनजातियां इस क्षेत्र को प्रकृति प्रेमियों के लिए और अधिक आकर्षक बना देती है। सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य इस क्षेत्र के प्रमुख आकर्षण में से एक है।

यह अभयारण्य उदयपुर-प्रतापगढ़ राज्य राजमार्ग पर स्थित है। यहां आने के लिए निकटतम हवाई अड्डा महाराणा प्रताप (डबोक) हवाई अड्डा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन हैं। यहां सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। प्रकृति-प्रेमियों के बीच वनस्पतियों और पशु-पक्षियों की विविधता से भरपूर यह अभयारण्य उत्तर भारत के अनोखे अभयारण्य के रूप में लोकप्रिय होने की अनंत संभावनाएं पेश करता है।

विविधता का केंद्र है यह अभयारण्य

अभयारण्य राजस्थान के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित है, जहां भारत की तीन पर्वतमालाएं अरावली, विंध्याचल और मालवा का पठार आपस में मिल कर ऊंचे सागवान वनों की उत्तर-पश्चिमी सीमा बनाते हैं। यहां बहती जाखम नदी गर्मियों में भी इसे आकर्षक बनाए रखती है। यहां सागवान, सालर, तेंदू, आंवला, बांस और बेल आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। यहां बहने वाली नदियों में जाखम और करमोई नदी प्रमुख हैं।

सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य में उड़न गिलहरी, तेंदुआ, लकड़बग्घा, सियार, जंगली बिल्ली, चार सींग वाले मृग, भारतीय पेंगोलिन और नीलगाय आदि प्रमुख वन्यजीव हैं। अभयारण्य का सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट जानवर उड़न गिलहरी है, जिसे रात के दौरान पेड़ों के बीच ग्लाइडिंग करते आसानी से देखा जा सकता है। उड़न गिलहरियों को स्थानीय भाषा में आशोवा नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम रेड फ्लाइंग स्किवरल पेटोरिस्टा एल्बी वेंटर है।

यह अभयारण्य चैसिंगा के प्रमुख स्थलों में से एक है। यह चैसिंगा की जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। चैसिंगा एंटी लॉप प्रजाति का दुर्लभतम वन्य जीव है जिसे स्थानीय भाषा में भेडल कहा जाता है। यहां पेंगोलिन जैसे दुर्लभ वन्यजीव के साथ-साथ आर्किड एवं विशाल वृक्षीय मकड़ियां भी पाई गई हैं। भारत के कई भागों से कई प्रजातियों के पक्षी प्रजनन के लिए यहां माइग्रेट करते हैं।

आरामपुरा अतिथि गृह

वन विभाग द्वारा संचालित आरामपुरा अतिथि गृह अभयारण्य के प्रवेश द्वारों में से एक है। यहां विश्राम कर आप प्रकृति के सुकून के मध्य वन्यजीवों

को देख सकते हैं। यह प्वॉइंट उड़न गिलहरी को देखने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। यह आरामपुरा प्रकृति के अलावा धार्मिक दृष्टिकोण से भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस आरामपुरा का जुड़ाव पौराणिक घटनाओं से माना जाता है। यह मान्यता है कि सीतामाता वनवास की अवधि के दौरान यहीं रही थी।

आकर्षक है अभयारण्य की जैव विविधता

सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य में सागवान, आम, महुआ, सफेद धोंक, चिरौंजी के वन भी पाए जाते हैं। यहां लीया नामक एक कंदीय पौधा भी पाया जाता है। अन्य वृक्षों में यहां आंवला, इमली, बेर, बरगद, बिजपत्ता, सालर, गूलर आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। सीतामाता औषधीय पौधों के लिए भी जाना जाता है। मुख्य औषधीय पौधों में चिरौंजी, जामुन, मूसली आदि पाए जाते हैं।

कई प्रजाति के जीव-जंतुओं की आश्रय स्थली

सीतामाता वन्यजीवों के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण अभयारण्यों में से एक है। यहां स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों, मछलियों और उभयचरों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह अभयारण्य उड़न गिलहरी, तेंदुआ और चैसिंगामृग और पेंगोलिन के लिए जाना जाता है। साथ ही यहां बिल खोदने वाले मेंढक और वृक्षारोही सर्प भी पाए जाते हैं।

सीतामाता का मंदिर है आस्था का बड़ा केंद्र

अभयारण्य में स्थित सीतामाता का ऐतिहासिक मंदिर

सीतामाता अभयारण्य जहां एक ओर इको-टूरिज्म के लिहाज से राज्य का एक महत्वपूर्ण स्थल है, वहीं कई प्रकार की धार्मिक मान्यता भी अपने अंदर समेटे हुए है। अभयारण्य आने वाले सैलानी सीतामाता मंदिर तक अवश्य आते हैं। कई किलोमीटर पैदल चलने और फिर कई सीढ़ियां चढ़ने के बाद दो पहाड़ों के मध्य सीतामाता का ऐतिहासिक मंदिर आता है। यहां दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहां से सीतामाता अभयारण्य का एक विहंगम दृश्य भी दिखाई देता है। •

पर्यटन का नया आयाम ईको टूरिज्म

■ हेमेंद्र सिंह
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

राजस्थान पर्यावरण परिदृश्यों की विविधता के साथ-साथ पर्यटन संसाधनों से संपन्न प्रदेश है। यहां के अतीत को परिलक्षित करते हुए विभिन्न ऐतिहासिक दुर्ग, महल, मंदिर व सुरम्य, समृद्धि को संजोए हुए लोक-संस्कृति, लोक कला, लोक जीवन प्रदेश को पर्यटन के मानचित्र पर विशेष पहचान के रूप में उकेरते हैं। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य में एक ओर प्राचीनतम अरावली पर्वत श्रृंखला है तो दूसरी ओर सुनहरा थार मरुस्थल है। पर्वतीय क्षेत्रों में घने जंगल हैं तो मरुभूमि में गडीसर, लूणकरसर आदि झीलें हैं।

वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों के रूप में रणथंभौर, सरिस्का, रामगढ़ विषधारी आदि स्थल हैं तो वहीं, केवलादेव, सांभर, खींचन आदि प्रवासी पक्षियों के शरण-स्थल भी यहां मौजूद हैं। इन मरु-पर्वत-जल पारिस्थितिकी तंत्रों की नैसर्गिक जैव विविधता प्रदेश को ईको- टूरिज्म की व्यापक संभावनाएं प्रदान करती हैं।

ईको ट्यूरिज्म का अर्थ है प्राकृतिक सौंदर्य के करीब जाना। ईको टूरिज्म प्राकृतिक क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के साथ बढ़ावा देने का माध्यम है, जिसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाती है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ नवीन ईको टूरिज्म पॉलिसी 2021 लागू करने के साथ ही जंगल सफारी, लव कुश वाटिकाएं विकसित करने आदि नीतिगत फैसले किए गए हैं।

ईको टूरिज्म पॉलिसी 2021

राज्य सरकार ने पारिस्थितिकी संरक्षण एवं स्थानीय समुदाय के विकास को केंद्र में रखकर ईको टूरिज्म पॉलिसी का मसौदा तैयार किया, जिसे जुलाई 2021 में लागू किया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संपदाओं का सरंक्षण करना, स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों का सृजन कर उन्हें सशक्त करना है। इस नीति में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए

प्राकृतिक क्षेत्रों ट्रैकिंग, नेचर वॉक, बर्ड एवं वाइल्ड लाइफ वॉचिंग, हाइकिंग, कैंपिंग, जंगल सफारी आदि गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गई है। वहीं स्थानीय समुदायों की सहभागिता एवं आर्थिक अभिवृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर कार्ययोजना तैयार की जाती है ताकि स्थानीय विशेषताओं एवं आवश्यकताओं का समावेश किया जा सके।

राजस्थान पारिस्थितिक पर्यटन नीति, 2021 को वन विभाग, राजस्थान सरकार एवं राजस्थान वन विकास निगम द्वारा लागू किया गया। साथ ही इसके ब्रांडिंग, प्रचार आदि के लिए पर्यटन विभाग को प्रायोजित किया गया।

वहीं नीति के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था के रूप में राजस्थान ईको टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी का सलाहकार एवं पर्यवेक्षक संस्था के रूप में गठन एवं राजस्थान फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा स्थानीय समुदायों के सहयोग से पर्यटन इकाइयों का संचालन प्रावधान किया गया है। वहीं जिला स्तर पर जिला ईको टूरिज्म कमेटी को प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक जैव विविधता का संरक्षण, प्रबंधन एवं स्थानीय समुदाय की आर्थिक अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना लागू करने का प्रावधान है।

पर्यावरण पर्यटन नीति स्थानीय समुदायों को पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन से जुड़ने के लिए प्रेरित करने के साथ ही प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में आय के नए अवसर के सृजन का माध्यम बन रही है।

ईको ट्यूरिज्म साइट्स का विकास

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में इकोट्यूरिज्म साइट्स का निरंतर विकास किया जा रहा है। हाल में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस - 2023 पर पर्यटकों के लिए जंगल सफारी सुविधा का विस्तार करते हुए उदयपुर के जयसमंद अभयारण्य एवं झुंझुनूं के बीड कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी की शुरुआत की गई।

12 जिलों के वन क्षेत्रों में शुरु होंगी रोमांचकारी गतिविधियां

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा की अनुपालना में वन क्षेत्रों में हाइकिंग, ट्रेकिंग, कैंपिंग एवं अन्य रोमांचकारी गतिविधियों के लिए 9.74 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से प्रदेश के 12 जिलों के विभिन्न वन क्षेत्रों में गतिविधियां शुरू की जाएंगी। इनमें अजमेर के तारागढ़, अलवर के चूहड़सिद्ध, बारां के रामगढ़ क्रेटर, भरतपुर के ब्रज चौरासी क्षेत्र, भीलवाड़ा के हमीरगढ़ व मंगरोप, चित्तौड़गढ़ के हथिनी औदी व मेनाल वाटरफाल, दौसा के मेढ़ा व गोलमेल, जयपुर के बुचारा व कचरावाला, सिरोही के मातरमाता, सीकर के बालेश्वर, प्रतापगढ़ के धूणीमाता व कमलेश्वर महादेव तथा उदयपुर के नाल सांडोल क्षेत्र शामिल हैं।

प्रत्येक जिले में स्थापित हो रही लव कुश वाटिकाएं

प्रदेश में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा में प्रत्येक जिले में लवकुश वाटिका के विकास घोषणा की गई। पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से इन वाटिकाओं में वन एवं वन्यजीवों से संबंधित मॉडल स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही यहां ईको ट्रेल पथों का निर्माण और प्रदर्शनी के लिए जगह बनेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त वाटिका विकसित करने की घोषणा की गई है, जिसके लिए 66 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। •

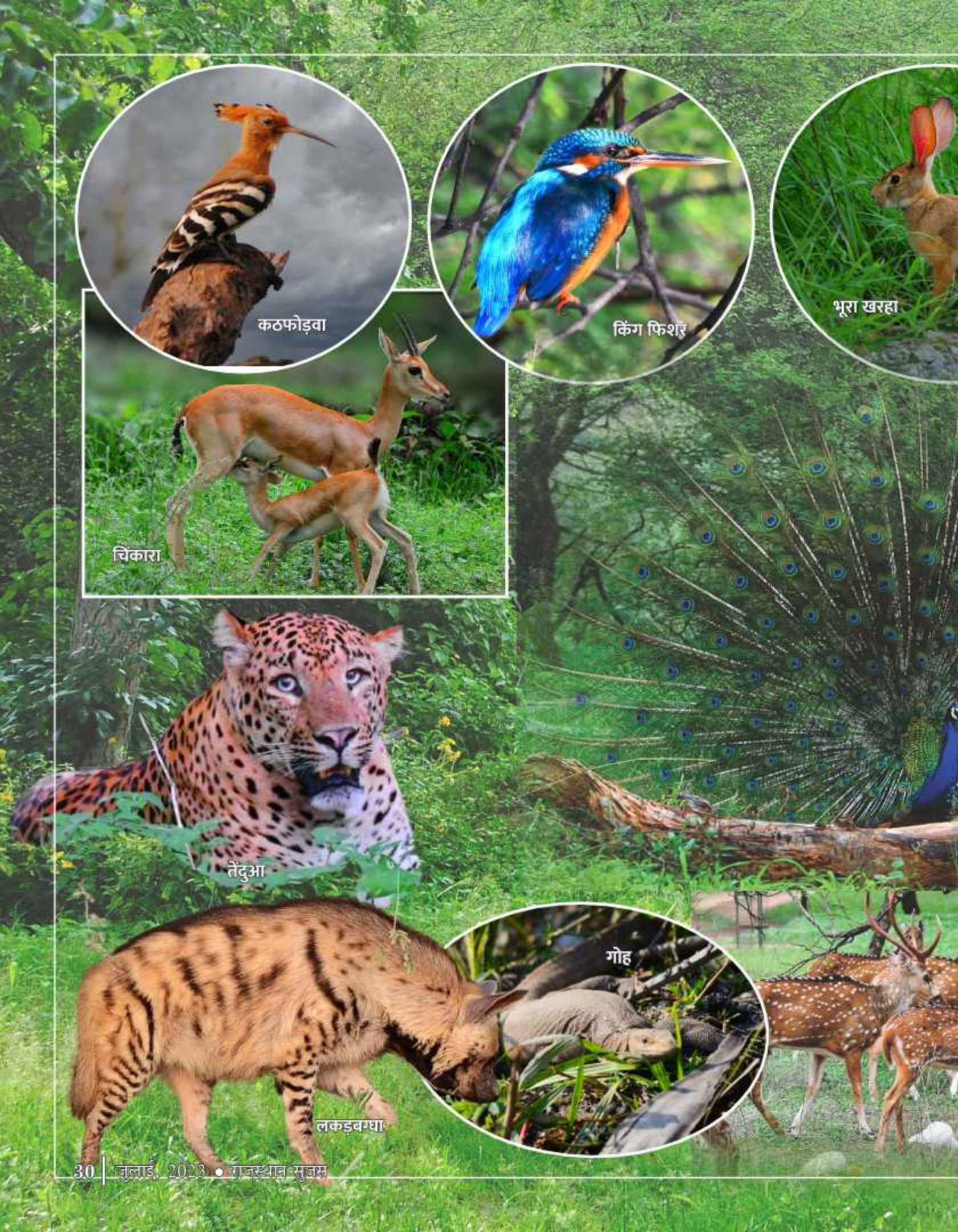
कठफोड़वा
किंग फिशर
भूरा खरहा
चिंकारा
तेंदुआ
गोह
लकड़बग्घा

रेड काइट
कृष्ण मृग
गौरया
मोर
बाघ
तीतर
चित्तीदार हिरण
नील गाय

विदेशी परिंदों के आतिथ्य के लिए मशहूर मारवाड़

जहां हर साल सजते हैं कुरजां के डेरे

आकांक्षा पालावत
जनसंपर्क अधिकारी

बहुआयामी पर्यटन विकास के मौजूदा दौर में बर्ड टूरिज्म की अपार संभावनाएं साकार हो रही हैं। इस दृष्टि से हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले विदेशी पक्षियों की वजह से भारत के कई क्षेत्रों में पक्षी पर्यटन के क्षेत्र में नए-नए आयाम स्थापित होने लगे हैं। आक्षितिज पसरी जलराशि और ऊंचे-ऊंचे पर्वतों के कठिन रास्तों को पार करते हुए विभिन्न प्रजातियों के आकर्षक पक्षियों का डेरा देश के विभिन्न क्षेत्रों, जलाशयों के इर्द-गिर्द बना रहता है।

ये क्षेत्र इन्हें सुरक्षित माहौल के साथ ही अनुकूलतम आबोहवा से निर्बाध जीवन का संगीत देने के लिए इतने अधिक माकूल हैं कि ये मेहमान हर साल भारत आकर विभिन्न क्षेत्रों में डेरा डालते और विचरण करते हुए पोषण भी पाते हैं और जलीय क्रीड़ाओं के अविस्मरणीय आनंद का अनुभव भी करते हैं। यह सब उन्हें इतना अधिक रास आ गया है कि ये विदेशी मेहमान भारत की मेहमानवाजी को भूल नहीं पाते और हर साल यहां खींचे चले आते हैं।

पक्षियों के इस अनूठे और रहस्यों भरे जीवन व्यवहार तथा ठहराव ने प्रदेश में बर्ड टूरिज्म को नई दिशा और दृष्टि दी है। इससे पक्षियों पर शोध करने वालों, पक्षी प्रेमियों तथा परिंदों के संसार को निहारने वाले जिज्ञासुओं का आवागमन भी बढ़ने लगा है। इसका सीधा सकारात्मक प्रभाव पर्यटन विकास पर पड़ा है और बर्ड टूरिज्म दिनों-दिन विस्तार पाता जा रहा है।

हजारों किमी दूर जाकर शीतकालीन प्रवास

कुरजां पक्षी मध्य यूरेशिया, काला सागर से मंगोलिया व पूर्वोत्तर चीन में निवास करते हैं। इन क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते भोजन की अनुपलब्धता के कारण ये शीतकालीन प्रवास पर भारत आ जाते हैं। साइबेरिया में हर साल सितंबर के दिनों में शुरू हो जाने वाली इस बर्फबारी से बचने के लिए यह पक्षी सर्दियों के प्रवास पर भारत, मंगोलिया, पाकिस्तान समेत कई देशों में जाता है।

लोक जीवन से गहरा नाता

विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के हर साल भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आगमन और कई-कई माहों तक यहीं पड़ाव डाले रहने की परंपरा बनी हुई है। इन्हीं में कुरजां पक्षी प्रमुख है जो यहां के लोकजीवन से गहरा रिश्ता रखता है।

विदेशी मेहमान कुरजाओं और जनमानस एवं परिवेश के बीच का रिश्ता ही ऐसा बना हुआ है कि इसे मेहमानवाजी के साथ लोकगीतों में भी वर्णित किया हुआ है। भारतीय संस्कृति, धर्म और प्राचीन साहित्य की परंपराओं से लेकर वर्तमान लोक लहरियों तक में इसका बहुत महत्व रहा है।

पश्चिमी राजस्थान में बेहतर माहौल और खान-पान की सहज उपलब्धता की वजह से विभिन्न जल स्रोतों के सन्निकट हर साल डेरा डालने वाले कुरजां पक्षियों के कारण से इस क्षेत्र में बर्ड टूरिज्म का नवीन एवं सुनहरा परिदृश्य सामने आया है।

मारवाड़ क्षेत्र बहुत पुराने समय से कुरजां के आतिथ्य के लिए मशहूर रहा है जहां हर साल विभिन्न क्षेत्रों में कुरजां के डेरे सजते हैं। तब के दिनों में इन क्षेत्रों का आकर्षण बहुगुणित होकर हर किसी को अपनी ओर खींचता हुआ दिखता है।

कुरजां के लिए अभयारण्य ही है खींचन

कुरजां के नाम से जगविख्यात साइबेरियन क्रेन जोधपुर जिले के खींचन, बाप एवं जांबा के साथ ही मारवाड़ के विभिन्न जलस्रोतों के आस-पास हर साल आकर अपना अस्थायी संसार बसा लेती हैं। इनमें जोधपुर जिले का खींचन गांव प्रसिद्ध है जहां हर साल हजारों की संख्या में कुरजां का पड़ाव हर किसी को मोहित करता रहता है।

फलौदी से मात्र 4 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव का नाम सामने आते ही पक्षियों का अनूठा सुनहरा संसार रील की तरह सामने चलता हुआ प्रतीत होता है। अब तो खींचन गांव और कुरजां एक-दूसरे के पर्याय ही हो चले हैं। कुरजां पड़ाव स्थल के रूप में खींचन ने पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है।

कुरजां पक्षियों के प्रवास का जिक्र पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से होने के बाद इस इलाके में हर साल कुरजां के पड़ाव के दिनों में पर्यटकों का तांता लगा रहता है। कुरजां की बदौलत बर्ड टूरिज्म लगातार परवान पर है।

कई समंदरों और पर्वत श्रेणियों को पार कर आते हैं कुरजां

आमतौर पर हजारों कुरजां पक्षी सितंबर के पहले सप्ताह से साइबेरिया से उड़ान भरकर लगभग 5,500 किलोमीटर तक सफर तय कर खींचन पहुंचते हैं। खींचन के जलस्रोतों के किनारे अस्थायी पड़ाव बसाते हैं। नवंबर तक इनकी संख्या 25 हजार तक पहुंच जाती है। मार्च में ये अपना प्रवास समाप्त कर यहां से प्रस्थान कर जाते हैं।

हाड़ कंपा देने वाले शीत देशों और क्षेत्रों में अपने अस्तित्व पर मंडराने वाले खतरों से बचने और अपने जीवन को बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की तलाश में हजारों किलोमीटर दूर से कुरजां भारत में आती हैं और कुछ माह रहने के बाद मार्च आते-आते अपने-अपने क्षेत्रों की ओर लौट जाती हैं।

आबोहवा से लेकर सुरक्षा तक तमाम अनुकूलताएं खींच लाती हैं यहां

कुरजां पक्षियों को साइबेरिया में डेमोसाइल क्रेन के रूप में जाना जाता है, लेकिन भारत में इन पक्षियों को कुरजां के रूप में जाना जाता है। इन

पक्षियों का मुख्य भोजन ज्वार, नमक, चूना पत्थर और खारा पानी है।

इन पक्षियों के खींचन में पड़ाव को लेकर मुख्य वजह यह है कि उन्हें उनका पसंदीदा भोजन यहां भरपूर मात्रा में मिलता है। इसका मूल कारण यह है कि इस गांव के पानी में खारापन होने से नमक की मात्रा पाई जाती है। इस क्षेत्र में नमक उत्पादन भारी मात्रा में होता है। यहां चूना पत्थर भी पाया जाता है। कुरजां को यह सब खूब पसंद आता है।

ग्रामीणों का स्नेहपूर्ण आत्मीय लगाव

गांव के लोग भी इन पक्षियों के प्रति जबरदस्त भावनात्मक लगाव रखते हैं। इन विदेशी परिंदों को मेहमान की तरह आतिथ्य सत्कार देने में यहां

के लोग कभी पीछे नहीं रहते।

ग्रामीण इनके लिए सुरक्षित एवं संरक्षित अनुकूल माहौल, बेहतर जीवनयापन के अवसरों की उपलब्धता और खान-पान के प्रबंध से लेकर हर तरह से सुकून देने में समर्पित भाव से जुटे रहते हैं।इस क्षेत्र के समृद्ध ग्रामीण इन पक्षियों के लिए ज्वार का प्रबंध भी करते हैं। इससे जितने दिन कुरजां यहां रहती हैं उन्हें दाना-पानी और भोजनादि में कोई समस्या नहीं आती। शर्मीले मिजाज के ये पक्षी खींचन में खुद को हर तरह से सुरक्षित एवं आनंदित महसूस करते हैं।

पक्षी प्रेम का अनुकरणीय आदर्श

हर साल हजारों की तादाद में आने वाले इन पक्षियों के लिए चुग्गे (दाने) की व्यवस्था ग्रामीणों द्वारा सामाजिक स्तर पर की जाती है, जिसमें सालाना लाखों रुपये खर्च होते हैं। लेकिन ग्रामीणों का दिली लगाव एवं आत्मीयता सब मुश्किलों पर भारी पड़ती है। पक्षियों के प्रति स्नेह और सुरक्षा का आलम यह है कि पूरा का पूरा खींचन गांव ही इन मेहमान परिंदों की रक्षा और उन्हें खिलाने की जिम्मेदारी निभाता रहा है। यही कारण है कि कुरजां को यहां का सुरक्षित माहौल और आतिथ्य इतना पसंद आ गया है कि वे यहां आना कभी नहीं भूलतीं।

स्थानीय प्रशासन भी संवेदनशील

इन पक्षियों के कारण दूर-दूर तक विख्यात खींचन क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा को लेकर न केवल क्षेत्रवासी बल्कि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी इनके प्रति पूर्ण संवेदनशीलता रखते हैं। इसके लिए स्थानीय ग्राम पंचायत को एक पक्षी एंबुलेंस भी सौंपी हुई है।

पक्षी पर्यटन के बहुआयामी प्रयास अपेक्षित

हजारों की संख्या में कुरजां पक्षियों की मौजूदगी ने पश्चिमी राजस्थान में बर्ड टूरिज्म की दिशा में नए द्वार खोले हैं। कुरजां के डेरों वाले जलाशयों

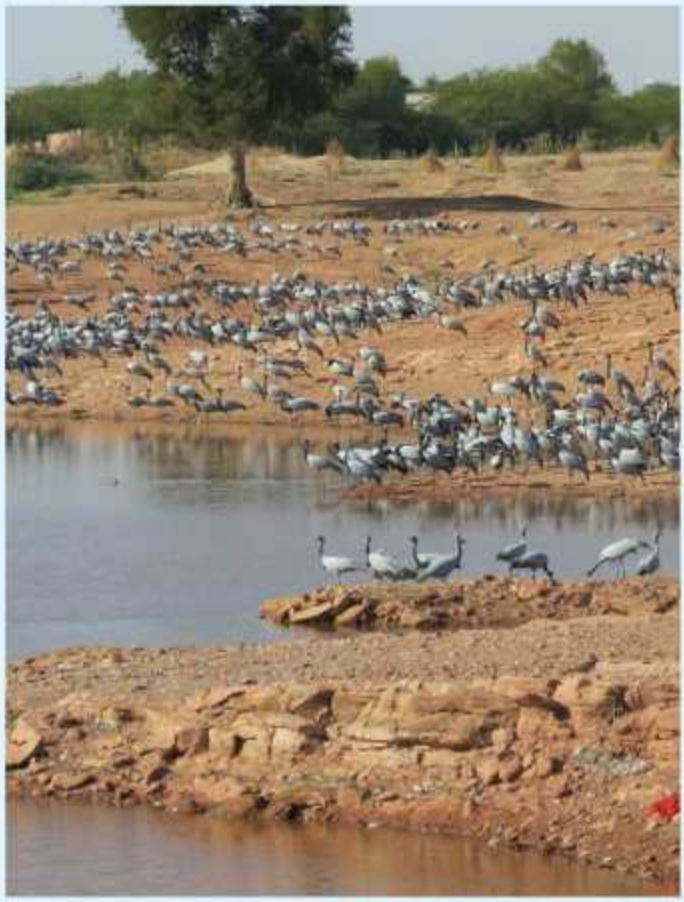

और क्षेत्रों तक पहुंच मार्गों पर आवागमन सुविधाओं को विकसित करने के साथ ही इनके व्यापक प्रचार-प्रसार पर योजनाबद्ध रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इसमे पक्षी प्रेमियों, पर्यटन छायाकारों और पर्यटकों का आकर्षण बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं और इससे क्षेत्र में पर्यटन विकास को सम्बल प्राप्त होगा।

परिंदे भी पाते हैं इस धरा पर सुकून

भारत के वसुधैव कुटुम्बकम और अतिथि देवो भव: की पुरातन परंपरा को दुनिया भर का मानव समुदाय ही नहीं बल्कि परिंदों का संसार भी मानता और स्वीकारता है, तभी दुनिया के कोने-कोने से विभिन्न प्रजातियों के पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय कर भारत आते हैं और यहां के आतिथ्य से अभिभूत होकर लौटते हैं। जाने कितने युगों से जारी रहने वाला यह क्रम आज भी बना हुआ है जो हमारी मेहमानवाजी परंपरा का गौरवगान कर रहा है। •

44 Notified Wetlands in Rajasthan

Concept of Better Wildlife Will Come True with Better Ecosystem

Dr Amrita Katara
Assistant Public Relation Officer

The Government of Rajasthan is determined to manage better wildlife along with better human life and continuous efforts are being made in this direction. Taking a historic step in the field of conservation and integrated management of wetlands, the Government of Rajasthan recently has released a list of total 44 notified wetlands in 19 districts of the state. Under which Baran district will have a maximum 12 wetlands.

The 44 wetlands would improve the ecological system in the state and a better food chain would be available for wildlife. Wetlands, which are known as the kidneys of the earth, play an important role in maintaining the natural balance, as well as in environmental protection, water harvesting and purification.

According to the notification issued by the Department of Environment and Climate Change, there will now be a total of 44 notified wetland areas in the state. As per the list Baran district include Eklera Sagar, Kotrapar Talab, Bethali Dam, Hinglot Dam, Utavali Dam, Sehrol Dam, Garda Talab, Niyana Talai, Nahargarh, Teja Ji Ki Talai, Pushkar Talab and Lhasi Dam.

Devi Kund Sagar and Sursagar in Bikaner. Naval Sagar Lake in Bundi. Mangalwad Talab, Kishan Kareri, Barwai Lake and in Chittorgarh Gambhiri Dam and Sabela Talab in Dungarpur. Kaylana and Surpura under Jodhpur district, Bird Sanctuary Kenwas under Kota, Kishore Sagar, Hanotia, in Nagaur district Didwana (Khalda), Lakhotia Talab and Lordia Talab in Pali district, Rajyawas and Raghav Sagar under Rajsamand district, Rewasa in Sikar district, Budhsagar, Bisalpur, Chandlai, Motisagar, Galvania, Tordi Sagar in Tonk district, Menar Talab Wetland Complex in Udaipur district. Chawandia in Bhilwara district, Kesariawad in Pratapgarh district, Lakherao Talab in Sirohi district. Bada Talab in Ajmer district, Rankhar in Jalore district and Badbela Talab in Jhalawar district.

The Activities Which are Prohibited

There will be a ban on any kind of encroachment in the wetland area and surrounding areas. There will be a ban on setting up any new industry and expansion of existing industries. Along with this, there will be a ban on the collection and disposal of solid, hazardous and e-waste. Food items given by common people to fish and migratory birds will be banned. Commercial mining, stone quarrying along with crushing units will also be banned. There will be an effective ban on any type of hunting. All commercial activities that emit pollution including activities that reduce the area and potential of wetlands will be prohibited. Also, any type of ground water extraction will be prohibited.

The Activities Which are Allowed

Fisheries, operation of boats, desilting, temporary construction, drainage of water for special purposes can be done in the wetlands area.

The Kidneys of the Landscape

Wetlands are known as the "Kidney of the Landscape" and "Biological Supermarket". These are such moist and marshy land, which is partially or completely filled with water throughout the year. Wetlands are ecosystems that absorb excess water during floods. Wetlands do this so that human habitation areas are saved from submerging. Not only this, by carbon absorption and increase in ground water level wetlands contribute significantly to environmental protection. •

ईको-टूरिज्म गतिविधियों से

पर्यटन मानचित्र पर उभर रहा चूरू

कुमार अजय
सहायक निदेशक, जनसंपर्क

ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य के काले हिरणों की अठखेलियों के लिए मशहूर चूरू जिला अब ईको-टूरिज्म गतिविधियों के चलते देश के पर्यटन मानचित्र पर अपनी अनूठी पहचान बना रहा है। राज्य सरकार की विभिन्न बजट घोषणाओं के अनुसार जिले में ईको-टूरिज्म में हो रहे विकास कार्य यहां की पर्यटन संभावनाओं को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। लोगों की आस्था के केंद्र और पौराणिक महत्व के स्थान तारानगर के श्याम पांडिया में राज्य सरकार की बजट घोषणा 2022-23 के मुताबिक लव कुश वाटिका का विकास किया गया है। यहां आकर्षक प्रवेश द्वार, गजिबो हट, जोहड़ के सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार, व्यू प्वाइंट निर्माण, इंटरलॉकिंग, सुलभ कॉम्प्लेक्स, फेंसिंग, ईको-ट्रेल निर्माण, ब्रिज, सीढ़ियों का सौंदर्यीकरण एवं नई सीढ़ियों का निर्माण, मुख्य द्वार, रेलिंग, तलाई निर्माण आदि कार्य कराए गए हैं।

इसी प्रकार बजट घोषणा 2023-24 की अनुपालना में चूरू जिले के प्रख्यात डूंगर बालाजी मंदिर सुजानगढ़ क्षेत्र में लव-कुश वाटिका विकसित की जा रही है। इस लव-कुश वाटिका को ईको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे ईको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। डूंगर बालाजी मंदिर में आने वाले श्रद्धालु लव-कुश वाटिका में आकर प्रकृति का आनंद ले पाएंगे। वाटिका में आकर्षक प्रवेश द्वार, जनसुविधाएं, झांपा (गोजिबो हट निर्माण), बच्चों के लिए झूले, पानी का तालाब, तलाई निर्माण, ब्रिज और व्यू प्वाइंट आदि का निर्माण करवाया जा रहा है। सुजानगढ़ में सालासर बालाजी, तालछापर अभयारण्य, डूंगर बालाजी, साईं बाबा मंदिर आदि यहां के खास पर्यटक स्थल हैं। इन स्थानों के अतिरिक्त लव-कुश वाटिका डूंगर बालाजी के पास खुलने से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के कारण तालछापर अभयारण्य के आसपास नए रिसोर्ट भी खुल रहे हैं। लव-कुश वाटिका में वन विभाग द्वारा विभिन्न प्रजातियों के पेड़ एवं पौधें लगाकर एक छोटा सा जंगल विकसित किया जाएगा, जिसमें लोग परिवार सहित ट्रेकिंग, वॉकिंग, बर्ड वॉचिंग के साथ-

साथ प्रकृति की गोद में समय व्यतीत कर पाएंगे।

तारानगर उपखंड मुख्यालय पर महात्मा गांधी औषधीय वन विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य बीड़ तारानगर वन क्षेत्र में पाए जाने वाले स्थानीय औषधीय प्रजाति के पौधों के संवर्धन हेतु औषधीय नर्सरी तथा लोगों का वनों से जुड़ाव करना है। बड़ी तादाद में शहर के लोग शाम-सवेरे वन में आते हैं। इसके अतिरिक्त वन विभाग द्वारा हरीतिमा बढ़ाने हेतु विभिन्न योजनाओं के सम्मिलन से ईको-टूरिज्म साइट विकसित की जा रही है। राजगढ़ में गांधी पार्क और ईको पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर लोगों में अभी से ही उत्साह देखा जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न बजट घोषणाओं की अनुपालना में ईको-टूरिज्म साइट रतननगर बीड़, ईको-टूरिज्म साइट राजगढ़ बीड़, तालछापर आदि में विकास कार्य कराए जा रहे हैं।

जिले में ईको-टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देने से भ्रमणकारियों में वन एवं वन्यजीवों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। चूरू जिला मुख्यालय स्थित नेचर पार्क अरबन फोरेस्ट्री के रूप में राज्य में एक उदाहरण बना है।

ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य

चूरू जिले के ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य में काले हिरणों की अठखेलियां अनायास ही दर्शकों का ध्यान खींचती हैं। अभयारण्य में चार हजार से अधिक काले हिरण हैं, जो देशी-विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। जैव विविधता से भरपूर इस अभयारण्य में काले हिरणों के अलावा लोमड़ी, नीलगाय, मरु लोमड़ी, चिंकारा, खरगोश, जंगली बिल्ली, मरु बिल्ली, जंगली सूअर आदि वन्यजीव हैं तथा प्रवासी पक्षियों के ठहराव का यह एक मुख्य केंद्र है। 300 से अधिक प्रजातियों के पक्षी यहां विभिन्न

मौसमों में देखे जा सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से अभयारण्य में आने वाले सैलानियों के लिए विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं और आने वाले समय में सुविधाओं तथा सांस्कृतिक व पर्यटन के विस्तार से लिए अब यहां के ओपन थिएटर को फिर से शुरू करने, स्टार गेजिंग, केमल सफारी, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए उत्पादों के विक्रय के लिए क्राफ्ट शॉप, कैफेटेरिया सहित विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

काले हिरण तालछापर अभयारण्य का मुख्य आकर्षण हैं। इसके अलावा यहां लोमड़ी, रोझ, चिंकारा, खरगोश, जंगली बिल्ली आदि पाए जाते हैं। वन्य जीवों के अलावा देशी-विदेशी पक्षियों के प्रवास स्थल के तौर पर यह अभयारण्य मशहूर है। यहां विभिन्न मौसमों में दिखाई देने वाली 200 से भी ज्यादा प्रजातियों में डेमोसिल क्रेन (कुरजां), हेरोन, काइट, ईगल, वल्चर, सैंडग्रूज, बी-ईटर, बबलर, किंगफिशर, साइक, ब्लैक विंगड स्टिल्ट, सनबर्ड, लार्कस आदि प्रमुख हैं।

यहां मिलने वाले सरीसृप वर्ग के जंतुओं में मुख्यतः गोह, सांडा, काला नाग, गिरगिट आदि हैं। तालछापर अभयारण्य में विभिन्न सुविधाएं सरकार की ओर से दी जा रही हैं। ताल छापर में वन विभाग का विश्राम गृह स्थित है जिसका रखरखाव वन विभाग द्वारा किया जाता है।

अभयारण्य में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एवं डेजर्ट ईको-सिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया गया है। पर्यटकों के ठहरने हेतु इनमें छह कमरों की सुविधा उपलब्ध है।

अभयारण्य में घूमने, निरीक्षण एवं गश्त हेतु कच्चा ट्रैक बना हुआ है। यहां एक ओपन एयर थिएटर बना हुआ है, जिसमें नियमित सांस्कृतिक गतिविधियां शुरू करने की कवायद चल रही है। यहां स्विस टेंट लगाया गया है तथा कैमल सफारी, क्राफ्ट शॉप आदि शुरू किए जा रहे हैं।

तालछापर में कृष्ण मृगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जसवंतगढ़ में कृष्ण मृगों हेतु लगभग 2,200 बीघा भूमि राजस्व विभाग से वन विभाग को आवंटित कर कृष्ण मृगों हेतु प्राकृतिक आवास विकसित करने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

यह स्थल न केवल वन्यजीवों, बल्कि प्रवासी पक्षियों हेतु वरदान साबित होगा। इससे स्थानीय पर्यटन तथा रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। •

पर्यावरणीय संवेदनशीलता की पाठशालाएं

लव-कुश वाटिकाएं

■ **विनय सोमपुरा**
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

राजस्थान प्राकृतिक विविधताओं और हेरिटेज के लिए देश-विदेश के पर्यटकों की खास पसंद है। हेरिटेज के साथ-साथ प्राकृतिक सौंदर्य भी प्रदेश में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यही वजह है कि पर्यटन के साथ-साथ राजस्थान सरकार पर्यावरण के प्रति आमजन को संवेदनशील बनाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। इसी का एक उदाहरण है प्रदेश के प्रत्येक जिले में विकसित की जा रही लव-कुश वाटिकाएं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती यह पहल पर्यावरण पर्यटन (Ecotourism) के साथ ही पर्यावरणीय संवेदनशीलता (Eco sensitivity) को बढ़ावा देने में भी मददगार साबित हो रही है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2022 में प्रदेश में ईको टूरिज्यम को बढ़ावा देने तथा आमजन की पर्यावरण के प्रति रुचि विकसित करने की मंशा से प्रत्येक जिले में लवकुश वाटिका स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। इसमें प्रत्येक जिले के लिए 2-2 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

हर जिले में तैयार हो रही लवकुश वाटिकाएं

मुख्यमंत्री बजट घोषणा की क्रियान्विति में राज्य के प्रत्येक जिले में लवकुश वाटिकाएं तैयार हो रही हैं। उदयपुर में शहर से सटे माछला मगरा वन क्षेत्र के 35 हेक्टेयर क्षेत्र को लव कुश वाटिका के रूप में विकसित किया गया है। इसी प्रकार आनासागर झील-अजमेर, चूहड़ सिद्ध घाटी अलवर, सवाई माता बांसवाड़ा, शाहबाद बारां, जूनापत्रसार बाड़मेर, मांडेरा रूंध भरतपुर, भड़क छत्रीखेड़ा भीलवाड़ा, जोड़बीड़ बीकानेर, भीमलत बूंदी, मोहन मगरी चित्तौड़गढ़, श्याम पांडिया तारानगर चूरू, गोल (मेन) दौसा, दमोह वाटरफॉल धौलपुर, रतनपुर बिछीवाड़ा डूंगरपुर, धन्नासार बरानी हनुमानगढ़, नईनाथ बांसखोह जयपुर, कनोई जैसलमेर, सुंधा माता जालौर, बड़बेला तालाब झालावाड़, मनसा माता झुंझुनूं, माचिया जोधपुर, कैलादेवी नेजर कैंप करौली, आवली रोजड़ी कोटा, गोगेलाव नागौर, खोबागुड़ा देसुरी पाली, गौतमेश्वर लालगढ़ प्रतापगढ, रूपनगर झीलवाड़ा राजसमंद, विजयगढ़ बौंली सवाईमाधोपुर, हर्ष पर्वत सीकर, राजल दाबेला सिरोही, 3 एमएसडी डाबला श्रीगंगानगर तथा बीसलपुर टोंक में लवकुश वाटिकाएं पर्यटकों और आमजन के लिए आकर्षक का केंद्र बनी हुई हैं।

प्रकृति की गोद में सुकून के पल

भाग-दौड़ भरे जीवन में प्रकृति की गोद में सुकून के दो पल मिल जाएं तो व्यक्ति तरोताजा हो जाता है। लवकुश वाटिकाएं आमजन को ऐसे ही आभास करा रही हैं। उदयपुर के माछला मगरा में तैयार की गई लवकुश वाटिका में जहां आमजन पाथ-वे, लक्ष्मण झूला वॉच टावर आदि के माध्यम से प्राकृतिक वातावरण में घूमने-फिरने और बैठने का आनंद ले पा रहे हैं वहीं किड्स प्ले एरिया बच्चों के आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। इसमें साहसिक गतिविधियों (Adventure Activities) की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर वनों में पाई जाने वाली वनस्पति भी विकसित की है। वहीं, चेकडैम और एनिकट बनाकर जल प्रबंधन एवं जल संचय का भी बंदोबस्त किया गया है। प्रत्येक जिले में वहां की पर्यावरणीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्य किए गए हैं।

शोधार्थियों के लिए भी सहायक

प्रदेश में विकसित की जा रही लवकुश वाटिकाएं अन्य वाटिकाओं से भिन्न हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कृत्रिम सजावट अथवा बाहर से लाई गई वनस्पति को विकसित करने के स्थान पर स्थानीय वानिकी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि ये वाटिकाएं संबंधित क्षेत्र की वानिकी परिस्थितियों के मॉडल के रूप में स्थापित हो सकें और पर्यटक व स्थानीय लोग भी उस क्षेत्र की वानिकी विशेषताओं से रूबरू हो सकें। वहीं वानिकी तंत्र के शोधार्थियों के लिए भी यह वाटिकाएं सहायक सिद्ध हो सकेंगी।

ताकि बढ़े वनों के प्रति संवेदनशीलता

लवकुश वाटिकाओं को विकसित करने के पीछे राज्य सरकार की मंशा वन एवं वन संपदा के प्रति आमजन को संवेदनशील बनाना भी है। इन वाटिकाओं में लोग वनों के मानव जीवन तथा जैव विविधता के लिए महत्व को भी समझ रहे हैं। खासकर बच्चों को वन संपदा से रूबरू होने तथा उनकी उपयोगिता को नजदीक से समझने का अवसर मिल रहा है। वाटिका में मौजूद वन विभाग के कार्मिक आंगतुकों की रुचि के अनुसार पेड़-पौधों और यहां तक की खरपतवार की पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्ता भी बताते हैं, ताकि लोगों में ईको सेंसेटिविटी का विकास हो। •

गुलाबी शहर का तेंदुआ जंगल

झालाना

सुमित जुनेजा
स्वतंत्र लेखक

जयपुर निस्संदेह भारत का एक सुंदर शहर है। दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र जयपुर तीन तरफ अरावली वनों से घिरा हुआ है। मानसून के दौरान ये हरे-भरे जंगल जीवविज्ञान विविधता की अविश्वसनीय शृंखला के घर बन जाते हैं। शहर के केंद्र से कुछ दूर एक पत्थर पर तेंदुओं के प्राकृतिक इतिहास का अवलोकन किया जा सकता है।

झालाना जयपुर क्षेत्र में स्थित है और अरावली पर्वत शृंखला से घिरा हुआ है जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है।

झालाना वन रेंज की सीमाओं के उत्तर में जवाहर नगर और आगरा रोड, पूर्व में खोनागोरियन की बस्ती और दक्षिण में जगतपुरा जैसे क्षेत्र विकसित हुए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय और मालवीय नगर इलाके पश्चिम में हैं।

1128 ई. में स्थापित जयपुर रियासत ने इस क्षेत्र पर शासन किया। जयपुर राज्य का मुख्यालय 14वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के आरंभिक भाग के बीच आमेर में था। इसके बाद महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा एक नई राजधानी, (जयपुर) का निर्माण किया गया - जो ज्यामितीय रूप से योजनाबद्ध शहर का सबसे पहला उदाहरण था।

रियासत काल में रहते हुए, एक राज्य के रूप में जयपुर वैज्ञानिक रूप से वनों के प्रबंधन के महत्व के प्रति सचेत था। एक आयरिश वनपाल श्री मैक मोइर को 1885 में राज्य के उप वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने राज्य के वनों को जैविक दबाव और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के आधार पर वर्गीकृत किया था। 1925 के बाद ही वनों का व्यावसायिक दोहन शुरू हुआ।

शहर से निकटता के कारण झालाना अच्छी तरह से संरक्षित था तथा सड़कों के साथ एक मध्य स्तरीय पहाड़ी पर स्थित ओधी से दोनों घाटियों का अवलोकन किया जा सकता था।

अपनी किताब 'हिंट्स ऑन टाइगर शूटिंग' में कर्नल केसरी सिंह बताते हैं कि कैसे उन्होंने 5 बाघ शावकों को बचाया। उसे वे बड़े सिर और मोटे पैरों के साथ हट्टे-कट्टे दिखाई दिए और उन्होंने शावकों का नाम स्नो व्हाइट के पांच बौनों के नाम पर रखा। उनमें से दो 'ग्रंपी' और 'हैप्पी' बच गए और उन्हें जयपुर चिड़ियाघर को सौंप दिया गया।

1950 के दशक में भी झालाना के जंगलों से बाघों की खबरें आम थीं। राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर से सटे लक्ष्मी मंदिर के पास एक बाघिन ने शावकों के साथ पीछा किया। झालाना आने वाले पर्यटक बाघ को याद करते हैं जो इस क्षेत्र में अक्सर देखा जाता था। 1960 के दशक तक आमेर घाटी और गलता में और 1962 में रामगढ़ में एक बाघिन और शावक के रिकॉर्ड सामने आए।

1962 में झालाना को राजस्थान वन के अंतर्गत एक आरक्षित वन घोषित किया गया

स्थानीय निवासी अक्सर झालाना आते हैं और तेंदुओं का दिखना आम बात हैं। वन विभाग ने इसके संबंध में नियम तय कर पर्यटकों के लिए व्यवस्थित वन्यजीव सफ़ारी शुरू की। आज, ये सफ़ारियां जयपुर के पर्यटकों के लिए आकर्षण हैं।

राज्य सरकार ने चारदीवारी के निर्माण, जल प्रवाह प्रबंधन, जल छिद्रों और पगडंडियों के निर्माण आदि द्वारा क्षेत्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण निवेश किया है।

इस देश के अधिकांश संरक्षित क्षेत्रों में, तेंदुओं को उनके शानदार छलावरण, अंतर्निहित शर्मीलेपन और इस तथ्य के कारण देखना मुश्किल है कि कई स्थानों पर उन्हें बाघ के साथ पारिस्थितिक रूप से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है।

हालांकि , सुंदरता, अनुग्रह और गति की तरलता के आधार पर,तेंदुआ वास्तव में बिल्ली प्रजाति का राजकुमार' है। यह तेंदुए की अनुकूलनशीलता है जिसने इस जानवर को झाड़ियों से लेकर वर्षावनों तक कई प्रकार के आवासों में बसने की अनुमति दी है।

राजस्थान वन विभाग द्वारा जयपुर में अरावली पर्वत मालाओं में दो लेपर्ड सफारी संचालित हैं जिनमें एक झालाना लेपर्ड सफारी व दूसरी आमागढ़ लेपर्ड सफारी है। •

अमृता देवी स्मृति पुरस्कार

वन और वन्य जीव संरक्षण में बेहतरी के लिए सम्मान

■ सपना शाह
जनसंपर्क अधिकारी

चिलचिलाती धूप और मीलों फैली रेत के बीच यदि किसी पेड़ की छांव मिल जाए तो सुकून मिलता है। हवा को शुद्ध करना हो या फल खाने हों या फिर पेड़ की छांव में बहती शीतल बयार में नींद लेनी हो, ऐसा लगता है मानो वृक्ष हमारे जीवनदाता हैं। ऐसे ही किसी पेड़ की छांव को बचाने के प्रयासों, पौधरोपण या वन्यजीवों की सुरक्षा करने पर यदि पुरस्कार मिल जाए तो सोने पर सुहागा।

ऐसा ही बेहतरीन प्रयास प्रदेश की संवेदनशील राज्य सरकार ने अमृता देवी स्मृति पुरस्कार के माध्यम से किया है। वृक्षारोपण, वन सुरक्षा एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था को अमृता देवी स्मृति पुरस्कार देने की योजना वन विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। वीर नारी श्रीमती अमृता देवी के नाम पर इस योजना का नामकरण किया गया है। वृक्षों को बचाने के लिए उनके बलिदान की कहानी युगों- युगों तक याद की जाएगी।

मरु प्रदेश जहां चारों ओर फैले मरुस्थल के बीच यदि यह कहा जाए कि लगभग 363 लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पेड़ों को कटने से बचाया तो यह असंभव प्रतीत होता है। लेकिन ऐसी ही एक ऐतिहासिक घटना आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व घटित हुई। विश्व के इतिहास में वृक्षों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने की घटना राजस्थान में ही घटी है। इस प्रकार का अविस्मरणीय बलिदान सन् 1730 में जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में हुआ, जहां सैकड़ों लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया।

खेजड़ली जोधपुर से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर बसा छोटा सा गांव है जिसमें खेजड़ी के पेड़ काफी तादाद में पाए जाते थे। इस गांव में अधिकतर आबादी बिश्नोइयों की है जिनके पंथ में हरे वृक्ष काटना पाप है। उनकी धारणा है कि "माथा कटे रूंख बचे तो भी सस्ता जाण"। तत्कालीन जोधपुर रियासत ने जोधपुर किले के निर्माण के लिए चूना पकाने के लिए खेजड़ली गांव से पेड़ काटकर लाने के आदेश दिए। जब रियासत के कर्मचारी पेड़ काटने खेजड़ी पहुंचे तो वहां बिश्नोइयों ने इसका सामूहिक विरोध किया। पेड़ काटने वालों ने तब यह बात वहां के दीवान को बताई तो उसने जबरन पेड़ काटने का आदेश दिया। इस आदेश की पालना में जब पेड़ काटने वाले खेजड़ली पहुंचे तो सबसे पहले उस गांव की वीर प्रसूता श्रीमती अमृता देवी ने अपना सिर कटा कर वृक्षों को काटने का विरोध किया। उनका अनुसरण उनकी तीन पुत्रियों ने किया और इस प्रकार 363 नर-नारियां वृक्षों की रक्षा के लिए शहीद हो गए। उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। रियासत ने क्षमा याचना करते हुए विश्नोई क्षेत्रों में वृक्ष काटने पर कठोर पाबंदी लगा दी।

भारतीय इतिहास की इस गौरवपूर्ण घटना को चिर स्मरणीय बनाने के लिए इस बलिदान की प्रणेता श्रीमती अमृता देवी की स्मृति में प्रदेश में वनों एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था के लिए अमृता देवी पुरस्कार देने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार उस वीर नारी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। इससे वन एवं वन्य जीव सुरक्षा

के क्षेत्र में लोगों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने से उनमें वन एवं वन्य जीव सुरक्षा की भावना और अधिक प्रबल करने में मदद मिलेगी।

पुरस्कारों की श्रेणियां

राज्य में वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए अनेक व्यक्तियों, वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों, पंचायतों तथा ग्राम स्तरीय संस्थाओं द्वारा प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है। इनमें से अधिकतर व्यक्ति या संस्थाएं राज्य के दूरदराज अवस्थित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, इसलिए इनके योगदान प्रायः अनदेखे या अप्रशंसित रह जाते हैं। इनके कार्यों को मान्यता प्रदान करने एवं सुरक्षा, वन विकास तथा वन्य जीव संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने के लिए राज्य स्तर पर अमृता देवी पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं।

प्रथम पुरस्कार के रूप में वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति, पंचायत या ग्राम स्तरीय संस्थाओं को एक लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है। द्वितीय पुरस्कार में वन विकास, संरक्षण एवं वन सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को 50 हजार रुपए एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है। इसी प्रकार तृतीय पुरस्कार में वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को 50 हजार रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के मापदंड

अमृता देवी स्मृति पुरस्कार प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के कुछ मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं। ऐसी संस्था जिसने अपनी या पंचायत भूमि पर उगे हुए प्राकृतिक वनों को कम से कम 3 वर्षों तक अपने स्वयं के प्रयास से कटिबद्ध रूप से सुरक्षा की हो अपनी अथवा सार्वजनिक भूमि पर 20 हजार या इससे अधिक वृक्ष लगाए हों और उन्हें कम से कम 3 वर्षों तक पनपाया हो और उनकी सुरक्षा की हो इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। ऐसी संस्था जिसने वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा तथा वन्य जीव संरक्षण स्थलों की सुरक्षा एवं विकास में कम से कम 3 वर्ष तक उत्कृष्ट कार्य किया हो इस पुरस्कार के पात्र होते हैं।

इसी प्रकार कोई भी कृषक या व्यक्ति जिसने अपनी या सार्वजनिक भूमि पर 5 हजार या इससे अधिक पौधों को रोपित कर उन्हें कम से कम 3 वर्ष तक विकसित किया हो, इस पुरस्कार के पात्र है। वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण में असाधारण भूमिका जैसे वनों को अग्नि, कटाव, चोरी से बचाने एवं उनकी रोकथाम स्वयं करने अथवा वन अधिकारियों को सहयोग प्रदान करने एवं स्वयं के स्तर पर वन विकास करने वाले व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए आवेदन करते हैं।

वनों के साथ वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण भी महत्वपूर्ण है। वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा में असाधारण कार्य जैसे वन्यजीवों को शिकारियों से बचाना, घायल जीवों को समय पर राहत पहुंचा कर उनका जीवन बचाना, वन्यजीव क्षेत्रों में घटित वन अपराध, अग्नि आदि की रोकथाम में किए गए उत्कृष्ट प्रयत्न एवं वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र विकास में सहयोग करने वाले व्यक्ति भी यह पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं।

ऐसे ले सकते हैं प्रतिस्पर्धा में भाग

प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा इच्छुक लोगों या संस्थाओं से पूरे विवरण के साथ प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रतिस्पर्धा के लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्था निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र निर्धारित समय तक उस क्षेत्र के उप वन संरक्षक को जमा करवा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वन सुरक्षा का कार्य किया है तथा जो स्थानीय स्टाफ की जानकारी में है उनके आवेदन पत्र निर्धारित तिथि से पूर्व, पूर्ण विवरण सहित किसी वन कर्मी या स्थानीय नागरिक द्वारा भी सीधे संबंधित अधिकारी को भरकर भेजे जा सकते हैं। जिलों से प्राप्त प्रविष्टियों को जिला स्तर पर गठित समिति, राज्य स्तरीय समिति के पास भेजती है। राज्य स्तरीय समिति सर्वोत्तम व्यक्ति या संस्था का चयन कर परिणाम जारी करती है। वन विकास एवं संरक्षण, वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा की पहल में अमृता देवी स्मृति पुरस्कार राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। •

वन एवं पर्यावरण संरक्षण की परंपरा
चिपको आंदोलन की वर्तमान प्रासंगिकता

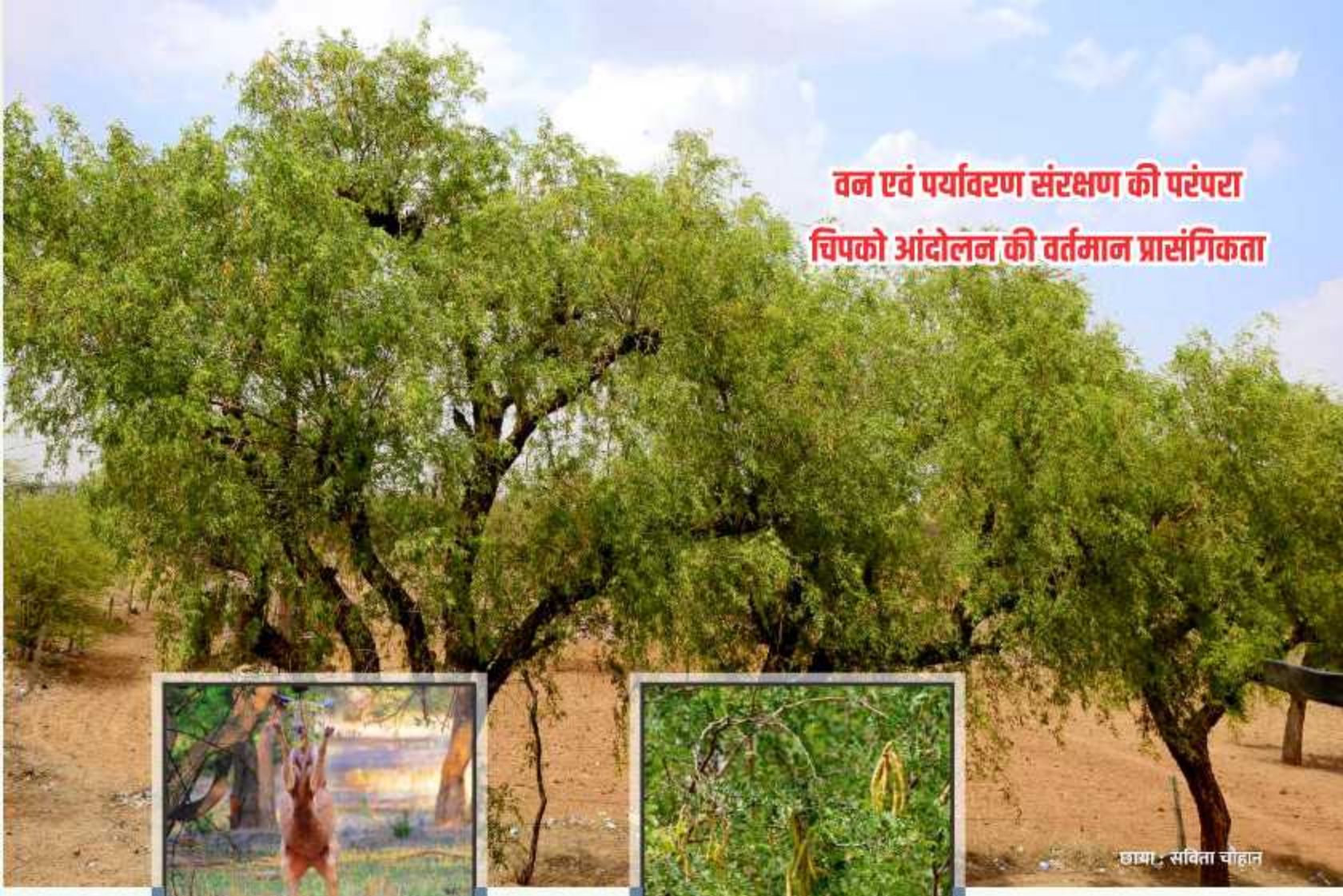

छाया : सविता चौहान

डॉ. गोरधन लाल शर्मा
राजस्थान प्रशासनिक सेवा

हमारे दर्शन और संस्कृति की परंपरा में प्रकृति को बहुत ही आदरपूर्ण और सम्मानजनक स्थान दिया गया है। मनुष्य प्रकृति का विजेता नहीं है, प्रकृति केवल उसके उपभोग के लिए रची हुई नहीं है। संपूर्ण सृष्टि पवित्र है और पर्यावरण की रक्षा सबका कर्तव्य है, ये बातें कई सदियों से मान्यता प्राप्त हैं। अनेक समुदायों में वृक्षों को बचाने की परंपरा है, जो इसी विश्व दृष्टि का परिणाम है।

लोक जीवन एवं भारतीय संस्कृति में प्रकृति की रक्षा हेतु वृक्ष पूजा वन पर्यावरण संरक्षण की परंपरा रही है। अनेक वृक्ष, जैसे नीम, पीपल, वट, शमी और तुलसी पवित्र माने जाते रहे हैं। औषधीय विशेषताओं के कारण इन सबका महत्व रहा है। अतएव इनकी सुरक्षा की जाती है और आज भी इनकी पूजा होती है। बड़े और छोटे वृक्षों के संरक्षण की कामना अनेक प्राचीन ग्रंथों में की गई है। वृक्ष संरक्षण की अभिलाषा आज तक बरकरार है। घर-घर में नीम, तुलसी का होना, इसी धारणा को पुष्ट करता है। पीपल दिन-रात ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है तथा प्रदूषित वायु को अमृततुल्य बनाता है।

चमोली के रैणी गांव में चिपको आंदोलन

चिपको आंदोलन के रूप में तहलका मचाने वाली घटना मार्च, 1974 में सीमांत जिला चमोली (उत्तराखंड) के रैणी गांव में हुई जिसमें पुरुषों की अनुपस्थिति में श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको पद्धति को अपनाकर महिलाओं ने रैणी गांव में वनों को भारी विनाश से बचाया।

मार्च, 1974 में रैणी गांव के वनों में बहुत बड़ी संख्या में सरकार ने पेड़ों को काटने के लिए छापा मारा। इस कटान की योजना के विरुद्ध श्री चंडी प्रसाद भट्ट, श्री गोविंद सिंह रावत व श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में क्षेत्र के विभिन्न गांवों के महिला मंगल दलों, छात्रों एवं कार्यकर्ताओं ने एकजुटता से वन विनाशकारी कटाव को रोकने का बीड़ा उठाया।

चिपको आंदोलन की वर्तमान प्रासंगिकता

सामाजिक आंदोलन की अवधारणा सामाजिक विकास और प्रगति की अवधारणा से भिन्न है। सामाजिक आंदोलन सामूहिक व्यवहार का स्वरूप है। इसका संचालन समाज एवं संस्कृति में नवीन परिवर्तन लाने के लिए होता है।

सामाजिक आंदोलनों का उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में आंशिक या आमूल -चूल परिवर्तन लाना हो सकता है। स्वतंत्रता से पहले और बाद में अनेक सामाजिक आंदोलनों का जन्म हुआ जिनमें चिपको आंदोलन को भी विशेष स्थान प्राप्त है। इसके पीछे मूल कारण यह है कि इस आंदोलन ने वन एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु सामाजिक जनचेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।

चिपको आंदोलन की मान्यता है कि वनों का संरक्षण और संवर्धन कानून बनाकर या प्रतिबंधात्मक आदेशों के लागू करने के साथ लोगों की जागरूकता से होता है।

वनों के महत्व को ध्यान में रखते हुए चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्न लिखित रहे हैं-

1. आर्थिक स्वावलंबन के लिए वनों का व्यापारिक दोहन बंद किया जाए।
2. प्राकृतिक संतुलन के लिए वृक्षारोपण के कार्यों को गति दी जाए।
3. चिपको आंदोलन की स्थापना के बाद चिपको आंदोलनकारियों द्वारा एक नारा दिया गया -

"क्या है जंगल के उपचार मिट्टी, पानी और बयार,

मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार"

चिपको आंदोलन की मान्यता है कि वनों के संरक्षण के लिए लोकशिक्षण को आधार बनाया जाए जिससे और अधिक व्यापक स्तर पर जनमानस को जागरूक किया जा सके। योजना की सफलता के लिए यह तथ्य भुलाया नहीं जा सकता है कि लोगों को जोड़े बिना वन संरक्षण की कल्पना ही व्यर्थ है।

चिपको आंदोलन में पेड़ों की रक्षा के लिए सुदृढ़ आधार, वन संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग, समुचित संरक्षण और वृक्षारोपण आदि के लिए कार्य किए गए। यह आंदोलन अब केवल पेड़ों से चिपकने तथा उनको बचाने का आंदोलन ही नहीं रह गया है बल्कि यह एक ऐसा आंदोलन बन गया है, जो वनों की स्थिति के प्रति जागृति पैदा करने, संपूर्ण वन प्रबंध को एक स्वरूप प्रदान करने और जंगलों एवं वनवासियों की समृद्धि के साथ ही धरती की समृद्धि के लिए समर्पित है।

पर्यावरण संरक्षण में चिपको आंदोलन द्वारा किए गए कार्यों का कभी भी विस्मरण नहीं किया जा सकता है। पेड़ न काटने देने से एक छोटी-सी सोच से शुरू हुई चिपको की यात्रा वनों की उपयोगिता, युक्तियुक्त उपयोग, वन और जन का अंतर्संबंध, वन व्यवस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के वृहत्तर संदर्भों के छोर छूने में सफल रही है और पेड़ बचाने का छोटा-सा दिखने वाला उपक्रम पर्यावरण संरक्षण का व्यापक अभियान बन गया है। साथ ही साथ यह अब यह आंदोलन लड़ने की नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण करने की सीख देने लगा है।

चिपको आंदोलन यह संदेश देता है कि वनों से हमारा गहरा रिश्ता है। वन और पर्यावरण हमारे वर्तमान और भविष्य के संरक्षक हैं। यदि वनों का अस्तित्व नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा।

मनुष्य का यह अधिकार है कि वह अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक साधनों का भरपूर उपयोग करें लेकिन इस निर्ममता के साथ नहीं कि प्राकृतिक संतुलन ही बिगड़ जाए।

चिपको आंदोलन के निरंतर प्रयास के कारण संपूर्ण देश में अब लोग यह समझने और स्वीकार करने लगे हैं कि अगर उन्हें अपनी खोई हुई खुशहाली को फिर से लौटाना है तो उसके लिए उन्हें वनरहित भूमि को पुनः हरी परत से ढंकना होगा। अतः यह आंदोलन आज राजस्थान, देश और सीमा पार अनेक देशों के लिए जनजागरण का सूत्र बना हुआ है। •

51 लाख से अधिक पेंशनरों के बैंक खातों में 1005 करोड़ रुपये हस्तांतरित

अरुण कुमार जोशी
अतिरिक्त निदेशक, जनसंपर्क

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 51 लाख 21 हजार 969 पेंशनरों के बैंक खातों में 1,005 करोड़ 41 लाख 28 हजार 750 रुपये हस्तांतरित किए। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में मई-जून माह की बढ़ी हुई पेंशन राशि (न्यूनतम 1,000 रुपये) डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भेजकर राहत पहुंचाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से सीधा संवाद किया।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी संवाद समारोह

मुख्यमंत्री श्री अशोक श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लाभार्थी जयपुर के रामलीला मैदान से वीसी के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। पेंशन लाभार्थियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में की गई बढ़ोतरी एवं इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि करने के संवेदनशील निर्णय पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक – 2023 पारित

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक – 2023 से प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को और मजबूती मिलेगी। इससे आमजन को राहत मिलेगी और गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा भूखंड आवंटन में की जाने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। 19 जुलाई को विधानसभा ने राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक – 2023 विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। कुछ गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आमजन को अनधिकृत पट्टे जारी किए जाते हैं। इससे क्षेत्र के सुनियोजित विकास में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम-2001 में संशोधन अपेक्षित था।

नए प्रावधानों के अंतर्गत अब रजिस्ट्रार बिना न्यायालय की अनुमति के सोसाइटी के अभिलेखों एवं संपत्ति की तलाशी ले सकेंगे तथा इनका अधिग्रहण कर सकेंगे। इससे न्यायालय में लगने वाले अतिरिक्त समय की बचत होगी और आमजन को जल्दी न्याय सुलभ हो सकेगा। विधेयक के माध्यम से अधिनियम की धारा-63 की उपधारा 3 को भी हटाया जाएगा।

राजस्थान विधियां निरसन विधेयक -2023 पारित

राज्य सरकार जन सामान्य के प्रति राज्य की विधिक प्रणाली को अधिक सुगम बनाने तथा उसमें सुधार करने लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से राजस्थान विधियां निरसन विधेयक -2023 लाया गया जिसके माध्यम से अप्रचलित एवं अनावश्यक 133 अधिनियमों को निरसित किया गया है। 19 जुलाई को विधानसभा में राजस्थान विधियां निरसन विधेयक - 2023 पर चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। अप्रचलित एवं अनावश्यक कानूनों के निरसन की एक सतत प्रक्रिया रही है। इससे पूर्व भी चार बार इसी तरह की प्रक्रिया द्वारा कई कानूनों को निरसित किया जा चुका है। निरसित होने वाले अधिनियमों से मूल एक्ट की भावना प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि जिस उद्देश्य से ये अधिनियम या संशोधन लाये गये थे वे पूरे हो चुके हैं।

राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक – 2023 पारित

18 जुलाई को विधानसभा में राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक – 2023 पर चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक में अपराधियों द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के साथ ही विशेष न्यायालयों की स्थापना एवं विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करने के प्रावधान किए गए हैं, ताकि मुकदमों का शीघ्र निस्तारण हो सके। इसमें अपराधियों की जमानत एवं अग्रिम जमानत नहीं होने के भी प्रावधान किये गए हैं।

राज्य में अपराध की प्रवृत्तियों के अध्ययन से यह प्रकट हुआ है कि पिछले दशक में राज्य में अपराध के पैटर्न में बदलाव आया है। आपराधिक गिरोहों ने शूटर, मुखबिर, गुप्त सूचना देने वाले और हथियार आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर संगठित नेटवर्क स्थापित कर लिए हैं। ये संगठित गिरोह मुख्य रूप से कॉन्ट्रेक्ट किलिंग, व्यवसायियों को धमकी देकर फिरौती मांगने, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे संगीन अपराधों में लिप्त हैं। ये गिरोह कानून और प्रक्रिया के सुधारात्मक और पुनर्वास संबंधी पहलुओं का लाभ उठाते हुए अपराध करने के लिए अभिरक्षा से रिहा भी हो जाते हैं। कुछ समय से इन अपराधियों ने जनता में डरावनी छवि बना ली है। इसलिए यह विधेयक इन अपराधियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक कठोर कानून की पूर्ति करेगा।

इस अधिनियम की धारा-28 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को विशेष न्यायालयों के संबंध में नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। वहीं, धारा-29 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-5 के अंतर्गत राज्य सरकार विशेष प्रक्रिया के कानून बना सकती है, जिसके अंतर्गत यह विधेयक लाया गया है। इस तरह का कानून बनाने वाला राजस्थान देश का चौथा राज्य है। इससे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गुजरात में इस तरह के कानून लागू किए जा चुके हैं।

राजस्थान कारागार विधेयक – 2023 पारित

प्रदेश की जेलों में बंदियों के लिए व्यवस्था को मजबूत बनाना राज्य सरकार का ध्येय है। बंदियों के लिए सुधारात्मक उपबंध, मूलभूत मानवाधिकारों के हक, उनके कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान कारागार विधेयक – 2023 लाया गया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद सदन ने 18 जुलाई को विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। वर्तमान में राज्य में 129 वर्ष पुराना प्रशासन एवं प्रबंधन कारागार अधिनियम – 1894 एवं 63 वर्ष पुराना राजस्थान बंदी अधिनियम – 1960 प्रभावी हैं। इन अधिनियमों में समय-समय पर किए गए विभिन्न संशोधनों को एकजाई कर राजस्थान कारागार विधेयक - 2023 लाया गया है। यह विधेयक बंदियों के साथ ही जेलों में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए कार्य करेगा।

राज्य सरकार द्वारा बंदी सुधार के लिए विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं, ताकि सजा पूरी होने के बाद उन्हें रोजगार मिल सके। खुला बंदी शिविर, कौशल विकास कार्यक्रम एवं जेलों में पेट्रोल पंप खोलना इस दिशा में किए गए महत्वपूर्ण नवाचार हैं। खुले शिविर के मामले में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है। देश के लगभग 40 प्रतिशत खुले बंदी शिविर राजस्थान में हैं।

4101 सड़क विकास कार्यों का शिलान्यास

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 232 नगर निकायों में 4,101 सड़क विकास कार्यों का शिलान्यास किया। 1,528 करोड़ रुपये लागत के इन सड़क विकास कार्यों से राज्य में 2642 कि.मी. लंबाई की सड़कों का निर्माण और विकास होगा। किसी भी प्रदेश की प्रगति में मजबूत सड़क तंत्र

का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी भावना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा सड़कों के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण कार्य करा रही है। इनमें वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 250 से अधिक जनसंख्या वाले ट्राइबल व डेजर्ट क्षेत्रों तथा 350 से अधिक जनसंख्या वाले अन्य क्षेत्रों को भी सड़कों से जोड़ा जा रहा है। राजस्थान सड़क तंत्र में आगे बढ़कर देश का मॉडल स्टेट बन रहा है। राज्य में सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, कृषि, पानी, बिजली तथा उद्योग सहित हर क्षेत्र का चहुंमुखी विकास हो रहा है। राज्य सरकार वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के विजन पर प्रतिबद्ध है। सड़क निर्माण के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाएं रोकने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के 1,548 ब्लैक स्पॉट को चिह्नित कर 1,365 को दुरुस्त कर दिया गया है। विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण के साथ ही अब बनाने वाली कंपनी की जिम्मेदारी भी 5 साल कर दी गई है। वहीं, जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

प्रदेश में 50 पक्षी घरों का होगा निर्माण

प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए 50 पक्षीघर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इन पक्षीघरों के निर्माण के लिए 43.50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। ये पक्षीघर 33 लवकुश वाटिकाओं तथा 17 अन्य स्थानों पर बनाए जाएंगे। उदयपुर के गुलाब बाग के पक्षीघर की तर्ज पर ये पक्षीघर बनेंगे। पक्षीघरों के निर्माण, पक्षियों के लिए भोजन एवं विदेशी पक्षियों के क्रय हेतु प्रति पक्षीघर 87 लाख रुपये का व्यय होगा। इस प्रकार कुल 43.50 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसी राशि में से एक-एक लाख रुपए से पक्षी घरों में कोकटियल (ऑस्ट्रेलियन बर्ड), लव बर्ड तोता, बजरिगर (बुग्गी तोता), गिनी फाउल (चकोर मुर्गा) आदि पक्षी पेट शॉप्स से खरीदे जाएंगे। इस मंजूरी से प्रदेश में पक्षियों को संरक्षण मिलने के साथ ही बीमार, असहाय एवं घायल पक्षियों का उपचार संरक्षण एवं संवर्द्धन किया जा सकेगा।

5 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक आयोजित होंगे शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेल

राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 5 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे। पूर्व में यह तिथि 10 जुलाई 2023 निर्धारित थी। इनमें कबड्डी, टेनिस-बॉल क्रिकेट, बास्केटबॉल, रस्साकशी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, शूटिंग बॉल, एथलेटिक्स आदि खेल सम्मिलित किए गए हैं तथा इसमें कुल पंजीकृत खिलाड़ियों की संख्या लगभग 56 लाख है।

प्रदेश में खुलेंगे 5 लोक अभियोजक कार्यालय

प्रदेश के जायल (नागौर), रायसिंह नगर (श्रीगंगानगर), फागी (जयपुर) एवं खेतड़ी (झुंझुनूं) में अपर लोक अभियोजक कार्यालय तथा जोधपुर में विशिष्ट लोक अभियोजक (एनडीपीएस प्रकरण) कार्यालय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। श्री गहलोत के इस निर्णय से न्यायिक एवं विधिक कार्यों का संचालन सुचारू रूप से हो सकेगा। साथ ही, न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी हो सकेगी।

प्रदेश में 1,035 पटवार मंडलों को स्वीकृति

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 1,035 नए पटवार मंडलों के सृजन की मंजूरी दी है। श्री गहलोत के इस निर्णय से आमजन को राजस्व, प्रशासनिक एवं सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों में सुगमता होगी। प्रस्ताव के अनुसार, अजमेर में 21, अलवर में 18, बांसवाड़ा में 12, बांरा, चूरू, धौलपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर में 15-15, बाड़मेर में 11, भरतपुर में 1, भीलवाड़ा में 63, बीकानेर में 128, बूंदी में 28, चित्तौड़गढ़ में 10, हनुमानगढ़ में 58, जयपुर में 35, जैसलमेर में 20, जालोर में 66, झालावाड़ में 14, झुंझुनूं में 18, जोधपुर में 51, करौली में 27, कोटा में 16, नागौर में 70, पाली में 20, प्रतापगढ़ में 26, राजसमंद में 17, श्रीगंगानगर में 75, सीकर में 30, सिरोही में 14, टोंक में 34 तथा उदयपुर में 77 पटवार मंडलों का सृजन होगा।

गृह रक्षा स्वयंसेवकों की अनुबंध अवधि 15 वर्ष हुई

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान गृह रक्षा के स्वयंसेवकों को उत्तम सुविधाएं देने तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु समिति गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही, राजस्थान गृह रक्षा स्वयंसेवकों की अनुबंध अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष किए जाने की स्वीकृति भी दी है। प्रस्ताव के अनुसार यह समिति गृह रक्षा के निदेशालय स्तर पर गठित की जाएगी। गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। महानिदेशक एवं महासमादेष्टा (कमांडेंट जनरल), गृह रक्षा तथा महानिरीक्षक पुलिस गृह रक्षा इस समिति के सदस्य होंगे। गृह विभाग के शासन सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

यह समिति गृह रक्षा स्वयंसेवकों का 12 माह नियोजन किए जाने, मानदेय पुलिस आरक्षी के समान दिए जाने, महंगाई भत्ता व ईएसआई/पीएफ सुविधा दिए जाने तथा गृह रक्षा स्वयंसेवकों को समय-समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निवारण संबंधी कार्य करेगी। साथ ही, अनुबंध अवधि बढ़ाए जाने से अब नवीनीकरण अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष हो जाएगी।

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक-2023 पारित

प्रदेश के सभी ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को एक वर्ष में 125 दिवस का रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला को प्रतिमाह न्यूनतम एक हजार रुपए पेंशन की गारंटी के लिए महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना शुरू होगी। इसके लिए राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक-2023 लाया गई। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक-2023 को सदन ने 21 जुलाई को पारित कर दिया। कानून बनाकर इस तरह की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।इस अधिनियम के लागू होने पर प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने के बाद 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्राप्त हो सकेगा। वहीं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी परिवारों को भी 125 दिवस का रोजगार मिलने की गारंटी होगी। राज्य में वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला को प्रतिमाह एक हजार रुपये न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। साथ ही, इसमें 15 प्रतिशत स्वत: वृद्धि का प्रावधान किया गया है, जो जुलाई में 5 प्रतिशत एवं माह जनवरी में 10 प्रतिशत की दर से होगी। इस वृद्धि की आधार राशि 1000 रुपये होगी। कानून बन जाने के बाद उपरोक्त प्रावधान जनता को अधिकार के रूप में प्राप्त हो जाएंगे।

विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना से 1 लाख युवाओं को मिलेगा संबल

राज्य सरकार प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए निरंतर अहम फैसले ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस योजना में विभिन्न श्रेणियों के 1 लाख लोगों को स्वरोजगार के लिए आवश्यक उपकरण, किट, सिलाई मशीन आदि खरीदने के लिए 5-5 हजार रुपये की सहायता मिलेगी। इनमें राजस्थान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड, राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू कल्याण बोर्ड, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के माध्यम से संचालित हस्तशिल्प योजना, राजीविका/एनयूएलएम-महिलाएं तथा श्रम विभाग-कामगार द्वारा चिन्हित दस्तकार शामिल होंगे।

प्रदेश से बाहर अंग प्रत्यारोपण होने पर भी मिलेगा पुनर्भरण

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदेश के बाहर किसी भी अस्पताल में निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण कराया जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में गाइडलाइन को स्वीकृति दी है। गाइडलाइन के अनुसार, प्रदेश के बाहर अंग प्रत्यारोपण एवं कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए पुनर्भरण किया जाएगा। अंग प्रत्यारोपण की अनुशंसा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में गठित ट्रांसप्लांट इवेल्यूएशन कमेटी करेगी। अनुशंसा जारी किए जाने के बाद अंग प्रत्यारोपण के पैकेज का लाभ मरीज को प्रदेश के बाहर मिल सकेगा। इसमें मरीज एवं एक सहायक को राज्य से बाहर उपचार हेतु आने-जाने के लिए 1 लाख रुपये तक की हवाई यात्रा के व्यय का पुनर्भरण भी होगा। इसके अतिरिक्त सक्षम स्तर की अनुमति से विशेष परिस्थितियों में पैकेज सीमा की 50 प्रतिशत तक की अग्रिम राशि भी मरीज को मिल सकेगी। वर्तमान में योजना के तहत प्रदेश के एंपेनल्ड अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण के 37 पैकेज तथा कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए 5 अतिरिक्त पैकेज लागू हैं।

चित्तौड़गढ़ में सत्यव्रत रावत चूंडा का बनेगा पेनोरमा

चित्तौड़गढ़ जिले में सत्यव्रत रावत चूंडा पेनोरमा का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 4 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस पेनोरमा के माध्यम से रावत चूंडा के महान् कृतित्व एवं व्यक्तित्व को दर्शाया जाएगा, जिससे लोगों को उनके अविस्मरणीय बलिदान, त्याग, साहस एवं स्वाभिमान की जानकारी मिलेगी। यह पेनोरमा आमजन तथा भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत साबित होगा। उल्लेखनीय है कि रावत चूंडा मेवाड़ के महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे। पिता के आदेश को मानकर अपनी वरिष्ठता, राजगद्दी और यहां तक कि राज्य की सीमाओं का भी त्याग करने वाले रावत चूंडा 'कलयुग के भीष्म पितामह' के नाम से प्रसिद्ध हुए। •

कुदरत का नायाब कारीगर बया

सम्पत राम चांदोलिया
उपनिदेशक, जनसंपर्क

हल्के पीले रंग का बुनकर प्रजाति का नन्हा सा पक्षी बया (वीवर फ़िंचेंज) , घास के छोटे-छोटे तिनकों और पत्तियों को बुनकर लालटेन की तरह लटकते बेहद ही खूबसूरत घोंसले का निर्माण करता है।

इसे बुनकर पक्षी और टेलर बर्ड भी कहा जाता है।अपनी कुशलता के कारण इन्हें पक्षियों का इंजीनियर कहा जाता है। बया प्रजाति के पक्षी पूरे भारतीय उपमहादीप और दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को मिलते हैं।

बया प्रजाति के पक्षी अधिकतर अपना घोंसला नहर,नदी और नालों के किनारों के आसपास पाई जाने वाली कंटीली झाड़ियों और पेड़ों में तैयार करते हैं। इन झाड़ियों में एक साथ कई उल्टे लटकते सुंदर घोंसले देखने को मिलते हैं। इनके दरवाजे नीचे की तरफ होते हैं। कई घोंसलों में दो कक्ष भी होते हैं।

बया अपना घोंसला इस तरह से तैयार करती है जिससे कि वह अपने अंडों और बच्चों को शत्रुओं, परभक्षियों और मौसमी प्रभावों से सुरक्षित रख सके। घोंसलों में तिनकों की एक महीन परत सुरक्षा के लिए बया तैयार करती है।

बया पक्षी को अपना घोंसला तैयार करने में लगभग 28 दिन का समय लगता है। बया पक्षी द्वारा घोंसला छोड़ने के पश्चात अन्य पक्षियों द्वारा इनके घोंसलों को उपयोग में ले लिया जाता है।

यह एक सामाजिक परिंदा है जो गौरैया और इन्सान की बस्तियों की तरह अपने घरों का निर्माण बड़ी ही कुशलता से करता है। इनके दीदार खेत-खलिहानों और नदी-नालों के पास आसानी से हो जाते हैं। •

वन्यजीवों व वनक्षेत्र की निगरानी में सूचना प्रौद्योगिकी

लक्ष्मण पारंगी
स्वतंत्र पत्रकार

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु आई.टी. आधारित सिक्युरिटी सिस्टम पाली जिले के जवाई बांध लेपर्ड कंजरवेशन रिजर्व में लागू किये जाने के तहत जवाई लेपर्ड कंजरवेशन रिजर्व के सम्पूर्ण क्षेत्र में जंगली जीवों व वन क्षेत्र में आठ स्वीकृत कैमरा टॉवरों में फोरेस्ट चौकी बलवना, पेरवा पहाड़ी, सेणा पहाड़ी, कोठार, हिरोला, लुन्दाडा की पहाड़ी, जगत बावडी वेलार -1 व काम्बेश्वर महादेव मंदिर वेलार -2 में ऑठ 40 मीटर ऊँचे टॉवर लगाने की स्वीकृति मिली। कैमरा टॉवरों के लगाने की जगहों पर फाइबर केबल लाइन बिछाई जा चुकी है। जवाई बांध क्षेत्र में वन एवं वन्यजीवों की निगरानी में नियन्त्रण कक्ष से जंगल में लगाये गये चार कैमरा टॉवरों के 22 हाई- रिजोल्यूशन कैमरे जिसमें कई किमी जूम करने की क्षमता के साथ नाईट विजन के रूप में थर्मल ईमेज व ऑप्टिकल कैमरों की सुविधा के साथ पी.टी.जेड, डोम व बूलेट कैमरे भी जरूरत के हिसाब से लगाये है।

इनमें जवाई डेम स्थित बलवना की पहाड़ी - जवाई, कोठार - लिलोडा पहाडी, काम्बेश्वर माद -मोतीमहाराज की धूणी व जगतबावड़ी वेलार के जंगली क्षेत्र में ये कैमरे रात-दिन कार्यरत हैं। जवाई बांध क्षेत्र में स्थित नियन्त्रण कक्ष में जंगल में लगाये चारों कैमरा टॉवरों के 22 कैमरे जंगल की जीवंत तस्वीरे भेजते रहते है। नियन्त्रण कक्ष में कार्यरत ऑपरेटर, सहायकों, वन विभाग के अधिकारियों व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्मिकों द्वारा निगरानी की जाती है। समय-समय पर जिले के उप वन संरक्षक द्वारा इसका फीडबेक भी लिया जाता है।

इन कैमरों से नियन्त्रण कक्ष में बडे स्क्रीन वाले मॉनिटर पर एक साथ जंगल में स्थापित सभी 22 कैमरों की जीवंत तस्वीरों पर ऑपरेटरों की नजर रहती है। संदिग्ध स्थिति दिखने पर वन विभाग के कार्मिक मौके पर पहुंच कर कार्यवाही को अंजाम देते हैं। ये कैमरे चौबीसौ घंटे सातों दिन लगातार कार्य करते हैं।

इन कैमरों को स्थापित करने जंगल में लगाये गये टॉवरों से जवाई बांध स्थित नियन्त्रण कक्ष तक भूमिगत ऑप्टीकल फाइबर केबल सैकड़ों किमी बिछाई गई। विभाग द्वारा पूर्व में चिन्हित किये गये बाली तहसील के पेरवा में करीब 13 किमी व सेणा में 16 किमी लम्बी फाइबर केबल टॉवर स्थापित करने की जगह तक बिछाई जा चुकी है। यहां भी कैमरा टॉवर लगेंगे।

जवाई बांध स्थित नियन्त्रण कक्ष में लगातार निगरानी हेतु 4 कर्मचारी तैनात हैं। जंगली इलाकों में फिलहाल चार टॉवर कार्यरत हैं इससे वन्यजीव सुरक्षा में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका साबित हुई। राज्य सरकार व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के इस महत्वपूर्ण कदम से जवाई लेपर्ड कंजरवेशन रिजर्व क्षेत्र में वन व वन्यजीवों में अवांछित दखल रोकने में मददगार है।

जवाई के साथ रणथंभौर में 12 टॉवर पर 62 कैमरे, सरिस्का में 16 टॉवरों पर 82 कैमरे, मुकंदरा में 16 टॉवरों पर 82 कैमरे व झालाना में 8 टॉवरों पर 42 कैमरे वन्यजीव सुरक्षा व निगरानी में लगाये जा रहे हैं। •

पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास

■ धर्मिता चौधरी
जनसंपर्क अधिकारी

हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा यहां निवास करता है,इसलिए पर्यावरण के लिए हमारी जिम्मेदारी अधिक है। विश्व पर्यावरण दिवस एक वैश्विक पहल है जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण संरक्षण के महत्व को जागृत करने,जनसंचार,सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के महत्व के बारे में बताने और विकास की ओर सामर्थ्यपूर्ण प्रतिबद्धता के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस को हर साल नई थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की थीम प्लास्टिक प्रदूषण पर प्रहार (BeatPlasticPollution) प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित है।

भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को जीवन का एक प्रमुख घटक बताया गया है। वेदों में भी पर्यावरण का महत्व बताया गया है। उपनिषदों में प्रकृति को माता की तरह प्रतिष्ठित किया गया है। यजुर्वेद में भूमि की शुद्धि और वनस्पति का महत्व बताया गया है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राष्ट्र के संपूर्ण भू-भाग का एक तिहाई वन क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन धरती पर वन कम होते जा रहे हैं। इसके साथ पर्यावरण भी प्रदूषित होता जा रहा है। जब पर्यावरण शुद्ध होगा तभी हमारा जीवन रहेगा,इसलिए कहा गया है "तरू तारे ताप,लगाओ पेड़ वरना रह जाएगा संताप।"

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने भी मानवता को नुकसान पहुंचा रहे प्लास्टिक को केंद्र में रखते हुए इस वर्ष का ध्येय तय किया है। दरअसल प्लास्टिक सुगमता और सुविधाजनक जीवन का आधार बन गया है और इससे मुक्ति के मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधा है। प्लास्टिक शरीर पर सदी का सबसे बड़ा आक्रमण कर रहा है। 21 मई से लेकर 30 मई तक चली 76वीं स्वास्थ्य सभा (Health Assembly) में यह गंभीर मुद्दा बना कि प्लास्टिक से फैल रहा प्रदूषण स्वास्थ्य पर किस प्रकार सीधा असर डाल रहा है। एक शोध में सामने आया है कि एक व्यक्ति 5 ग्राम प्लास्टिक हर हफ्ते में किसी न किसी कारण से अपनी आंतों को सौंप देता है। यह एक बड़ा मुद्दा है जिस पर निरंतर शोध की आवश्यकता है। अभी तक शोध में सामने आया है कि माइक्रोप्लास्टिक के कण अदृश्य ढंग से हर तरफ हमला कर रहे हैं।

पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए बढ़ाएं कदम

घरों से निकलने वाले कचरे को कंपोस्ट में बदलने का प्रयास करना होगा क्योंकि कंपोस्ट खाद नाइट्रोजन,फास्फोरस और कीटनाशकों जैसे प्रदूषण को रोककर भूमि और पानी की गुणवत्ता सुधारती है। इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ेगी।

रासायनिक खेती पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रही है। भूमि से लेकर पानी तक दूषित हो रहा है। इसमें इस्तेमाल नाइट्रोजन का लगभग 2 तिहाई भाग नदियों में चला जाता है जिससे समुद्री पर्यावरण एवं नदियां भी प्रदूषित हो रही हैं। इसके विपरीत जैविक खेती इस तरह के नाइट्रोजन प्रवाह को हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जाने से रोकती है। जैविक खेती प्रदूषण को कम करती है। पानी और मिट्टी को बचाती है और इससे वनस्पति

व पशु-पक्षियों को नुकसान नहीं होता। बिजली के इस्तेमाल में छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर कुल खपत को 25 से 30 प्रतिशत कम किया जा सकता है। इसके लिए उपकरण खरीदते समय यह देखने की आवश्यकता है कि बिजली के उपयोग के बारे में इसकी रेटिंग क्या है, जैसे— एनर्जी स्टार रेटिंग वाला रेफ्रिजरेटर बिजली की खपत 9 प्रतिशत तक कम करता है। 5 स्टार एसी औसतम 3 स्टार एसी से 28 प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा बचा सकता है।

जब भी कमरे से बाहर निकलें तो लैपटॉप, टीवी, एसी जैसे उपकरण बंद करके निकलें। यह एनर्जी सेविंग का आसान तरीका है। जल संरक्षण से भूमि उपजाऊ होगी और भूजल स्तर भी बढ़ेगा। शहरी क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाना जरूरी है।

सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें क्योंकि इससे हम समुद्री जीवों की भी जान बचा सकते हैं। सरकार द्वारा 12 अगस्त, 2021 को एक अधिसूचना जारी कर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 प्रकाशित किए गए।

अधिसूचना में 1 जुलाई 2022 में प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पॉलीस्टाइरीन की सजावटी सामग्री, प्लेटे, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसी कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर आदि को प्रतिबंधित किया गया है। सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, पन बिजली, पवन ऊर्जा जैसे ग्रीन स्रोत सस्ते भी होते हैं। इन्हें अपनाना चाहिए। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों में वृद्धि हुई है। ये समुद्र में घुल रही हैं जिससे महासागर अम्लीय हो रहे हैं और इससे समुद्री जीवों को भी खतरा है।

इसके लिए आवश्यक है कि लोकल उत्पाद अपनाएं। कपड़े के थैले एवं नेपकीन अधिक से अधिक इस्तेमाल करें क्योंकि रोज हजारों पेड़ टिशू पेपर एवं डिस्पोजल बनाने में कटते हैं।

कांच का जीवन चक्र 10 लाख साल होता है। कांच को बार-बार रिसाइकल करना एवं उपयोग में लेना आसान और सुरक्षित है। इसलिए घरों में प्लास्टिक की जगह कांच का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

शिक्षा मानव जीवन के बहुमुखी विकास का एक प्रबल साधन है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के अंदर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बुद्धि एवं परिपक्वता लाना है। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्राकृतिक वातावरण का ज्ञान अति आवश्यक है। प्राकृतिक वातावरण के बारे में ज्ञानार्जन की परंपरा भारतीय संस्कृति में आरंभ से ही रही है। आज के भौतिकवादी युग में परिस्थितियां भिन्न होती जा रही हैं। एक ओर जहां विज्ञान एवं तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों में नए-नए आविष्कार हो रहे हैं, दूसरी ओर मानव परिवेश भी उसी गति से प्रभावित हो रहा है। आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों का ज्ञान शिक्षा के माध्यम से होना आवश्यक है। इसके अलावा कपड़े के थैलों का उपयोग करना भी प्लास्टिक का कम से कम उपयोग में लाने का प्रयास है। वृक्ष लगाना और उसका संरक्षण पर्यावरण शुद्धि का वह यज्ञ है जिससे भावी जीवन सुखद, स्वस्थ रह सकता है। प्रकृति और पर्यावरण की हमारी संस्कृति के संरक्षण का संकल्प, प्रकृति के आंतरिक संतुलन को क्षति पहुंचाए बिना विकास की सोच को मूर्त रूप दे सकता है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के अनुसार राज्य सरकार वन और वन्यजीव की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है।

प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीवों अभयारण्य, कंजर्वेशन रिजर्व और टाइगर प्रोजेक्ट के संरक्षण और संवर्धन के लिए अधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा ईको-टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई। साथ ही सरिस्का और मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बॉर्डर होमगार्ड लगाकर विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना की गई है। यह अनूठी पहल है।•

पालनहार से पल रहे मासूम आंखों में सपने

कॅरिअर संवार परिवार का सहारा बनना चाहते हैं नौनिहाल

■ रचना शर्मा
सहायक निदेशक, जनसंपर्क

राज्य सरकार की पालनहार योजना बालपन में ही दुष्कर परिस्थितियों से जूझने वाले मासूमों के लिए वरदान बन रही है। पिता या माता-पिता दोनों का साया उठ जाने, दिव्यांग अभिभावक या अन्य परिस्थितिवश विपरीत हालात का सामना करने वाले मासूम विपदा की घड़ी में भटक न जाएं, इनके सपने न मर जाएं, इसके लिए सरकार खुद इनकी पालनहार बनी है। सरकार के इस संबल की बदौलत आज ऐसे परिवारों के बच्चे पल-बढ़ रहे हैं। भविष्य के सुनहरे सपने उनकी आंखों में पल रहे हैं। कोई प्रशासनिक उच्चाधिकारी, डॉक्टर या इंजीनियर बन कर देश की सेवा करना चाहता है तो कोई पुलिस, शिक्षक या अन्य सेवाओं के जरिये सेवा करने का सपना संजो रहा है। पढ़-लिख कर अपने पैरों पर खड़े होकर ये बच्चे अपने परिवार का सहारा बनना चाहते हैं।

प्रदेश में पालनहार योजना में 5.91 लाख से अधिक लाभार्थी हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर राज्य स्तरीय लाभार्थी संवाद समारोह में प्रदेश के 5.91 लाख से अधिक पालनहार लाभार्थियों के बैंक खातों में 146.74 करोड़ रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरित किए। इसमें जून माह के 59.38 करोड़ रुपये 5,92,630 लाभार्थियों को और जुलाई माह के 87.36 करोड़ रुपये 5,91,730 लाभार्थियों को सहायता राशि दी।

कोटा जिले में 11 हजार 422 लाभार्थी इस योजना में लाभान्वित हो रहे हैं। हाल में आयोजित लाभार्थी उत्सव में 11 हजार 329 लाभार्थियों के खाते में 1 करोड़ 68 लाख से अधिक की राशि मौके पर ही संबंधित के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। इस राशि से ये बच्चे अपनी पढ़ाई-लिखाई संबंधी व्यय कर पाते हैं। इस तरह पालनहार योजना ने ऐसे बच्चों की पढाई-लिखाई की चिंता मिटा दी है। सुनहरे सपने उनकी आंखों में आकार लेने लगे हैं।

जिले के सकतपुरा में रहने वाले परिवार के साथ भी ऐसी अनहोनी

कोटा में आमली रोजड़ी क्षेत्र निवासी एक परिवार पर नियति ने कहर ढाया और पत्थर का काम करने वाले घर के मुखिया मजदूर की असामयिक मृत्यु हो गई। दो मासूम पुत्रों की परवरिश की खातिर मां अनीता घरों में झाड़ू—पोछे का काम करने लगी, लेकिन इससे कहां तक सहारा मिलता। किसी ने बताया तो सरकार की पालनहार योजना से जुड़ी और इससे उन्हें बड़ा संबल मिला। बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान नहीं आया। अब बड़ा बच्चा अंकित 11वीं कक्षा में है और डॉक्टर बनना चाहता है। वह छोटे भाई को भी योग्य बनाना चाहता है और मां को सहारा देना चाहता है।

हुई और असमय पिता का साया बच्चों के सिर से उठ गया, लेकिन पालनहार योजना के कारण इन बच्चों के सपने मर नहीं पाए। अपनी कक्षा में अव्वल रहने वाली इशिका सुमन नौवीं कक्षा में पढ़ती है और भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है। भाई इंजीनियर बनना चाहता है।

इन श्रेणियों में मिलता है पालनहार योजना का लाभ

अनाथ बच्चे, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे, पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, एच.आई.वी. एड्स से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे, विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चे, पेंशन प्राप्त कर रही तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता महिला के बच्चे, सिलिकोसिस पीड़ित माता-पिता के बच्चे योजना की पात्रता रखते हैं।

यह है अनुदान राशि

अनाथ श्रेणी के 0-6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1,500 रुपये प्रतिमाह और 6-18 आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए 2,500 रुपये प्रतिमाह अनुदान राशि दी जाती है। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार पालनहार योजना में अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के 0 से 6 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए 750 रुपये प्रतिमाह और 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1,500 रुपए प्रतिमाह सहायता राशि दी गई। साथ ही कपड़े, स्वेटर, जूते आदि के लिए हर वर्ष 2,000 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं (विधवा और नाता श्रेणी को छोड़कर)। इस योजना में बच्चों का आंगनबाड़ी या विद्यालय जाना अनिवार्य है।

अणतपुरा निवासी दिव्यांग दंपती रविशंकर कश्यप और पत्नी आरती के लिए पालनहार योजना ने बड़ा सहारा दिया है। दिव्यांग होने के कारण रवि छोटा—मोटा काम ही कर पाते हैं, ऐसे में अपनी दो बच्चियों की पढ़ाई—लिखाई को लेकर काफी चिंतित थे। पालनहार योजना का लाभ मिलने से दोनों बच्चियों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त राशि मिल जाती है। अब रवि और आरती दोनों बेटियों की पढ़ाई की चिंता से मुक्त हैं। वे कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई की चिंता सरकार ने मिटा दी।

रायपुरा निवासी मजदूर परिवार के दो बच्चे भी पढ़ाई कर भविष्य संवारना चाहते हैं। सातवीं कक्षा में पढ़ रही लक्ष्मी और चौथी कक्षा में पढ़ने वाला भाई रवि दोनों पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं। माता चमेली देवी को इन बच्चों से आस लगी है कि वे सबके सपने पूरे करेंगे। वह सरकार को इस योजना के लिए धन्यवाद देती है। गोविंद नगर निवासी इशिका चौहान तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी है। वह 8वीं कक्षा में पढ़ती है। पिता निजी तौर पर वाहन चलाने का कार्य करते थे। दो साल पहले मृत्यु हो गई तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मां एक निजी अस्पताल में कार्य करती हैं। मुसीबत की घड़ी में पालनहार योजना उनकी सहारा बनी और इशिका एवं चौथी कक्षा में पढ़ने वाले भाई अपनी पढ़ाई जारी रख पा रहे हैं। वे सरकार को इसके लिए धन्यवाद देती हैं। •

भरतपुर अंचल में लक्ष्मण मंदिर

गुलाब बत्रा
वरिष्ठ पत्रकार

स्वाधीनता के समय भारत विभाजन से पहले देशी रियासतों में भरतपुर रियासत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ब्रज के आंचल में अवस्थित इस धरा का कण-कण शूर-वीरता एवं पराक्रम का प्रतीक है। अपने अस्तित्व को दांव पर लगाते हुए शरणागत की रक्षा में अग्रणी यह रियासत वीर भाव की पूजक रही है। ऐतिहासिक धरोहर को समेटे इस अंचल के जनमानस की अभिवादन के रूप में राम-राम के संबोधन की विशिष्टता है। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुज लक्ष्मण के यहां अनेक मंदिर हैं। यह माना जाता है कि राम के भ्राता भरत की याद में भरतपुर नाम रखा गया। भरतपुर की पुरानी राजधानी डीग को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नया जिला बनाने की घोषणा की है। स्कंद पुराण में दीर्घपुर नाम से इसका उल्लेख मिलता है। आधुनिक युग में इसकी पहचान डीग के विख्यात जलमहलों के रूप में हुई। अनुपम वास्तुशिल्प के इन भवनों में चित्ताकर्षक विविध रंगों के फव्वारों की छटा धरती पर इंद्रधनुष का परिदृश्य उत्पन्न करती है।

डीग के लक्ष्मण मंदिर

तीन सौ साल पहले दक्षिण भारत से डीग आए रामानंद संप्रदाय के आचार्य बालानंद गोसाई की प्रेरणा से जाट रियासत के संस्थापक श्री बदन सिंह ने 1723-24 में कस्बे के मध्य लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। सवा बीघा क्षेत्र में भूतल से 40 फीट ऊंचे परकोटे पर पूर्वमुखी गर्भगृह में अयोध्या के अनुरूप बाल स्वरूप रामलला के विग्रह के दोनों ओर लक्ष्मण एवं उर्मिला के विग्रह खड़ी अवस्था में हैं। डीग के बाद भरतपुर- कुम्हेर-सिनसिनी आदि स्थानों पर बने आधा दर्जन से अधिक मंदिरों में केवल लक्ष्मण, उर्मिला के विग्रह हैं।

डीग के मंदिर के गर्भगृह पर पांच मंजिले नयनाभिराम शिखर को छूती हुई सूर्य रश्मियां इन विग्रहों के चरण स्पर्श करती दिखाई देती हैं। मंदिर से करीब 500 फीट की दूरी से श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। आज भी इस क्षेत्र के दुकानदार मंदिर की तरफ ढोक देकर अपनी दुकान खोलते हैं। रियासत काल में जलमहलों से इस मंदिर में भी फव्वारे लगाए गए थे।

सायपुरा का लक्ष्मण मंदिर

निकटवर्ती गांव सायपुरा में निर्मित मंदिर में राम, सीता एवं लक्ष्मण के अष्ट-धातु के पांच फुट लंबाई के विग्रह हैं। इस मंदिर को पूर्व राजपरिवार का गुरु स्थान माना जाता है। मुख्य लक्ष्मण मंदिर के निकट आदर्श सेकेंडरी स्कूल की गली में लगभग ढाई सौ वर्ष पहले बागड़ा ब्राह्मणों ने मंदिर बनवाया था।

व्यंकटेश और अन्य मंदिर

भरतपुर का पुराना लक्ष्मण मंदिर नागा साधुओं ने वर्ष 1815 में

बनवाया था। इसे वैंकटेश/वैंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के बाहर खुले मैदान में वर्षों तक भरतपुर की प्रसिद्ध रामलीला का मंचन होता रहा। नागा साधुओं के दल सेना के साथ युद्ध में भी भाग लेते थे। शहर के बीचों बीच नया लक्ष्मण मंदिर स्थित है। मुख्य बाजार में बने इस विशाल मंदिर के चारों ओर दुकानें बनाई गईं ताकि मंदिर व्यवस्था के लिए वित्तीय प्रबंधन बना रहे। पुराना मंदिर भी इसके पास है। नए मंदिर के दालान में भी रामलीला मंचन के कुछ दृश्य होते थे।

दाल बाजार का लक्ष्मण मंदिर

जामा मस्जिद से नए लक्ष्मण मंदिर के मध्य दाल बाजार में बने लक्ष्मण मंदिर में राम, सीता और लक्ष्मण, उर्मिला के युगल रूप में विग्रह शोभायमान है। आम बोलचाल में इसे संतोषी मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और इसके मुख्य द्वार पर पत्थर की नक्काशी बेजोड़ है। इसी प्रकार हिंदी साहित्य समिति भवन से अटलबंद रोड पर भी लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है। यह इलाका कभी यतीमखाना नाम से भी जाना जाता था।

सिनसिनी के लक्ष्मण मंदिर

भरतपुर, डीग सड़क मार्ग पर सिनसिनी ग्राम में बस स्टैंड के निकट पुराना लक्ष्मण मंदिर है। रियासत की टकसाल रही कुम्हेर के मुख्य बाजार में सुनारों की गली में बने लक्ष्मण मंदिर में युगल स्वरूप का विग्रह है। डीग का मुख्य लक्ष्मण मंदिर, कुम्हेर मंदिर, भरतपुर का नया लक्ष्मण मंदिर एवं अटलबंद रोड पर राधारमण मंदिर के निकट पुराने यतीमखाना क्षेत्र में बना लक्ष्मण मंदिर देवस्थान प्रभार के देवालय हैं। ये सभी राजस्थान राजपत्र में अधिसूचित मंदिर हैं। शेष निजी अथवा ट्रस्ट संचित मंदिर हैं।

भरतपुर जिले में लक्ष्मण मंदिरों की परंपरा एवं श्रद्धालुओं की भक्ति भावना बेमिसाल है। अन्य देवी-देवताओं के मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ ये लक्ष्मण मंदिर राम के 14 वर्ष के वनवास में अनुज लक्ष्मण की सेवा भावना के प्रतीक हैं जिनमें उर्मिला को भी सम्मान मिला है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देश पर जन-जन को मंदिर संस्कृति एवं उनकी स्थापत्य कला से रूबरू कराने के लिए देव-दर्शन पदयात्राओं का आयोजन किया गया। भरतपुर में 3 जुलाई को अटलबंद मंडी स्थित सिरकी वाले हनुमान मंदिर से आरंभ यह पदयात्रा राधारमण मंदिर, नया लक्ष्मण मंदिर, लाला जी मंदिर होती हुई लोहागढ़ दुर्ग स्थित बिहारी मंदिर पर समाप्त हुई।•

ग्रामीण पर्यटन में पहचान बना रहे बांसवाड़ा के गांव

स्वप्निल कुलश्रेष्ठ
स्वतंत्र लेखक

महात्मा गांधी के अनुसार भारत की आत्मा गांवों में बसती है। लेकिन आधुनिकता और विकास से शहरों के आकार का विस्तार हो रहा है और गांव छोटे होते जा रहे हैं। असल में जीवन का सुकून, शांति और संतुष्टि आज भी गांवों में रची- बसी है। इस बात को समझ कर संवेदनशील राज्य सरकार ने सही समय पर सही निर्णय लिए और गांवों की आत्मा को नया जीवन दिया है।

राज्य का विकास गांवों के विकास पर निर्भर है। विकास की भाग - दौड़ में एक समय ऐसा आता है जब इंसान प्रकृति और गांव की ओर लौटना चाहता है। बहुत से शहर में पले लोग भी गांवों में जमीन तलाश रहे हैं कि वहां एक अलग तरह का सुकून मिलता है।

वर्तमान समय में गांव ग्रामीण विकास और ग्रामीण पर्यटन अर्थव्यवस्था का केंद्र बनते जा रहे हैं। राजस्थान के वागड़ में स्थित बांसवाड़ा जिला इसी का जीवंत उदाहरण है। जनजाति अंचल की हरितिमा आच्छादित खूबसूरती ईश्वरीय वरदान साबित हो रही है। ईश्वर प्रदत्त प्रकृति और हरियाली के उपहार के साथ राज्य सरकार के प्रयासों से यह देशभर के प्रमुख ग्रामीण पर्यटन स्थलों में अंकित हो रहा है।

वाग्वर अंचल माही और त्रिपुरा सुंदरी की गोद में बसा बांसवाड़ा अपनी धार्मिक आस्था, ग्रामीण पर्यटन और सादगी के लिए अनूठी पहचान बनाए हुए है। बरसात के मौसम से लेकर शीतकाल तक गांवों की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भी बांसवाड़ा के जनजाति अंचल में ग्रामीण पर्यटन और विकास, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, पलायनवादी संस्कृति को रोकने के लिए गांवों को विकास की दौड़ में शामिल करने के लिए पूरे बजट में विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के नाम से विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। बजट की अनेक घोषणाओं का केंद्र गांव होने से गांवों का विकास हो रहा है और खासतौर पर बांसवाड़ा के बहुत से गांव ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में अनूठी पहचान बना रहे हैं।

"सर्वजन हिताय – सर्वजन सुखाय" के भावों के द्वारा पर्यटन उन्नयन समिति की स्थापना कर माही अरथूना महोत्सव, मैंगो फेस्टिवल, एडवेंचर गेम्स, जंगल सफारी आदि की शुरुआत की वजह से ग्रामीण पर्यटन को नया आयाम मिला है।

100 द्वीप, चाचाकोटा, कलाटिया भैरव, सवाई माता पहाड़ी, विभिन्न प्राकृतिक झरने आदि आकर्षणों के साथ गांवों में सर्व सुविधा उपलब्ध हो ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

इससे पर्यटक जब आए तो उन्हें आवास, भ्रमण, भोजन और सुरक्षा की गारंटी दी जा सके। राज्य सरकार मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, सड़क को सुचारू और मजबूत कर रही है। •

जालोर दुर्ग

जालोर दुर्ग अपनी प्राचीनता, सुदृढ़ता और शौर्य के कारण प्रसिद्ध है। अरावली के सोनगिरि पहाड़ी व सूकड़ी नदी के किनारे बना यह दुर्ग पश्चिमी राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्गों में गिना जाता है। दुर्ग में चार द्वार, बावड़ियां व जलाशय हैं। पहाड़ी के शिखर भाग में निर्मित वीरमदेव की चौकी अप्रतिम वीर की यशोगाथा को संजोए हुए है।

आलेख और छाया : रूपांक्षा चारण
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

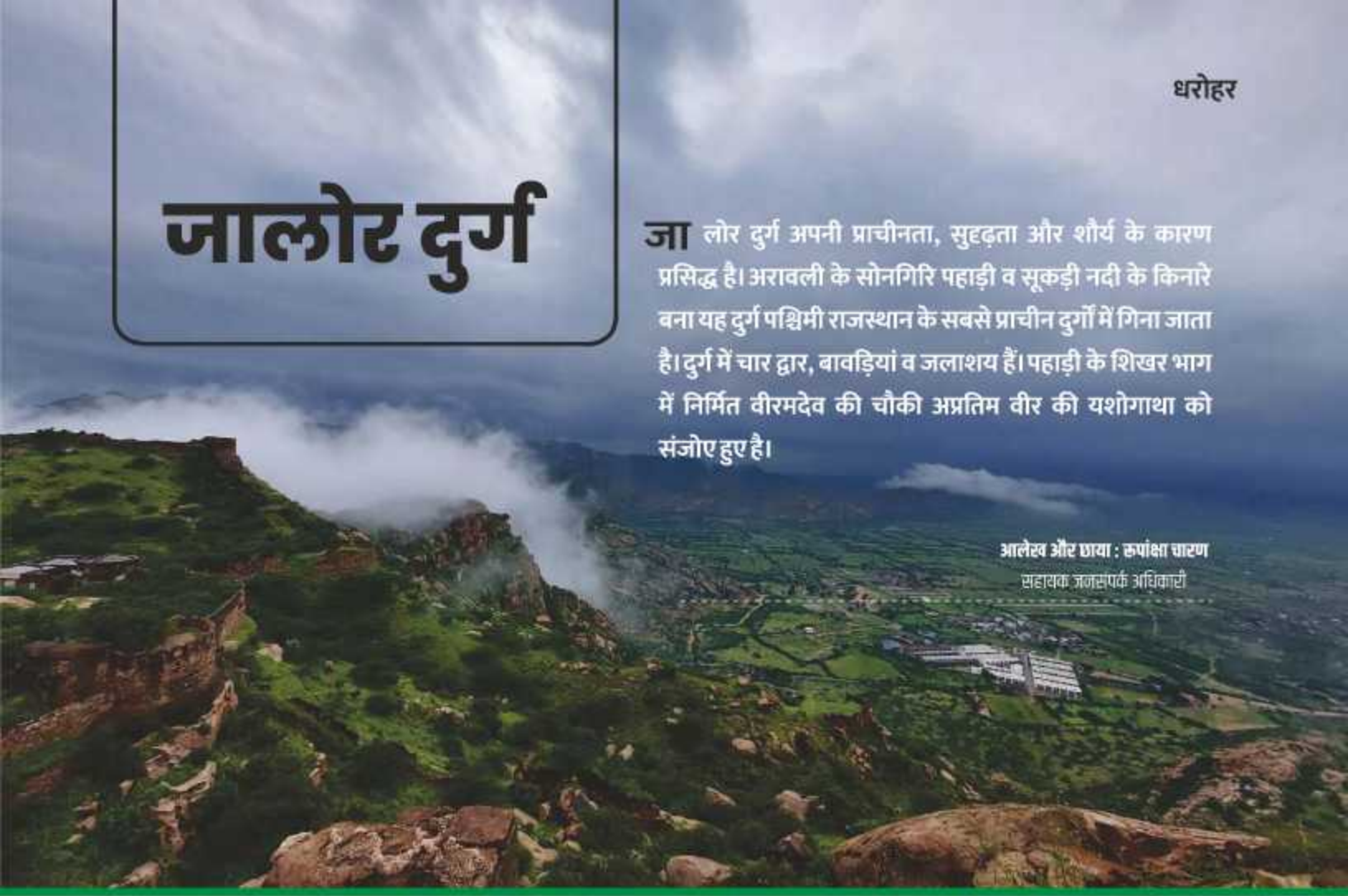

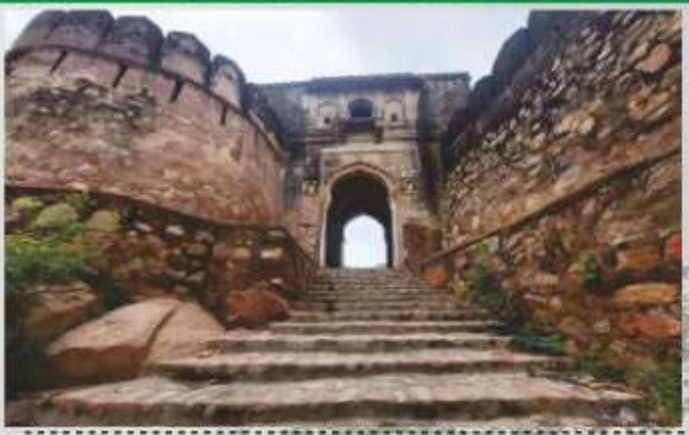

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2023-25
Registered with Registrar of Newspapers for India under R. No. 56175/1991

तस्वीर बदलाव की

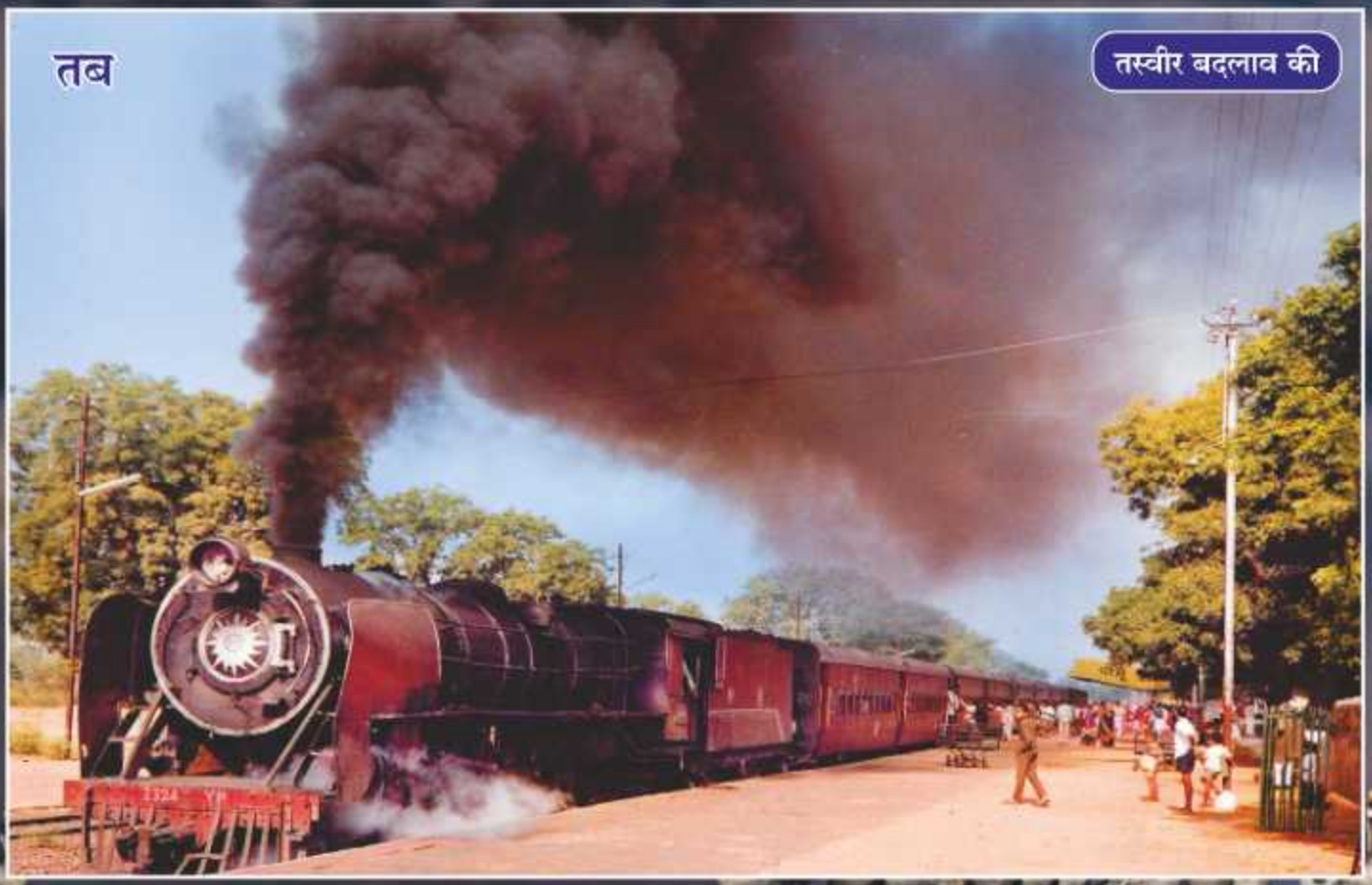

राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम और अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी
https://jankalyan.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक – सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशक, पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक – श्रीमती अलका सक्सेना, मै. कृष्णा प्रिन्टर्स, डी–14, सुदर्शनपुरा, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस'–पृष्ठ संख्या 60, लागत मूल्य 33.30 रुपये • 1,00,000 प्रतियां